राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 8 अंक 57

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, सोमवार, 5 अगस्त, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

असम में 'लव जिहाद' मामले में शीघ्र लाएंगे उम्रकैद का कानून

>> 3

वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी, बिना सत्यापन नहीं ले सकेगा जमीन

नियंत्रित हो सकती हैं बोर्ड की शक्तियां, वक्फ कानून में 40 संशोधनों के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वक्फ संपत्तियों पर विवाद व वक्फ बोर्ड के अधिकारों को नियंत्रित करने की उठ रही मांग के बीच सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों के प्रस्ताव को गत दिवस कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी जा चुकी है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा।

बताया जाता है कि रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सर्वाधिक भूमि का स्वामित्व रखने वाले वक्फ बोर्ड के अनियंत्रित अधिकारों में कटौती के लिए अधिनियम में संशोधन की तैयारी मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू कर दी थी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, शिया व बोहरा जैसे मुस्लिम समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग भी कर रहे थे। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सभी वक्फ संपत्तियों से प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यह ऐसी संस्थाओं के पास मौजूद संपत्तियों की संख्या के अनुरूप नहीं है। मूल रूप से वक्फ बोर्डों के पास पूरे देश में करीब 52 हजार संपत्तियां थीं। 2009 तक, चार लाख एकड़ जमीन वाली तीन लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थीं। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के पास आठ लाख एकड़ से अधिक में फैली हुई 8,72,292 संपत्तियां हैं।

सूत्रों के अनुसार, संप्रग सरकार ने 2013 में 1995 के मूल वक्फ अधिनियम में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया था। बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। दलील यह दी जाती है कि यह संपत्ति जरूरतमंद मुस्लिमों की भलाई के लिए है, पर देखा गया है कि कुछ प्रभावशाली लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई संपत्तियों को जबरन भी वक्फ संपत्ति घोषित करने का विवाद है। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और हस्तांतरण में बड़ा बदलाव आएगा। इससे अन्य इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड के पास जो ताकत है उसके हिसाब से होगा। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं।

कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट ने 123 विवादित संपत्तियों की जांच का आदेश दिया था पेज>>4

- इसी सत्र में संसद में संशोधन विधेयक ला सकती है सरकार
- संप्रग सरकार ने 2013 में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया था

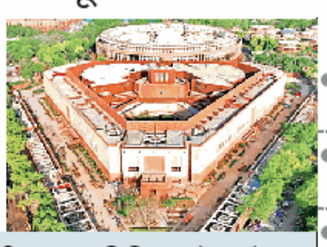

इसलिए सरकार कर रही वक्फ अधिनियम में संशोधन

एएनआइ के अनुसार, मुसलमान खुद पूछ रहे थे कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही है? बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। राज्य व केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिलाधिकारी के दफ्तर में पंजीकृत करानी होगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। राजस्व की जांच व वक्फ में पारदर्शिता करने के लिए समिति होनी चाहिए।

नए कानून से यह होगा बदलाव

- नए प्रविधानों के तहत वक्फ बोर्ड की विवादित पुरानी संपत्तियों का भी फिर से सत्यापन करना होगा
- बोर्ड की संरचना में बदलाव करते हुए इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी
- वक्फ बोर्डों को संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए जिलाधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा
- नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड व व्यक्तिगत मालिकों द्वारा दावे- प्रतिदावे किए गए हैं
- प्रस्तावित बिल के अनुसार, वक्फ बोर्डों द्वारा किए गए सभी दावों के अनिवार्य व पारदर्शी सत्यापन की जरूरत होगी
- वक्फ अधिनियम की धारा 9 व 14 में बदलाव से केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव है

जज्बे से जीता दिल, अब पदक की बारी

नई दिल्ली, जेएनएन : पेरिस ओलिंपिक के आठवें दिन भारतीय हाकी टीम ने अंत तक हार न मानने के जज्बे से दिल जीता। रविवार को क्वार्टर फाइनल में 42 मिनट तक 10 खिलाड़ियों से खेलने के बावजूद हरमनप्रीत की अगुआई वाली हाकी टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अंतिम ग्रुप मैच में 52 साल बाद ओलिंपिक में आस्ट्रेलिया को हराने वाली भारतीय टीम ने एक खिलाड़ी कम होने के बाद भी हार नहीं मानी। भारत की जीत के नायक रहे गोलकीपर पीआर श्रीजेश, जो अपना अंतिम टूर्नामेंट खेल रहे हैं। भारत ने लगातार दूसरे ओलिंपिक में सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और वह पदक से एक जीत दूर है। भारतीय हाकी टीम ने टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीता था और अब उसके पास फाइनल में पहुंचकर पदक का रंग बदलने का अवसर है।

कांस्य पदक के लिए खेलेंगे लक्ष्य: भारत के उभरते स्टार शटलर लक्ष्य सेन रविवार को सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से 20-22, 14-21 हार गए, जिसके बाद वह सोमवार को कांस्य पदक के मुकाबले में उतरेंगे। लक्ष्य का सामना मलेशिया के ली जि जिया से होगा। ओलिंपिक में अभी तक बैडमिंटन में भारत केवल तीन पदक ही जीत पाया है। इनमें सिंधू ने 2016 में रजत और 2020 में कांस्य, जबकि 2012 में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था।

संबंधित खबरें >> पेज-12

- ग्रेट ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर हाकी टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह
- अपना अंतिम टूर्नामेंट खेल रहे गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने रहे जीत के नायक

पेरिस ओलिंपिक में ब्रिटेन के खिलाफ विजयी गोल दागने के बाद राजकुमार पाल साथी खिलाड़ी सुखजीत सिंह के साथ। एपी >>

ओलिंपिक में भारत

- लवलीना बोरगोहाइ चीन की ली कियान से हारीं, मुक्केबाजी में अभियान समाप्त
- एथलेटिक्स में पुरुषों की लंबी कूद में जेस्वीन एल्ड्रिन 18वें स्थान पर रहे
- महिलाओं की 3,000 मीटर स्टीपलचेज में पारुल चौधरी 8वें नंबर पर रहीं
- महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में निशानेबाज महेश्वरी चौहान फाइनल में चूकीं
- 25 मीटर रैपिड पिस्टल स्पर्धा में विजयवीर सिद्धू नौवें व अनीश 13वें पर स्थान पर रहे

जागरण विशेष

ग्लेशियर के अध्ययन को मिलेगी नई दिशा

रुद्रकी : ग्लोबल वार्मिंग से पार पाने के लिए देश में अनेक संस्थान अध्ययन कर रहे हैं। अलग-अलग अध्ययन कर रहे ये संस्थान केंद्र की पहल पर आएंगे एक प्लेटफार्म पर। ● पेज-6

संपादकीय

विवेक देवराय

आदित्य सिन्हा

जल निकासी में असहाय शहर : यदि हमें अपने शहरों को रहने योग्य बनाना है तो शहरीकरण की योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण से जुड़े उपायों को प्राथमिकता सूची में रखना होगा। **विवेक देवराय** और **आदित्य सिन्हा** का आलेख।

लैंगिक समानता की दिशा में सही कदम : बजट में नारी उत्थान के प्रति सरकार की संवेदनशीलता तो झलकती है, मगर चुनौती क्रियान्वयन के मोर्चे पर है। **ऋतु सारस्वत** का दृष्टिकोण। ● पेज-8

विमर्श

खनिज संपदा पर अधिकार का फैसला : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्यों को खदानों तथा खनिज वाली भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। राहुल लाल का विश्लेषण।

नजूल जमीन हथियाने का खेल और बैकफुट पर भाजपा : नजूल मतलब सरकारी जमीन यूं तो देशभर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति को लेकर प्रस्तावित कानून पर इन दिनों राजनीतिक माहौल क्यों गर्म है बता रही है अजय जायसवाल की डायरी। ● पेज-9

मप्र के सागर में दीवार गिरने से मलबे में दबकर नौ बच्चों की मौत

- शिवलिंग बनाने के दौरान मंदिर परिसर से सटे मकान की 50 वर्ष पुरानी दीवार गिरी, दो बच्चे घायल भी हुए
- एक दिन पहले रीवा में दीवार गिरने से हुई थी स्कूल से छुट्टी के बाद निकलते समय चार बच्चों की मौत

मप्र के सागर जिले में रविवार को शाहपुर गांव के मंदिर परिसर से सटी कच्ची दीवार ढहने के बाद जारी बचाव कार्य। वीडियोग्रैब/प्रेट्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर

मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे दीवार गिरने से मलबे में दबकर नौ बच्चों की मौत हो गई। हादसा सागर जिले के शाहपुर में हुआ। यहां हरदौल मंदिर परिसर में बच्चे पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे। इसी दौरान मंदिर परिसर से सटे मकान की करीब 50 वर्ष पुरानी दीवार उनके ऊपर गिर गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल दो बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों की ओर से मंदिर में सावन में भागवत कथा एवं पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का आयोजन चल रहा था। रविवार को अवकाश होने से शिवलिंग बनाने के लिए बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे थे। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों भारी वर्षा हो रही है। सागर में ही 24 घंटे में 104 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है। इसके एक दिन पहले शनिवार को रीवा जिले में स्कूल के नजदीक एक मकान की दीवार गिरने से चार बच्चों की मौत हो गई थी। इस हादसे में एक बच्ची और एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा स्कूल की छुट्टी के समय हुआ, उस समय बच्चे स्कूल से निकल रहे थे।

सीएमओ और उपयंत्री निलंबित : शाहपुर हादसे को लेकर शासन ने नगर परिषद के सीएमओ और उपयंत्री को निलंबित कर दिया है, वहीं बीएमओ व एक मेडिकल अफसर को नोटिस दिया गया है। दरअसल, दीवार गिरने के बाद स्थानीय लोग जब घायल बच्चों को लेकर शाहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां कोई डाक्टर नहीं मिला। अस्पताल में केवल एक नर्स थीं।

ग्रामीणों के अनुसार वर्षा में खुले में शिवलिंग बनाने की जगह मंदिर के सामने बने सामुदायिक भवन में आयोजन की योजना थी, लेकिन भवन में खाली नहीं होने के कारण यह खुले में किया गया।

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने की आर्थिक मदद की घोषणा

शाहपुर हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने जान गंवाने वाले बच्चों के स्वजनों को दो-दो लाख रुपये और घायल बच्चों के स्वजनों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उधर, मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के स्वजनों को चार-चार लाख और घायल बच्चों के स्वजनों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने घायल बच्चों के उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश भी दिया है।

बांग्लादेश में हसीना के इस्तीफे के लिए हिंसा, 91 मरे

ढाका, प्रेट्र : पड़ोसी देश बांग्लादेश में रविवार को फिर से हिंसा भड़क उठी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन के परिणामस्वरूप हुई हिंसक झड़पों में शाम तक 91 लोग मारे जा चुके थे। मारे गए लोगों में 14 पुलिसकर्मी थे। पूरे बांग्लादेश में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, इनमें 300 पुलिसकर्मी हैं। हालात बेकाबू होते देख गृह मंत्रालय ने शाम छह बजे से पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू का एलान कर दिया है। इंटरनेट मीडिया पर भी रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों को आतंकवादी कहा है और देशवासियों से उन्हें कुचल देने का आह्वान किया है।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मसले पर रविवार सुबह भेदभाव विरोधी छात्र मोर्चा के बैनर तले राजधानी ढाका सहित देश के कई शहरों में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की एक मात्र मांग प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की थी। इस मांग के विरोध में हसीना की पार्टी अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए और दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। शाम तक ढाका सहित कई शहरों में हिंसक टकराव बढ़ता गया। सबसे ज्यादा हिंसा सिराजगंज में होने की सूचना है, वहां के इनायतपुर पुलिस थाने पर हमला कर 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। एक पुलिसकर्मी की हत्या कोमिला के इलियटगंज में हुई है। नरसिंहदी शहर में अवामी लीग के छह नेताओं और कार्यकर्ताओं की हिंसक भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। यहां पर कई लोग घायल भी हुए हैं। ढाका में चार लोगों के शव अस्पताल लाए गए हैं। फायरिंग में घायल 56 लोग इलाज के लिए ढाका मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ढाका की बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी में अज्ञात लोगों ने सैकड़ों वाहन जला दिए।

हसीना ने सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक की पेज>>11

- मरने वालों में 14 पुलिसकर्मी, सैकड़ों घायल, भारी आगजनी
- हिंसक आंदोलनकारियों से सत्तारूढ़ दल समर्थकों का टकराव
- पूरे देश में कर्फ्यू, पीएम हसीना ने उपद्रवियों को आतंकी बताया

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रविवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा शॉपिंग सेंटर में आग लगाए जाने के बाद भागते लोग। एपी

अयोध्या दुष्कर्म कांड : आरोपितों ने सुलह के लिए दिया था लालच

अयोध्या : नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में नया तथ्य प्रकाश में आया है कि आरोपितों ने धमकी देने से पहले पैसे लेकर सुलह का दबाव बनाया था। आरोपित की बेकरी पर शनिवार को बुलडोजर चलाए जाने के बाद उसकी अन्य संपत्तियों को भी चिह्नित किया जा रहा है। श्मशान भूमि पर भी उसका अवैध कब्जा पाया गया है। वहीं, भदरसा चौकी के एक अन्य सिपाही को भी लाइनहाजिर कर दिया गया। (पेज-5)

उत्तराखंड में कुदरत का कहर, सेना ने मोर्चा संभाला

नई दिल्ली : उत्तराखंड में केदारघाटी में आई आपदा के बाद बचाव व राहत कार्य में सेना भी जुट गई है। सेना ने गौरीकुंड-सोनप्रयाग हाईवे पर फंसे 25 घायल, बुजुर्ग व दिव्यांगों को ट्राली के जरिये से निकाला। सेना, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान में रविवार को 1275 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। (पेज-6)

विपक्ष कितना भी शोर करे, 2029 में भी मोदी ही पीएम होंगे : शाह

चंडीगढ़ : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष को जितना भी शोर मचाना है मचा ले, 2029 में भी नरेन्द्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। पिछले तीन चुनावों में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं, उससे अधिक सीट तो अकेले भाजपा को अब मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। (पेज-3)

दैनिक जागरण सप्तरंग
साहित्य और संगीत का
अथातो 'जाति' जिज्ञासा!
स्वरसिद्ध ठुमरी साम्राज्ञी
● पेज-13

24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी हरियाणा सरकार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र

हरियाणा की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी 24 फसलों की खरीदने की घोषणा की है। ऐसा कर उसने जहां किसानों का भरोसा जीता, वहीं विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। हरियाणा में 14 फसलें पहले से एमएसपी पर खरीदी जा रही थीं। रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए 10 और फसलें एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने इसे अपने आंदोलन की जीत बताया है।

केंद्र सरकार हर साल 24 फसलों का एमएसपी घोषित करती है। हरियाणा 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फसलों की खरीद एमएसपी पर कराने को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसान कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे। तीन कृषि कानूनों के विरोध तथा एमएसपी पर फसलों की खरीद को लेकर दिल्ली-हरियाणा की सीमा पर पूरे एक साल तक आंदोलन चला। अब किसान फिर से हरियाणा-पंजाब सीमा पर अंबाला के निकट शंभू बार्डर पर धरने पर बैठे हैं।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, उनकी सरकार किसानों के हितों को लेकर फिक्रमंद है। किसानों का पिछले आबियाने (नहरी पानी शुल्क) का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपये का बकाया माफ कर दिया गया है। साथ ही भविष्य के लिए भी आबियाना खत्म हो गया है। इससे किसानों को प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। 2023 से पहले विभिन्न जिलों में आपदा से फसलों को हुई क्षति के मुआवजे की लंबित 137 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान की घोषणा करते हुए सैनी ने कहा, अब किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तीन स्टार वाली मोटर देश भर से कहीं से भी खरीदने की अनुमति होगी।

- किसान आंदोलन के बीच नायब का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष से छीना मुद्दा

नायब सिंह सैनी। फाइल

व्यवस्था सुधार

केंद्र सरकार ने पहली बार अंगों के परिवहन को लेकर जारी किए दिशानिर्देश, वायु से लेकर सड़क मार्ग तक के लिए एसओपी, दान में मिले अंगों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना लक्ष्य

...ताकि जीती जा सके जिंदगी की जंग

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने पहली बार अंगों के परिवहन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि कम से कम समय में अंग प्रत्यारोपण कर जिंदगी की जंग जीती जा सके। सड़क, रेलवे से लेकर वायुमार्ग और जलमार्ग जैसे विभिन्न साधनों के जरिये मानव अंगों के निर्बाध परिवहन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लेकर आया है। यह एसओपी देशभर में अंग प्रत्यारोपण में शामिल लोगों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगी। अंग परिवहन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के पीछे केंद्र का लक्ष्य दान में मिले अंगों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और जीवन-रक्षक प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे अनगिनत रोगियों को आशा प्रदान करना है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा- 'यह एसओपी देशभर में अंग पुनर्प्राप्ति और प्रत्यारोपण संस्थानों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप हैं।' असल में जब अंगदाता और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही या अलग-अलग शहरों के अस्पतालों में हों तो उस जीवित अंग को प्रत्यारोपित करने वाले अस्पताल तक समय से पहुंचाना जरूरी होता है। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) के निदेशक डा. अनिल कुमार ने कहा कि जीवित अंग का परिवहन एक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग की शेल्फ लाइफ सीमित होती है और इसके परिवहन में विभिन्न एजेंसियों में समन्वय जरूरी होता है।

अंग प्रत्यारोपण में एक दशक में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोतरी पेज>>7

एसओपी के अहम बिंदु

- मानव अंगों को ले जाने वाली एयरलाइंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान की प्राथमिकता से टेक-आफ और लैंडिंग के लिए अनुरोध कर सकती हैं। वे अंग परिवहन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्राथमिकता से आरक्षण और देरी से उनके चेक-इन के प्रविधान का भी अनुरोध कर सकती हैं। जहां से अंग ले जाया जा रहा है, वह ह्वाई अड्डा गंतव्य ह्वाई अड्डे के साथ संवाद करेगा। आगमन पर ट्राली की व्यवस्था अंग बाक्स को विमान से एंबुलेंस तक ले जाने के लिए करनी होगी।

प्रतीकात्मक

- सड़क परिवहन के लिए विशिष्ट अधिकारियों या एजेंसियों के आग्रह पर ग्रीन कारिडोर प्रदान किया जा सकता है। पुलिस विभाग का एक नोडल अधिकारी प्रत्येक राज्य या शहर में ग्रीन कारिडोर बनाने से संबंधित मुद्दों को संभाल सकता है।
- मेट्रो से अंग परिवहन के लिए मेट्रो यातायात नियंत्रक को मानव अंगों को ले जाने वाली मेट्रो के लिए परिवहन को प्राथमिकता देनी होगी। मेट्रो सुरक्षा कर्मचारियों को अंग बाक्स ले जाने वाली टीम को बोर्डिंग तक एस्कार्ट करना चाहिए। मेट्रो अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा जांच में कोई देरी न हो। इसी तरह ट्रेनों और बंदरगाहों के माध्यम से अंगों के परिवहन की सुविधा के लिए एसओपी जारी की गई हैं
- अंग बाक्स को परिवहन के दौरान 90 डिग्री पर सीधा रखा जाना चाहिए और सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए। अंग बाक्स पर 'सावधानीपूर्वक संभालें' का संदेश भी लगाना होगा।

****

फर्जी किसानों की सूची बनाकर तृकां नेताओं ने किया 45 करोड़ गबन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

ईडी ने दावा किया है कि बंगाल के राशन आवंटन घोटाले में पिछले दिनों गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान उर्फ बिदेश और अलीफ नूर उर्फ मुकुल रहमान ने फर्जी किसानों की सूची बनाकर चावल की सब्सिडी में लगभग 45 करोड़ रुपये का गबन किया। दोनों भाइयों ने इस सूची में अपने रिश्तेदारों व करीबियों के नाम डाले थे। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इस भ्रष्टाचार में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने उनकी मदद की थी, जो अभी राशन आवंटन घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं।

जांचकर्ताओं का दावा है कि 45 करोड़ रुपये ज्योतिप्रिय की तीन कंपनियों में जमा किए गए थे। पैसे विभिन्न व्यवसायों और संपत्तियों में निवेश किए गए। ईडी ने इस मामले में मल्लिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ईडी को दोनों भाइयों की चार चावल मिलों व आटा मिलों के बारे में पता चला है। तृकां के दोनों नेता सब्सिडी वाले राशन के चावल को अपनी मिलों में पालिश कर ऊंचे दाम पर खुले बाजार में बेचते थे।

उधर, ईडी ने बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। साहा को घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सीबीआइ ने पिछले साल गिरफ्तार किया था, उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।

बंगाल राशन आवंटन घोटाला

- सूची में अपने रिश्तेदारों व करीबियों के डाले थे नाम, भ्रष्टाचार में पूर्व खाद्य मंत्री ने की थी मदद

130 किमी रेलवे ट्रैक दिल्ली कैंट से रेवाड़ी के बीच का नवीनीकरण का काम उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के इंजीनियरिंग विभाग ने पूरा कर लिया है। इस काम के बाद अब ट्रेनें अब अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकेंगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 5 अगस्त, 2024

आज का मौसम

बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने एवं हल्की वर्षा होने के आसार हैं। 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
5 अगस्त	35.0	27.0
6 अगस्त	34.0	27.0
नोएडा		
5 अगस्त	35.0	27.0
6 अगस्त	36.0	27.0
गुरुग्राम		
5 अगस्त	33.0	26.0
6 अगस्त	33.0	26.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

सिसोदिया की याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सीबीआइ और ईडी की ओर पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि सीबीआइ ने जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन वह रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। (प्रेट्र)

यमुना में मछलियों की मौत पर पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस

नई दिल्ली: बुराड़ी में यमुना किनारे बड़ी संख्या में मृत मछलियों के मिलने की जागरण डाट काम में प्रकाशित खबर का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संज्ञान लिया है। एनजीटी न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी व पर्यावरण विशेषज्ञ ए. सेंथिल वेल की पीठ ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) व उत्तर जिला के जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। (जासं)

पार्षदों की नियुक्ति पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली में एमसीडी के पार्षदों की नियुक्ति का फैसला बिना केजरीवाल सरकार के मंत्रियों से विचार-विमर्श कर किए जाने का आप ने विरोध किया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट दाखिल याचिका पर पांच अगस्त को फैसला सुनाएगा। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के फैसले पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पार्डीवाला ने पिछले साल 17 मई को सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। (प्रेट्र)

छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारी चिह्नित

कोचिंग सेंटर हादसा ▶ मुख्य सचिव को डीएम आज सौंपेंगे रिपोर्ट, एमसीडी, डीजेबी व पुलिस अफसरों से की गई पूछताछ

रिपोर्ट में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के बयान भी रिपोर्ट में शामिल किए गए

अजय राय ● जागरण

नई दिल्ली : ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव आइएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में हुए जलभराव में डूबने से तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में सिविक एजेंसियों के लापरवाह अधिकारी चिह्नित कर लिए गए हैं। मध्य दिल्ली के जिलाधिकारी जी सुधाकर ने इन अधिकारियों के पद और नाम के साथ कार्रवाई की संस्तुति के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके तहत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और संबंधित थाने के पुलिस अधिकारियों को तलब कर पूछताछ की गई। सोमवार को डीएम रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेंगे।

ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को भारी वर्षा के बाद जलभराव हो गया था। इस दौरान वर्षा का पानी राव आइएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में जाने से जलभराव हो गया। इसमें डूबने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहीं दो छात्रा और एक छात्र की मौत के बाद नागरिक एजेंसियों की लापरवाही को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद मुख्य सचिव ने मध्य दिल्ली के जिलाधिकारी

ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर राव आइएएस के बेसमेंट में हुआ था हादसा। फाइल

से जांच कर लापरवाह विभाग और अधिकारी को चिह्नित करने का आदेश दिया था। डीएम से इसकी रिपोर्ट सात दिन में मांगी गई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए मध्य जिला के डीएम ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित घटनास्थल और आसपास के इलाके में जाकर जांच की। संबंधित विभागों के अधिकारियों को दरियागंज स्थित जिला मुख्यालय तलब किया। इसमें दिल्ली नगर के करोलबाग जोन के सभी इंजीनियरों, दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अफसरों और राजेंद्र नगर थाने के एसएचओ एवं जांच अधिकारी को तलब कर उनकी भूमिका और कार्य संबंधी सवाल कर बयान दर्ज किए। इसके साथ डीएम ने धरने पर बैठे छात्रों को भी बयान देने के लिए बुलाया, जिसमें पांच छात्रों ने स्थिति के बारे में बताया। सूत्रों के अनुसार छात्रों ने सिविक एजेंसियों के अधिकारियों के साथ कोचिंग सेंटर के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है।

'सीसीटीवी से करें नालों की निगरानी, कूड़ा फेंकने वालों पर करें कार्रवाई'

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली

▶ बाढ़ रोकने के लिए बारापुला, सुनहरी व कुशक नाला साफ करने के उपराज्यपाल ने दिए निर्देश

पिछले वर्ष आई बाढ़ के मद्देनजर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को बारापुला, सुनहरी और कुशक नाला का निरीक्षण कर साफ-सफाई के निर्देश दिए। नालों में जमी गाद और मलबे को देख उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही नालों की सफाई का काम 15 दिन में हल हाल में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि वर्षा का पानी यमुना तक ले जाने वाले नालों की पिछले कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है। इसके कारण शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। इनमें दक्षिण पूर्व और नई दिल्ली के बड़े हिस्से शामिल हैं।

नालों की स्थिति और संबंधित एजेंसियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए उपराज्यपाल ने बाढ़ को कम करने व पानी के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने नालों की घेराबंदी करने को कहा, ताकि नालों में कूड़ा-कचरा और मलबा न डाला जा सके। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए नालों की निगरानी करने और नालों में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एजली ने एमसीडी और आइ एंड एफसी जैसी संबंधित नाला-स्वामित्व वाली

बारापुला नाले का निरीक्षण करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना। सौ. एलजी हाउस

एजेंसियों के अधिकारियों के साथ साइटों पर गाद निकालने के काम को देखा। साथ ही एजेंसियों को 15 दिनों के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया।

वहीं संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को तस्वीरों के साथ सफाई कार्यों की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। आइ एंड एफसी विभाग के स्वामित्व वाले बारापुला नाले में पुलिया के नीचे 12 ब्लाक में से केवल पांच ही चालू मिलीं। झुग्गियों के अतिक्रमण के कारण इनमें से एक खाड़ी भी बंद थी। नाले के जाम होने से पानी बैक फ्लो होता है और निजामुद्दीन, लोधी रोड, जंगपुरा, सीजीओ कांप्लेक्स और अन्य आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है।

बारापुला नाले की सफाई के लिए जिम्मेदारी तय करें

विनीत त्रिपाठी, जागरण, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में नालों की सफाई बेपटरी क्यों है, इसका एक उदाहरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष बारापुला नाले के एक हिस्से को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सामने आया। बारापुला नाले के ए-7 से बी तक के हिस्से की सफाई को लेकर डीडीए, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। दोनों एजेंसियों के रुख पर हैरानी जताते हुए एनजीटी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सफाई में तत्काल बैठक बुलाकर एजेंसी की जिम्मेदारी तय की जाए। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी व पर्यावरण सदस्य डा. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने मुख्य सचिव को बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी। निजामुद्दीन वेस्ट एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर अधिवक्ता कालिन गोंसाल्वेस ने बारापुला नाले के ए-1 से ए-7 और ए-7 से बी के हिस्से में सिल्ट नहीं निकाले जाने का मामला उठाया।

आर्मी प्रेस के ध्वस्तीकरण पर नहीं कर रहे हैं विचार: केंद्र सरकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के पूर्व के आदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तरी दिल्ली के खैबर पास क्षेत्र में आर्मी प्रेस को ध्वस्त करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। कुछ व्यक्तियों की याचिका पर एल एंड डीओ ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ के समक्ष जवाब दाखिल कर यह जानकारी दी है। अदालत ने केंद्र के बयान को दर्ज करते हुए आवेदन का निपटारा कर दिया। साथ ही खैबर पास के निवासियों द्वारा मार्च में जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका खारिज कर दी। ।

एल एंड डीओ द्वारा गत शनिवार को सिविल लाइंस में एक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाना था। यहां राष्ट्रीय पिस्टल कोच समरेश जंग और उनकी पत्नक विजेता पत्नी अनुजा सहित कई परिवार रहते हैं। याचिकाकर्ताओं ने 2010 में याचिका दायर की थी और अदालत ने कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया था। हालांकि, इस वर्ष के प्रारंभ में अनधिकृत कब्जे और निर्माण को हटाने की चेतावनी दी गई तो याचिकाकर्ताओं ने स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया। केंद्र के स्थायी वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि 29 नवंबर 2010 के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं के कब्जे के संबंध में कठोर कदम न उठाने का आदेश दिया गया था।

सीबीआइ का छापा पड़ा तो हटाए जाएंगे थानाध्यक्ष

राकेश कुमार सिंह ● जागरण

▶ पुराने नियम को पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दोबारा किया लागू

▶ दो वर्षों से थानों व चौकियों में लगातार सीबीआइ छापे पड़ने से सवाल उठने पर आयुक्त को लेना पड़ा कड़ा निर्णय

नई दिल्ली: दिल्ली के थानों व चौकियों में आए दिन सीबीआइ के छापे पड़ने से पुलिस महकमे में इन दिनों इसी की ही चर्चा है। छापों को लेकर सवाल उठने पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने अब यह नियम बना दिया है कि जिस थाने अथवा चौकी में सीबीआइ के छापे पड़ेंगे वहां के थानाध्यक्ष अथवा थानाध्यक्ष का काम देखने वाले एटीओ या इंस्पेक्टर इंवेस्टिगेशन को लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। पिछले दो वर्षों से थानों व चौकियों में लगातार सीबीआइ के छापे पड़ने पर आयुक्त को पुराने नियम को दोबारा लागू करना पड़ा। पूर्व पुलिस आयुक्त वाईएस डडवाल के कार्यकाल में इसी तरह का नियम था, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया था।

पिछले माह कई थानों में सीबीआइ के छापे पड़ने पर पुलिस आयुक्त ने दोनों कानून एवं व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव व मधुप तिवारी को अपने-अपने जोन के आला अधिकारियों की बैठक बुला पुलिस को भ्रष्टाचार के मामले में फंसने से बचने की सख्त हिदायत देने को कहा। इसके बाद मधुप तिवारी ने अपने जोन के संयुक्त आयुक्त व डीसीपी को मुख्यालय में बुला एसीपी व थानाध्यक्षों के जरिये पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेने से बेचने की हिदायत देने को कहा। रवींद्र सिंह यादव ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया। थानाध्यक्षों को लाइन हाजिर करने का मौखिक आदेश ही दिया गया है। इस पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है।

बीते 26 जुलाई को द्वारका सेक्टर 23 थाने में तैनात एएसआइ अनिल कुमार को सीबीआइ ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। एएसआइ ने पीड़ित से उसके जब्त वाहन को छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की थी।

स्थायी नियुक्ति नहीं, संविदा के सहारे चलेगा एम्स

रणविजय सिंह ● जागरण

नई दिल्ली: देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की पहचान यहां की फैकल्टी रही है, लेकिन लंबे समय से स्थायी नियुक्तियां नहीं होने से डाक्टरों की कमी से जूझ रहा यह संस्थान अब संविदा के सहारे चलेगा।

जानकारी के मुताबिक, एम्स में फैकल्टी स्तर के डाक्टरों के 1207 स्वीकृत पद हैं। हाल ही में आरटीआइ के तहत मांगी गई जानकारी में बताया गया कि संस्थान में फैकल्टी स्तर के डाक्टरों के 390 पद खाली हैं, जिसमें 115 प्रोफेसर और 275 सहायक प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इसका कारण यह है कि एम्स में लंबे समय से स्थायी तौर पर फैकल्टी स्तर के डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। एम्स में स्थायी तौर पर अंतिम बार सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति वर्ष 2021-22 में हुई थी। पिछले वर्ष अप्रैल में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। बाद में नियुक्ति प्रक्रिया के प्राविधानों की समीक्षा के कारण उसे टालना पड़ा। एम्स

125 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए अस्पताल प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया

दिल्ली स्थित एम्स। फाइल

ने अपने जवाब में 229 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति का भरोसा दिया था, लेकिन अब एम्स ने संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए 117 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआइ) में सबसे अधिक 46 सहायक प्रोफेसर नियुक्त होंगे। डाक्टर बताते हैं कि वैसे तो किसी विभाग में डाक्टरों की ज्यादा कमी होने पर अगल-अगल विभागों में अस्थायी सहायक प्रोफेसर तैनात होते रहे हैं, लेकिन पहली बार इतने बड़े स्तर पर संविदा के आधार पर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए पहल की गई है।

संविदा पर नियुक्ति से सबसे अधिक शोध प्रभावित : संविदा पर नियुक्ति से सबसे अधिक प्रभाव शोध कार्यों पर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर शोध परियोजनाएं तीन वर्ष के लिए होती हैं। इस वजह से अस्थायी तौर पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर को जल्दी शोध परियोजनाएं नहीं मिल पातीं। इसके अलावा एम्स में गंभीर व पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीज अधिक पहुंचते हैं, जिनका लंबे समय तक इलाज चलता है। संविदा पर नियुक्त डाक्टरों के एक-दो वर्ष के बाद छोड़कर चले जाने पर मरीजों का फालोअप इलाज प्रभावित हो सकता है। एम्स का सालाना बजट साढ़े चार हजार करोड़ का है। इसलिए स्थायी नियुक्ति में फंड की कमी भी अड़चन नहीं है। एक वरिष्ठ डाक्टर ने बताया कि स्थायी नियुक्ति के लिए संस्थान के विभिन्न कमेटियों व गवर्निंग बाडी से स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसमें समय लगता है। संभवतः इस वजह से संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन एम्स ने आधिकारिक तौर पर इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

एम्स अक्टूबर के पहले सप्ताह में नए अस्पताल में शुरू करेगा ओपीडी

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: एम्स ने मैदान गढ़ी में बनकर तैयार नए अस्पताल एम्स-सीएपीएफआइएमएस (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान) में डाक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 50 वरिष्ठ रेजिडेंट डाक्टरों की नियुक्ति अगले माह हो जाएगी। इसके अलावा संविदा पर सहायक प्रोफेसर भी नियुक्त होंगे। अक्टूबर के पहले सप्ताह में एम्स इस नए अस्पताल में ओपीडी सुविधा शुरू कर देगा। इससे अर्धसैनिक बलों के परिवारों के साथ-साथ आम लोगों को भी इलाज का एक बेहतर विकल्प मिल पाएगा। दक्षिणी दिल्ली में मैदान गढ़ी के आसपास के इलाके के लोगों को सबसे अधिक फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2,091 करोड़ की लागत से सीएपीएफआइएमएस का निर्माण कराया है।

गाजियाबाद में खुला देश का पहला एआइ आधारित आंगनबाड़ी केंद्र

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश के पहले एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एआइ से बच्चों को और बेहतर शिक्षा व जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र की दिनभर की गतिविधियों की रिपोर्ट एआइ आधारित डिजिटल बोर्ड के जरिये जिला प्रशासन तक पहुंचेगी। गाजियाबाद में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को एआइ आधारित बनाया जाएगा।

▶ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया शुभारंभ, सौ और केंद्र एआइ तकनीक से होंगे उन्नत

रविवार को जिले के ग्राम मोरटी में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में बच्चों के साथ-साथ महिलाएं भी कुपोषित हैं। जब हमारी माताएं सशक्त बनेंगी तो हमारे बच्चे और देश भी सशक्त बनेगा। आंगनबाड़ी सहित अन्य संस्थाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषणयुक्त आहार प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने एक किट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी और निर्देशित किया कि इस प्रकार की किट सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर होनी चाहिए। छात्रों से बातचीत की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विद्यार्थियों को पढ़ाने के तरीके के बारे में जानकारी ली।

गाजियबाद के मोरटी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बच्चों की प्रस्तुति देखतीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सौ. प्रशासन

वकीलों के फीस बिलों को अपलोड करने की व्यवस्था को बनाएं सरल: हाई कोर्ट

जासं, नई दिल्ली: राज्य सरकार की एक पैनल अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित आनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम (ओएसडब्ल्यूएस) पोर्टल पर सरकारी पैनल में शामिल वकीलों के फीस बिलों को अपलोड करना सुचारु किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने कहा कि इस प्रणाली को वकीलों के शुल्क बिलों की मंजूरी के लिए एक माडल बनना चाहिए ताकि विभिन्न सरकारी विभागों में भारी कागजी बोझ से बचा जा सके।

इससे पहले दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि ओएसडब्ल्यूएस पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है और बिल अपलोड करना निर्बाध हो गया है। अदालत ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ओएसडब्ल्यूएस प्रणाली कुशलता से काम करे। अदालत ने कहा, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

डीयू कम प्रचलित कोर्सों में 10 व अधिक प्रचलित में 50 प्रतिशत प्रवेश देगा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ सीटों के खाली रहने की वजह से तय सीटों से अधिक पर प्रवेश लेने का निर्णय लिया

▶ विद्यार्थियों के निजी कालेजों की ओर रुख करने से सीटें खाली रहने से चिंता बढ़ी है

डीयू में प्रवेश को लेकर जानकारी लेती छात्राएं। जागरण आर्काइव

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने स्नातक की सभी सीटें भरने के लिए तय सीटों से 50 प्रतिशत अधिक प्रवेश देने का निर्णय लिया है। इसे दो तरह से लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय के अधिक प्रचलित कोर्सों की सीटों 50 और कम प्रचलित कोर्सों की सीटों पर 10 प्रतिशत तक अधिक प्रवेश दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर सभी सीटें नहीं भरती हैं तो 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि, पिछले वर्ष भी कुछ कालेजों की सभी सीटों को भरने के लिए अधिक सीटों से अधिक प्रवेश लिए गए थे। हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि प्रवेश के बावजूद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अन्य शिक्षण संस्थानों का विकल्प चुन लिया था और पांच हजार सीटें खाली रह गई थीं।

डीयू में प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। डीयू में 69 कालेजों की 71 हजार सीटों पर प्रवेश दिया जा रहा है। सात अगस्त तक छात्र कालेज और कोर्स के संयोजन भर सकते हैं। पहली प्रवेश सूची 16 अगस्त को जारी की जाएगी। इस वर्ष प्रवेश सत्र पिछले वर्षों से बहुत अधिक लंबित हो चुका है। सीटें खाली रहने से बचाने के लिए डीयू ने तय सीटों से अधिक प्रवेश देने की रणनीति बनाई है। हालांकि, डीयू में कई ऐसे कोर्स हैं, जिनमें सीटें नहीं भर पातीं, क्योंकि उनमें छात्र प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं रहते हैं। ऐसे कोर्सों को चिह्नित कर उनमें 10 प्रतिशत अधिक प्रवेश की योजना बनाई गई है। डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि सभी सीटें भरने को लेकर विश्वविद्यालय प्रयासरत हैं, इसलिए ही 50 प्रतिशत अधिक प्रवेश देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ कोर्स को नए तरह से बदला जा रहा है।

लामबंदी

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव में हिंदू मतदाताओं को साधने के लिए प्रत्याशियों के पैनलों द्वारा किए जा रहे आयोजन, कुल 2,054 मतदाताओं में से 280 मतदाता हैं हिंदू, 11 अगस्त को होना है मतदान

आइआइसीसी के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में हिंदू मतदाता

नेमिष हेमंत ● जागरण

नई दिल्ली: देश-विदेश में प्रतिष्ठित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर (आइआइसीसी) के आगामी 11 अगस्त को होने वाले चुनाव में हिंदू मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इसके चुनाव में दुनियाभर के 2,054 लोग मतदान करेंगे, जिसमें करीब 280 मतदाता हिंदू हैं, जो इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा बोर्ड आफ ट्रस्टी, कार्यकारी समिति के सदस्यों का भाग्य तय करेंगे।

दिल्ली के लोदी रोड स्थित आइआइसीसी का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पहल पर वर्ष 1981 में हुआ था। हमदर्द के संस्थापक हकीम अब्दुल हमीद इसके पहले अध्यक्ष थे। 2006 में इसके भव्य केंद्र का उद्घाटन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था। आइआइसीसी का हर पांच वर्ष बाद चुनाव होता है। इस बार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष समेत 13 पदों के

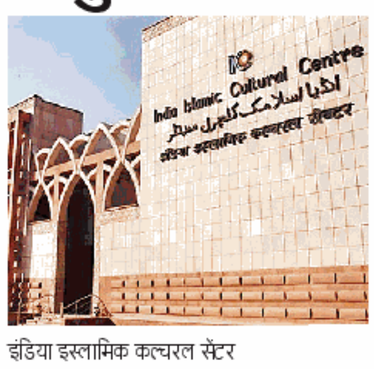

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर

लिए सात पैनल मैदान में हैं। मौजूदा अध्यक्ष उद्योगपति सिराजुद्दीन कुरैशी लगातार चार बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, जो इस बार बोर्ड आफ ट्रस्टीज के एक सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके पैनल से डा. माजिद अहमद तालिकोटी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। एक अन्य पैनल पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का है तो एक अन्य पूर्व आइएएस अफजाल अमानुल्लाह के नेतृत्व में चुनावी मैदान में है।

इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में प्रतिभावान और योग्य सदस्यों की कोई कमी नहीं है। उनकी योग्यता और अनुभव का लाभ उठाते हुए उस सही दिशा देने की जरूरत है। साथ ही युवाओं के बेहतर मार्गदर्शन के लिए सेमिनार, गोष्ठियां और सेमिनार आयोजित होने चाहिए। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों के पैनल द्वारा मतदाताओं को साधने का प्रयास तेजी से चल रहा है। इसके लिए प्रत्याशी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में मतदाताओं के साथ बैठकों का आयोजन कर रहे हैं और उसमें अपने दावे-वादे कर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। उन्हें साधने की अपील की जा रही है। इसके मतदाता सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद, बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर, स्तंभकार शाहिद सिद्दीकी समेत देश-विदेश में बसे नेता, नौकरशाह, अधिवक्ता, बुद्धिजीवी व उद्योगपति शामिल हैं। कई अनिवासी भारतीय भी इस संस्था के सदस्य हैं। हिंदू मतदातों में प्रमुख नाम डा. कर्ण सिंह है, गजल महफिल के आयोजकों में बड़ी हस्ती कामना प्रसाद जैसे नाम शामिल हैं। अधिवक्ता अनिल कुमार वर्मा, कविता खन्ना, गोपाल सुब्रमण्यम, नीरज चौधरी व विकास अरोड़ा भी मतदाताओं में शामिल हैं।

चुनाव लड़ रहे कुछ पैनल का जोर हिंदू मतदाताओं को भी साधने पर है और इसके लिए हिंदू मतदाता आधारित अलग से आयोजन किए जा रहे हैं। अधिवक्ता अनिल कुमार वर्मा कहते हैं कि इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके निर्णायक होने की उम्मीद कम है, क्योंकि उनका एकतरफा वोट किसी एक पैनल को नहीं जा रहा है। हर पैनल के साथ वह अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर जुड़े हुए हैं।

****

60 किमी तक पीछा कर पार्श्वनाथ डेवलपर्स के एमडी को दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ दिल्ली पुलिस ने आइजीआइ एयरपोर्ट के पास से किया गिरफ्तार, मिली जमानत

शाहदरा जिले की स्पेशल टास्क फोर्स ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स के सीईओ व प्रबंध निदेशक संजीव कुमार जैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 60 किलोमीटर पीछा कर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट के पास से उसे गिरफ्तार किया। आरोपित गुरुग्राम स्थित डीएलएफ फेज-दो का रहने वाला है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने संजीव कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपित को आयोग के सामने पेश किया, जहां से उसे जमानत दे दी गई।

शाहदरा जिला के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 2017 में पार्श्वनाथ डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार जैन के खिलाफ एनसीडीआरसी में रजत बब्बर और अन्य ने शिकायत दी थी। शिकायत के बाद एमडी संजीव कुमार जैन आयोग के सामने पेश नहीं हुआ। 2022 में आयोग ने निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 18 जुलाई 2024 को संजीव जैन को आयोग में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। तीन अगस्त को पुलिस को मोबाइल की लोकेशन से संजीव जैन के असोला भाटी के पास मौजूद होने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया तो वह ओखला, चाणक्यपुरी, धौला कुआं होते आइजीआइ एयरपोर्ट की तरफ भागा। 60 किमी पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे एयरपोर्ट के पास से ही दबोच लिया।

15 करोड़ घरों तक जल हर घर नल योजना से पहुंच चुका है। 75 प्रतिशत घरों को देश में कवर कर चुके हैं, साथ ही डायरिया के तीन लाख केस भी इससे कम हुए हैं।

लाल किले से नारी सशक्तीकरण का संदेश देंगी 150 महिला सरपंच

जितेंद्र शर्मा ● जागरण

- स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभर से आमंत्रित की गई हैं बेहतर काम करने वालीं जनप्रतिनिधि
- पंचायतीराज में महिलाओं के नेतृत्व विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भी शामिल होंगी अतिथि

लाल किला। फाइल फोटो

नई दिल्ली: अपनी पंचायतों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने में अहम भूमिका निभा चुकीं महिला जनप्रतिनिधि लाल किले से नारी सशक्तीकरण का संदेश देंगी। पंचायतीराज मंत्रालय के मानकों पर खरी उतरीं और राज्यों द्वारा चयनित 150 महिला सरपंच, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि महिला जनप्रतिनिधि इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी। इनकी नेतृत्व क्षमता को और तराशने के लिए न सिर्फ यहां राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा यहां इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।

नारी शक्ति को एक प्रमुख जाति के रूप में संरक्षण व प्रोत्साहन देने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करा चुकी है। राजग सरकार समय-समय पर बेहतर काम करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को प्रेरणापुंज के रूप में स्थापित करने के अवसर तलाश रही है।

गणतंत्र दिवस समारोह में केंद्र सरकार ने देशभर से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था, पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में सिर्फ पंचायतों की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को ही बुलाया गया है। गत दिनों पंचायतीराज मंत्रालय की ओर से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा गया था कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए अपने-अपने राज्यों की महिला पंचायत जनप्रतिनिधियों का चयन करें। इसके लिए मानक बताए गए कि पंचायत ने कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पुरस्कार जीता हो, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेजयल, स्वच्छता या पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया हो, सामाजिक-आर्थिक विविधता के लिए कार्य किया हो या पंचायत प्रतिनिधि का संबंध स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हो। राज्यों की ओर से प्राप्त सूची को पंचायतीराज मंत्रालय ने अपने मानकों पर परखा और अंतिम सूची तैयार कर ली है। महिला जनप्रतिनिधियों को उनके पति सहित आमंत्रित किया गया है। उनके साथ राज्यों से नोडल अधिकारी भी व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए आएंगे। इस तरह 150 महिला प्रधान या सरपंच, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कुल 274 अतिथि देशभर से आ रहे हैं।

इन महिला जनप्रतिनिधियों के लिए 14 अगस्त को नई दिल्ली स्थित डा. भीमराव आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संबह दस बजे से 'पंचायतीराज में महिला नेतृत्व' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दोपहर में सभी विशिष्ट अतिथि प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण करेंगे, जबकि शाम को आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ही केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री ललन सिंह और राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा।

राज्यों से आने वाले अतिथि

राज्य	कुल अतिथियों की संख्या	राज्य	कुल अतिथियों की संख्या
उत्तर प्रदेश	48	उत्तराखंड	8
महाराष्ट्र	30	हिमाचल प्रदेश	8
बिहार	20	पंजाब	7
मध्य प्रदेश	18	जम्मू-कश्मीर	5
राजस्थान	17	मेघालय	5
गुजरात	16	अरुणाचल प्रदेश	3
तमिलनाडु	16	असम	3
ओडिशा	12	दादरा-नगर हवेली और दमन-द्वीव	3
आंध्र प्रदेश	10	सिक्किम	3
हरियाणा	9	नगालैंड	2
झारखंड	9	मिजोरम	2
केरल	9	मणिपुर	2
छत्तीसगढ़	9	कुल	274

पायलटों को थकान से बचाने के लिए उड़ान ड्यूटी के नए मानदंड लागू करें

- एफआइपी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस बारे में लिखा पत्र

प्रतीकात्मक

मुंबई, प्रेट्र: पायलटों की थकान के बारे में चिंता जताते हुए पायलटों के संगठन फेडरेशन आफ इंडियन पायलट्स (एफआइपी) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से उड़ान ड्यूटी और आराम की अवधि के बारे में संशोधित मानदंडों को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू को लिखे पत्र में एफआइपी के अध्यक्ष सीएस रंधावा ने संशोधित सीएआर को जल्द से जल्द लागू करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

छह हजार से अधिक सदस्यों वाले संगठन एफआइपी ने पहले भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पायलटों के लिए संशोधित सीएआर (नागरिक उड्डयन आवश्यकता) पर पत्र लिखा था, जब डीजीसीए ने उनके कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया था। उड़ान ड्यूटी समय सीमा से संबंधित संशोधित सीएआर पायलटों की थकान पर बढ़ती चिंताओं के बीच पायलटों को अधिक आराम का समय प्रदान करने का प्रयास करता है। मार्च में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इसके कार्यान्वयन को स्थगित करने का फैसला किया था। उल्लेखनीय है कि पायलटों का कहना है कि उन्हें अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है।

विपक्ष कितना भी शोर कर ले, 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे : अमित शाह

कहा- विपक्ष में रहकर काम करना सीख लेंगे तो कांग्रेस व उसके सहयोगियों के लिए होगा अच्छा

बोले, 2047 में विकसित भारत का संकल्प लोगों के एक-एक कदम बढ़ने से होगा पूरा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

मनीमाजरा शिवालिक गार्डन में 24 घंटे जलापूर्ति प्रोजेक्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर पहुंचते ही लोगों का अभिवादन करते गृह मंत्री अमित शाह। संजय घिल्डियाल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को जितना भी शोर मचाना है मचा ले, 2029 में भी नरेन्द्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। पिछले तीन चुनावों में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं, उससे अधिक सीट तो अकेले भाजपा को अब मिली है।

गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह (विपक्ष) कहते हैं कि यह सरकार चलने वाली नहीं है, लेकिन यह सरकार पांच साल बेहतर ढंग से पूरा करेगी। आगे भी यही सरकार आने वाली है। उन्हें यह बात समझ आ जानी चाहिए। शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दलों को विपक्ष में रहकर काम करना सीख लेना चाहिए उनके काम आएगा। विपक्ष में रहकर मर्यादा के साथ काम करना सीखेंगे, तो अच्छा होगा। 2014 से 2024 तक दस वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में जो कार्य हुए हैं वह स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने कभी बड़े कार्यक्रम नहीं किए। केवल औपचारिकता निभाई गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाते हुए सभी को जोड़ा। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकल्प लिया है। उन्होंने जो संकल्प लिए वह एक-एक कर सब पूरे किए, लेकिन उनका विकसित भारत का यह संकल्प जनता के संकल्प से ही पूरा होगा।

हर घर जल से डायरिया के 3 लाख केस घटे : शाह ने कहा कि स्वच्छ जल हर नागरिक तक पहुंचे इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना शुरू की है। 15 करोड़ घरों तक जल इस योजना से पहुंच चुका है। 75 प्रतिशत घरों को देश में कवर कर चुके हैं, साथ ही डायरिया के 3 लाख केस भी इससे कम हुए हैं। मोदी 3.0 में हर घर जल पहुंचाने की योजना पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। बच्चे को सिखाया जाए कि थाली में जूठा नहीं छोड़ना, तो इस संकल्प से देश आगे बढ़ेगा। बच्चा संकल्प ले कि रोजाना सुबह माता पिता के पैर छूकर जाऊंगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। व्यापारी संकल्प लें कि वह टैक्स की चोरी नहीं करेगा, कोई व्यक्ति यह ठान ले कि ट्रैफिक नियमों को कभी नहीं तोड़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सभी एक-एक कदम बढ़ाएंगे तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद भारत विकसित बन जाएगा।

कटारिया की तारीफ की : शाह ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया राजस्थान से हैं, उन्हें पानी का मूल्य अच्छे से पता है। मैं गुजरात से हूं और मैंने भी पानी की किल्लत देखी है। मनीमाजरा में लोगों को पानी टैंक में सहेजने की जरूरत नहीं होगी, चौथी मंजिल तक पूरे प्रेशर से पानी चढ़ेगा। 75 करोड़ की इस परियोजना से पानी रिसाव के कारण बर्बाद नहीं होगा। स्मार्ट मीटर से चोरी भी तुरंत पता चलेगी।

असम में 'लव जिहाद' मामले में शीघ्र लाएंगे उम्रकैद का कानून : हिमंत

- कहा-हिमंता सरकार असम में जन्मे लोगों को देगी सरकारी नौकरी
- सरमा बोले-जन्म प्रमाणपत्र के साथ बच्चों को मिलेंगे आधार कार्ड

गुवाहाटी में रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा (प्रथम पंक्ति में दाएं से दूसरे) प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए। एएनआइ

गुवाहाटी, प्रेट्र : उत्तर प्रदेश सरकार के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने भी घोषणा की है कि उनकी सरकार जल्द ही 'लव जिहाद' के मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाएगी। सरमा ने गुवाहाटी में राज्य भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा नेताओं के साथ बात करते हुए कहा कि जल्द ही इस बाबत विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा।

असम के मुख्यमंत्री सरमा रविवार को कहा, असम सरकार की ओर से नई अधिवास नीति भी लाई जाएगी। इसके तहत केवल असम में जन्मे लोगों को ही सरकारी नौकरियों के लिए योग्य माना जाएगा। सरमा ने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार राज्य सरकार की ओर से दी गई नौकरियों में असम के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार ने चुनाव से पूर्व एक लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। इस बाबत जल्द ही सूची जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, असम सरकार ने मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी निर्णय लिया है। सरमा ने कहा कि सरकार ऐसे लेन-देन को होने से रोक तो नहीं सकती लेकिन वह इसे अंतिम रूप देने से पहले मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए उनके सामने ऐसे मामलों को पेश करना अनिवार्य कर देगी।

सरमा ने यह भी कहा, असम सरकार राज्य के 13 मेडिकल कालेजों में नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड जारी करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगी। नवजात शिशुओं के जन्म के कुछ दिनों के भीतर ही आधार कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। शुरू में यह परियोजना केवल जिले के मेडिकल कालेजों में शुरू की जाएगी। उसके बाद यह योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी, ताकि बच्चों को उनके जन्म के साथ ही आधार कार्ड मिल जाए और उनके परिजनों को इसके लिए कतार में नहीं लगना पड़े। उन्होंने कहा, असम सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के युवाओं के लिए विशेष योजना शुरू की है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवाओं को उद्योग लगाने के लिए दो लाख रुपये देने की योजना शुरू की गई है। इसके पहले चरण में 16 अगस्त से 5 सितंबर तक जिलों में इंटरव्यू लिए जाएंगे और 30 सितंबर तक धनराशि का वितरण किया जाएगा।

नगरीय सीमा में आने वाले उद्योगों से मप्र में नहीं लिया जाएगा संपत्ति कर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल

- निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके देने जा रही है छूट
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग कैबिनेट में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अलग-अलग अधिनियमों में कई परिवर्तन कर रही है। नगरीय सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से दोहरा कर वसूला जाता है। नगरीय निकाय भी संपत्ति कर(प्रापर्टी टैक्स) लेते हैं और उन्हें लीज रेंट भी देना होता है। औद्योगिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की पहल पर अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगरीय निकायों की सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को प्रापर्टी टैक्स में छूट देने जा रही है। हालांकि, इनसे सेवा शुल्क लिया जाएगा जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में आधा होगा। इसके लिए टैक्स में छूट का प्रस्ताव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और वित्त विभाग से अभिमत लेकर कैबिनेट में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए सरकार नियमों को उद्योगों को अनुकूल बना रही है। अभी नगरीय क्षेत्र की सीमा में आने वाले औद्योगिक केंद्रों में स्थापित उद्योगों से संबंधित नगरीय निकाय प्रापर्टी टैक्स लेते हैं। इसके लिए मप्र नगर निगम अधिनियम 1956 व मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 में प्रविधान हैं। वर्ष 2013 में सरकार मप्र निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंधन अधिनियम में यह प्रविधान कर चुकी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों से प्रापर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद भी स्थानीय निकायों द्वारा न केवल टैक्स वसूला जा रहा है बल्कि न देने पर कार्रवाई भी हो रही है। विभिन्न औद्योगिक संगठन दोहरे कराधार को समाप्त करने की मांग सरकार से कर चुके हैं। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक संगठनों के अलावा उद्योगपतियों से चर्चा भी कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी उद्योगपति को प्रदेश में उद्योग लगाने में कठिनाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री की पहल के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मप्र नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 163 और नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 132 के प्रविधान अनुसार उद्योगों को प्रापर्टी टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों से प्रापर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा पर उन्हें सेवा शुल्क देना होगा। यह जलकर, स्वच्छता सहित अन्य सुविधाओं के लिए जो शुल्क देना होता है, वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में आधा ही लगेगा।

तीनों सेनाओं के वित्तीय तालमेल पर आज सीडीएस चौहान करेंगे सम्मेलन

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान और अन्य वरिष्ठ सैन्य अफसर सोमवार को तीनों सेनाओं (थल, नौ और वायु) को संयुक्त रूप से काम करने में वित्तीय योजनाओं में उचित तालमेल के लिए विचार-विमर्श करेंगे।

सैन्य अधिकारियों ने रविवार को बताया कि तीनों सेनाओं के संयुक्तीकरण के लिए उनके बीच समुचित व्यवस्था, एकजुटता, वित्तीय तालमेल पर सम्मेलन होगा। इसकी अध्यक्षता जनरल अनिल चौहान करेंगे। केंद्र सरकार के थिएटर कमांड के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मूर्तरूप देने के लिए सशस्त्र सेनाओं में वित्तीय योजनाओं के लिए समुचित तालमेल और व्यापक एकजुटता सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श होगा। थिएटर माडल के तहत सरकार तीनों सेनाओं की एकीकृत क्षमताओं का पूरा लाभ लेना चाहती है। ताकि युद्ध और अभियानों के दौरान उनके संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। सम्मेलन में सशस्त्र सेनाओं के वित्तीय मुद्दों को सुलझाने को रक्षा मंत्रालय के अफसरों, सैन्य मुख्यालयों व रक्षा लेखा महानियंत्रक की भी भागीदारी होगी।

जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों को ड्यूटी के दौरान लेना होगा टिकट

- जीआरपी सिपाही आधिकारिक यात्रा के दावों को नहीं कर सका साबित
- ट्रिब्यूनल ने उसके दायर मुआवजा संबंधी याचिका को किया खारिज

प्रतीकात्मक

अहमदाबाद, प्रेट्र : रेलवे दावा ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों को ट्रेन यात्रा के लिए वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी या टिकट खरीदना होगा। केवल पहचान पत्र ले जाना पर्याप्त नहीं है। ट्रिब्यूनल ने एक कांस्टेबल द्वारा दायर मुआवजे की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। उसने दावा किया था कि ट्रेन से गिरने के समय वह आधिकारिक ड्यूटी पर था। ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद पीठ ने जीआरपी कर्मियों को ड्यूटी कार्ड पास जारी करने के परिपत्र के संबंध में रेलवे के लापरवाह रवैये को भी रेखांकित किया, जिन्हें अक्सर यात्रा करनी पड़ती है।

जीआरपी कांस्टेबल राजेश बगुल ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर रेलवे से ब्याज के साथ आठ लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। दावा किया था कि दुर्घटना के दिन वह ड्यूटी पर थे। याचिका के अनुसार, बगुल 13 नवंबर, 2019 को आधिकारिक ड्यूटी के लिए सूरत रेलवे पुलिस थाने गए थे। वह सूरत-जामनगर इंटरसिटी ट्रेन से सूरत से भरूच लौट रहे थे। इसी दौरान वह पालेज स्टेशन पर गिर गए, जिससे उनके बाएं पैर में गंभीर चोटें आईं और पैर का एक हिस्सा काटना पड़ा। ट्रिब्यूनल के सदस्य (न्यायिक) विनय गोयल ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बगुल अपने आधिकारिक यात्रा दावों को साबित करने के लिए कोई वैध यात्रा अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। कहा कि वैध यात्रा अनुमति के अभाव में आवेदक को वास्तविक यात्री नहीं माना जा सकता। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि रेलवे को जीआरपी और आरपीएफ अधिकारियों को वैध यात्रा अनुमति देने के संबंध में जारी परिपत्र का पालन करना चाहिए।

गोवा विस में एसटी आरक्षण संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश होने की संभावना

नई दिल्ली, प्रेट्र: गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित विधेयक इस हफ्ते लोकसभा में पेश किया जा सकता है। गोवा विधानसभा में फिलहाल अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। समुदाय की मांग के बीच अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए सरकारी कामकाज में सूचीबद्ध किया गया है। संसद सत्र का समापन 12 अगस्त को होना है।

विधि मंत्रालय का विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में अनुसूचित जनजातियों की आबादी अधिसूचित करने का अधिकार देगा। विधेयक के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 में मंजूरी दी थी। अभी तक 40 सदस्यीय विधानसभा में कोई भी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है, एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति समुदाय की मांग है कि विधानसभा में चार सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएं। गोवा में अनुसूचित जनजाति की आबादी डेढ़ लाख है।

परिवर्तन की बयार

अनुच्छेद 370 हटने के बाद पांच वर्ष में ही बदल गई जम्मू-कश्मीर की आबोहवा, प्रदेश में तेजी से आ रहा पूंजी निवेश, पर्यटन के नए केंद्र के रूप में बनी पहचान

नया आगाज, नई तस्वीर ...विकास के पथ पर जम्मू-कश्मीर

नवीन नवाज ● जागरण

प्रतीकात्मक

श्रीनगर : पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए के निस्तीकरण के साथ सामाजिक न्याय, राजनीतिक सशक्तीकरण, आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं विश्वास का जो पौधा लगाया गया था, वह अब फल देने लगा है। आमजन बिना किसी भय-व्यवधान के सपनों को पूरा करने की उड़ान भर रहे हैं। अलगाववाद की राजनीति पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। आतंक भी अंतिम सांसें गिन रहा है, पर षड्यंत्र जारी है जिसे सुरक्षाबल नाकाम बना रहे हैं। आजादी का नारा देने वाले कई चेहरे मई में संपन्न हुए लोकतंत्र के महोत्सव में अपनी अंगुली पर मतदान की स्याही लगाकर इतराते नजर आए।

कुछ भी असंभव नहीं है, यह कहावत बीते पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर में बह रही परिवर्तन की बयार सत्य साबित करती है। पत्थरबाजी और संगठित हड़ताल अब बंद हो चुके हैं। आतंकी हिंसा और नए आतंकियों की भर्ती न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। जिस लाल चौक पर कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, वहां अब तिरंगा लहराती भीड़ आतंक से मुक्ति का जश्न मनाती है। यह कश्मीर में सैलानियों के लिए हीं नहीं आम लोगों के लिए भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र और सेल्फी प्वाइंट बन चुका है। हाल में सपन्न लोकसभा चुनाव में 35 वर्ष का सबसे ज्यादा 58.46 प्रतिशत रिकार्ड मतदान हुआ। चुनाव बहिष्कार की राजनीति का केंद्र रही जमात-ए-इस्लामी के कई नेता भी मतदान केंद्रों में नजर आए। अब सभी विस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं।

पर्यटन का नया केंद्र

लगभग 2.5 करोड़ पर्यटकों के आगमन का रिकार्ड मौजूदा वर्ष में बनने की उम्मीद है। बीते वर्ष 2.11 करोड़ पर्यटक आए थे। प्रदेश में 75 नए आफबीट पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। गुलमर्ग गंडोला की बीते वर्ष 10 लाख पर्यटकों ने सैर की और 100 करोड़ का राजस्व सरकारी खजाने को मिला। 400 फिल्मों और वेब-सीरीज की शूटिंग पांच वर्ष में कश्मीर में हो चुकी है। श्रीनगर को शिल्प नगरी का दर्जा मिला है।

जम्मू-कश्मीर में अब सभी 890 केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। पांच अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर में 1947 में पाकिस्तान से आकर बसे नागरिकों को नागरिकता का अधिकार नहीं था। वाल्मिकी समुदाय, गोरखा समाज और देश के अन्य भागों से रोजी-रोटी कमाने के लिए आकर बसे नागरिक भी कई मौलिक अधिकारों से वंचित थे। अनुच्छेद 35ए के निरस्तीकरण ने उन्हें मौलिक अधिकार दिलाए। अधिवास प्रमाणपत्र की व्यवस्था शुरू की गई है। पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में बसे नागरिकों के अलावा 1965 के नागरिकों को आवंटित भूमि का मालिकाना हक भी मिला है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं था, पर अब इसमें 45 जातियां शामिल हैं। पहाड़ी कबीला समुदाय, गड्डा ब्राहमणों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। ओबीसी को नगर निकायों व पंचायतों में आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। अनुसूचित जातियों के लिए भी कोटा है। प्रदेश में विस सीटों की संख्या 90 हो गई है जिनमें से 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में हैं।

नौकरियों में सिफारिश और चोर दरवाजा बंद हो चुका है। वर्ष 2019 के बाद 38384 सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों को मिली हैं। 4100 राजपत्रित कैडर के अफसरों की भर्ती हुई है। छह माह में सात हजार और पदों को फास्ट ट्रैक पर भरने की तैयारी है। पुलिस में दो महिला व दो सीमांत वाहिनियां गठित की गई है। कांस्टेबल स्तर पर चार हजार रिक्तियां अगले चार माह में भरी जाएंगी। हर दूसरे जिले में एक मेडिकल कालेज है। दो एम्स और दो कैंसर संस्थान हैं। दो आइआइटी, दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।

****

कह कर रहेंगे माधव जोशी

2013 के वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने कहा है कि ऐसा कोई भी बदलाव, जो वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रकृति को बदलता है या सरकार या किसी व्यक्ति के लिए उन्हें हड़पना आसान बनाता है, कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 5 अगस्त, 2024

'वक्फ' की अनियमितताएं दूर करना चाहती है सरकार

दावा ▶ उप्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, मुस्लिम संगठनों ने सरकार से किया है हस्तक्षेप का अनुरोध

संपत्ति पर कब्जा के एवज में मुआवजा न देने की शिकायत

नई दिल्ली, आइएएनएस : भाजपा ने रविवार को कहा कि वक्फ की संपत्तियों में कई अनियमितताएं हैं, जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है। वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार को वक्फ संपत्तियों की अनियमितताओं को दूर करना होगा और लोगों को उनका उचित हिस्सा देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है और वह ऐसे सभी कदम उठाएगी, जो लोगों और अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी हो।

भाजपा नेता ने कहा कि विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने सरकार को प्रतिवेदन देकर संपत्ति विवाद के मामलों में हस्तक्षेप करने को कहा है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वक्फ ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और दूसरे पक्ष को पूरा मुआवजा नहीं दिया है। सरकार को उन लोगों की शिकायतों का समाधान करना होगा, जिनकी संपत्ति वक्फ ने अपने कब्जे में ले ली है। उन्होंने कहा कि हमें पीड़ित पक्ष की भी बात सुननी चाहिए। उन्हें भी अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। जो कोई भी न्याय चाहता है, वह अदालतों में जा सकता है।

दिनेश शर्मा। फाइल

पीड़ित पक्ष की भी बात सुननी चाहिए उन्हें भी अपनी बात कहने का हक

वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता छीनना चाहती है सरकार : ओवैसी

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्डों की 'अनियंत्रित' शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक लाए जाने की खबरों के बीच एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है। उसने अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड को खत्म करने का प्रयास किया है। बता दें कि वक्फ की संपत्तियों पर यदा-कदा विवाद होते रहते हैं।

असदुद्दीन ओवैसी। फाइल

मोदी सरकार की कोशिश को मिल रही वाहवाही

नई दिल्ली, आइएएनएस : वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार की कोशिश को इंटरनेट मीडिया ने खूब सराहा है। कई इंटरनेट यूजर्स ने एक्स पर इस फैसले के पक्ष में अपनी राय देते हुए कहा कि वह इस मनमाने कानून को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में देखते हैं। एक यूजर ने वक्फ एक्ट में संशोधन के बजाय इसे पूरे तरीके से खत्म करने की पैरवी कर डाली।

ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा हलचल रहेगी। यह फैसला भी ऐसे समय में आने जा रहा है जब दो महीने बाद ही महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में भी दस विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होने हैं। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में ही नहीं इंटरनेट मीडिया में भी हलचल मचा दी है। लोगों का मानना है कि कांग्रेस सरकार ने इस कानून के जरिये समुदाय विशेष को मनमानी ताकतें दे दी हैं। भाजपा नेता अनिला सिंह ने एक्स पर कहा, 'वक्फ की ताकत को सीमित करने का यह बड़ा कदम है। मोदी कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। हम उसका स्वागत करते हैं। वक्फ एक्ट को सशक्त करके राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे थे और देश की बहुसंख्यक आबादी को निशाना बनाया जा रहा था।' एक अन्य नेटिजन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'क्या आपको पता है कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते भारत में जमीनों का तीसरा सबसे बड़ा मालिकाना हक या कब्जा वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ताकतों को सीमित करने के लिए संसद में मोदी सरकार 'वक्फ बोर्ड संशोधन बिल' लेकर आएगी।'

▶ इंटरनेट पर यूजर्स ने वक्फ को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बताया

▶ एक यूजर ने वक्फ एक्ट को पूरे तरीके से खत्म करने की पैरवी कर डाली

सरकार के पक्ष में एक्स पर खूब आ रही हैं टिप्पणियां। प्रतीकात्मक

एक्स पर एक अन्य यूजर ने एक और कदम आगे बढ़कर लिखा, 'वक्फ बोर्ड कानून का सिर्फ संशोधन काफी नहीं होगा, बल्कि उसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए। तुष्टीकरण जारी है, वोट बैंक की राजनीति जारी है।' सरकार के कदम की सराहना करते हुए एक्स पर यूजर वीरेंद्र शर्मा ने लिखा, 'भारत में जमीनों का सबसे ज्यादा स्वामित्व रखने वालों में वक्फ बोर्ड तीसरे स्थान पर है। संशोधन बिल एक बार पास होते ही वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को बतौर वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ से अधिक की भू-संपत्ति है।' एक अन्य एक्स यूजर ने कहा, 'इस तानाशाही भरे वक्फ बोर्ड कानून के चलते किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा सकता है। 1995 का यह चरम सेक्युलर राजनीति का नतीजा है। लुटियंस मीडिया इस खतरे को छिपाती रही।'

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी वक्फ की 123 विवादित संपत्तियों की जांच का दिया था आदेश

प्रथम पृष्ठ से आगे

गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली की 123 ऐसी ही विवादित संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया था। प्रस्तावित विधेयक इसी सत्र में लाया जा सकता है और अगर यह पारित हो गया तो वक्फ बोर्ड बिना सत्यापन किसी भी संपत्ति पर अधिकार घोषित नहीं कर सकेगा। वक्फ बोर्ड कई बार ऐसे दावे करता रहा है, जिससे विवाद हुआ। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर अपना हक होने का दावा किया, जहां सदियों से बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती थी। अधिनियम में संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि दावे से पहले प्रत्येक संपत्ति के सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य की जा सकती है।

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो उसके लिए सिर्फ इतना सोचना ही काफी है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को किसी सुबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वक्फ बोर्ड यह मान ले कि कोई संपत्ति उसकी है तो संपत्ति का मालिक कोर्ट भी नहीं जा सकता। हालांकि, वह वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

क्या है वक्फ

वक्फ अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रख-रखाव और उनका प्रबंधन करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ निकाय हैं।

क्या है वक्फ एक्ट 1954

वर्ष 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट, 1954 पास किया गया। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रख-रखाव तक को लेकर प्रविधान हैं। एक्ट के प्रविधानों के मुताबिक वर्ष 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई।

अंग्रेजों ने वक्फ बताया था अवैध

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं हैं। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि यह लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में चार जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना था और 1913 में नया एक्ट लाई।

जदयू में शामिल हुए विधायक सरयू राय

सरयू राय। फाइल

राज्य ब्यूरो,जागरण, रांची: भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक और जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय रविवार को जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल हो गए। वे अपने दल भारतीय जनतंत्र मोर्चा का जदयू में विधिवत विलय भी करेंगे। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण सरयू राय ने पार्टी छोड़ दी थी फिर जनतंत्र मोर्चा बनाया था।। मालूम हो कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्व से चुनाव भी हराया था। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना में उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। सरयू राय ने हाल के दिनों में कई बार पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने भी इच्छा जताई थी कि सरयू राय जदयू में शामिल होकर झारखंड में संगठन का विस्तार करें।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज का तंज, जो वोट के लिए अहमद बन गए वह क्या बोलेंगे

जागरण संवाददाता, बेगूसराय

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो वोट के लिए अहमद बन गए वह क्या बोलेंगे। जो चोर हैं, उसे सारे लोग चोर ही नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे ने तो मुस्लिम वोट के लिए अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की विरासत और उनके संस्कार को मिट्टी में मिला दिया। बिहार के बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय कपड़ा मंत्री रविवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह पर उद्धव ठाकरे द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर वह खासे नाराज दिखे।

केंद्रीय मंत्री ने अयोध्या में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद अखिलेश यादव एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। कहा कि अयोध्या में एक बेटी के साथ जो हुआ, वह बहुत ही शर्मनाक है। फिर भी इस तरह की शर्मनाक घटना पर ये सभी नेता कुछ नहीं बोले, क्योंकि

▶ राहुल, अखिलेश व तेजस्वी पर भी जमकर बरसे, ममता की तुलना किम जोंग से की

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। जागरण

आरोपित मुसलमान है। सवालिए लहजे में कहा कि जब देश के सनातनियों पर चोट करनी होती है, तब वह सब एकजुट होकर बोलते हैं। आज राहुल गांधी सहित उन सभी नेताओं की जुबान क्यों बंद है?

केंद्रीय मंत्री ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग करार देते हुए कहा कि वह तानाशाह के समान व्यवहार करती हैं। इसलिए उनके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। खुले में मीट बेचने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर पूरे देश में रोक लगनी चाहिए ताकि सनातन धर्म को मानने वालों को विपरीत स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

लाल झंडा देख वाहन छोड़ बाइक से निकले गिरिराज : बिहार जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलनरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनकर्मियों ने रविवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के काफिले को कैंटीन चौक के समीप रोकने का प्रयास किया। काफिला नहीं रुका तो झंडा लेकर सड़क किनारे खड़े कर्मी जुलूस की शक्ल में कार्यक्रम स्थल पहुंच गए, कार्यक्रम खत्म होते ही हाथों में झंडा लिए कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री के वाहन का घेराव कर दिया। यह देख केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित वार्ड पार्षद की बाइक पर बैठ भाजपा जिला कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने चले गए। सांसद के बाइक से निकल जाने की खबर मिलते ही कर्मी आक्रोशित हो गए और नारेबाजी की।

अजा-जजा आरक्षण का बंटवारा अनुचित, असंवैधानिक : मायावती

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

बसपा प्रमुख मायावती ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमति जताई है। बसपा प्रदेश मुख्यालय में रविवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि हमारी पार्टी शीर्ष न्यायालय के फैसले से पूरी तरह से असहमत है। आरक्षण का बंटवारा अनुचित और असंवैधानिक है। अनुसूचित जाति व जनजाति का उपवर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 2004 में फैसला सुनाया था, तब उन्होंने वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी थी। अब फैसला पलट दिया गया है। बसपा प्रमुख ने एनडीए सरकार के साथ-साथ कांग्रेस को भी कठघरे में खड़ा किया। आरोप लगाया कि इन्होंने सही पैरवी नहीं की।

मायावती ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस बिंदु पर भी विचार नहीं किया कि अनुसूचित जाति व जनजाति में किन लोगों को क्रीमीलेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और इसका मानक क्या होगा।

▶ बसपा प्रमुख ने कहा- कोर्ट के जरिये आरक्षण को खत्म करने की कोशिश, निर्णय पर पुनर्विचार करे शीर्ष कोर्ट

मायावती। फाइल

इस निर्णय से असंतोष की भावना पैदा होगी। इससे केंद्र व राज्य सरकारों के बीच भी टकराव बढ़ेगा। राज्य सरकारें अपने वोट बैंक के लिए मनचाही जातियों को आरक्षण का लाभ देंगी। एससी और एसटी को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। यह वर्ग आरक्षण से वंचित हो जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट से यही कहेंगे कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। बसपा प्रमुख ने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों ने ऐसी दलील दी कि जिससे मौजूदा चल रहे आरक्षण के विरुद्ध निर्णय आए। जाहिर है ये लोग आरक्षण को खुद न खत्म कर, न्यायपालिका के माध्यम से खत्म करना चाह रहे हैं। इससे भाजपा, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी को आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भी कहा कि यदि भाजपा की नीयत साफ है तो वह संसद में संविधान में संशोधन करे और इस फैसले को पलटे। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार व आइएनडीआइए गठबंधन से भी एससी व एसटी आरक्षण को पहले से बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाने और इनके आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखने की मांग की। मायावती ने एससी व एसटी वर्ग के लोगों से भी अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने की अपील की। कहा कि आपातकालीन स्थिति को समझते हुए एकजुट हो और सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डालकर उन्हें संवैधानिक संशोधन के लिए मजबूर करें।

'चुनावों को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा झूठा अभियान'

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनावों को बदनाम करने के लिए झूठा अभियान चलाया जा रहा है। आयोग ने उस रिपोर्ट को को खारिज कर दिया, जिसमें लोकसभा चुनाव में शुरुआत में घोषित मतदान प्रतिशत के आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों के बीच असामान्य रूप से बड़ा अंतर होने की बात कही गई थी।

चुनाव आयोग का यह बयान कांग्रेस द्वारा शनिवार को 'वोट फार डेमोक्रेसी' की रिपोर्ट का हवाला देने के एक दिन बाद आया है, जिसमें लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि के बारे में सवाल उठाए गए हैं और चुनाव आयोग से चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया गया है। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया, मानव इतिहास में अब तक के सबसे पारदर्शी तरीके से हुए सबसे बड़े चुनावों को बदनाम करने के लिए झूठा अभियान चलाया जा रहा है। मतदान के दिन शाम साम बजे के अनुमानित मतदान प्रतिशत की तुलना वोटिंग के एक दिन बाद उपलब्ध मतदान प्रतिशत से करने का निराधार प्रयास किया गया है।

▶ लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर उठे सवालों को किया खारिज

▶ कहा- चुनावी डाटा और नतीजों में किया गया प्रक्रियाओं का पालन

चुनावी डाटा और नतीजों में पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। किसी प्रत्याशी या निर्वाचक द्वारा परिणाम को चुनौती देने का वैध तरीका चुनाव याचिका है, लेकिन कथित तौर पर ऐसे आधार पर कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती है। चुनाव याचिका (ईपी) नतीजों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। चुनाव आयोग ने कहा कि 2019 के संसदीय चुनावों में 138 ईपी की तुलना में 2024 में 79 सीटों पर ईपी दाखिल किए गए हैं।

कर्नाटक एमयूडीए घोटाले के खिलाफ यात्रा से सीएम भयभीत : विजयेंद्र

रामनगर, प्रेट्र: कर्नाटक में विपक्षी दल भाजपा और उसकी सहयोगी जदएस ने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण स्थल (एमयूडीए) आवंटन घोटाले के खिलाफ रविवार को दूसरे दिन भी बेंगलुरु से मैसुरु तक सात दिवसीय मार्च जारी रखा। इस दौरान दोनों दलों ने कांग्रेस सरकार एवं सिद्दरमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम भयभीत हैं। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू की गई 'मैसुरु चलो' पदयात्रा दूसरे दिन बिदादी से शुरू हुई और 22 किलोमीटर की दूरी तय कर कैंगल पहुंची है।

भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष एवं विधायक बीवाई विजयेंद्र, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, दोनों दलों के कई विधायक, नेता और कार्यकर्ता रविवार को बिदादी से शुरू हुए मार्च में शामिल हुए। विजयेंद्र ने मार्च से पहले सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस, सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार विपक्ष के विरोध मार्च के बाद भयभीत हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि भाजपा और जदएस की यह यात्रा उनके 'उनके पापों से मुक्ति' की यात्रा है।

शिअद की नई कोर कमेटी में एसजीपीसी अध्यक्ष धामी व सरना को भी मिली जगह

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

शिरोमणि अकाली दल ने 23 जुलाई को कोर कमेटी भंग करने के बाद रविवार को 23 सदस्यीय नई कोर कमेटी की घोषणा कर दी है। इसमें एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर धामी को भी जगह मिली है। उनके अलावा बलविंदर सिंह भूंदड़, नरेश गुजराल, परमरजीत सिंह सरना, मंजीत सिंह जीके भी शामिल किए गए हैं। कमेटी में चार विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इनमें मौजूदा सांसद के अलावा यूथ अकाली दल के प्रधान, स्त्री अकाली दल की नेता और शिअद लीगल विंग के प्रधान शामिल हैं। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल की अध्यक्षता में वर्किंग कमेटी की हुई बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद वरिष्ठ नेता डा. दलजीत सिंह चीमा ने इसकी जानकारी इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा की।

बता दें कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते

▶ कोर कमेटी में परमजीत सरना, जीके, गुजराल व भंडड़ भी शामिल

▶ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बगावत के बाद भंग की गई थी कोर कमेटी

हरजिंदर धामी। फाइल

परमरजीत सिंह सरना। फाइल

शिअद के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रधान के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। इनमें प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, बीबी जगीर कौर, परमिंदर सिंह ढींडसा प्रमुख थे और ये सभी शिअद की कोर कमेटी के सदस्य भी थे। बागी गुट की ओर से श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश होकर पूर्व में पार्टी की ओर से की गई गलतियों के लिए माफीनामा भी अकाल तख्त के जत्थेदार को सौंपा था। इसके बाद 15 जुलाई को पांचों तख्तों के जत्थेदार ने शिअद प्रधान को 15 दिन के अंदर श्री अकाल तख्त के सामने पेश होने का आदेश दिया था। श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश होने से पहले शिअद प्रधान ने 23 जुलाई को कोर कमेटी को भंग कर दिया और अगले दिन वे श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए थे। उधर, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी ने 30 जुलाई को बागी गुट के आठ सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। निष्कासित सदस्यों में प्रो. चंदूमाजरा, बीबी जगीर कौर, गुरप्रताप सिंह वडाला, परमिंदर सिंह ढींडसा, सिकंदर सिंह मलूका, सुरजीत सिंह रखड़ा, सुरिंदर सिंह ठेकेदार और चरणजीत सिंह बराड़ शामिल थे। अगले दिन जब पार्टी के संरक्षण सुखदेव सिंह ढींडसा ने बागी गुट के निष्कासन को रद करने की घोषणा की तो पार्टी ने उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

केंद्र और बिहार सरकार आरक्षण विरोधी : तेजस्वी

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना : आरक्षण की सीमा 65 प्रतिशत करने पर कोर्ट की रोक के बाद भी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव केंद्र और बिहार की राजग सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। रविवार को उन्होंने एक बार फिर कहा कि केंद्र और बिहार सरकार आरक्षण विरोधी है, इसलिए बिहार में हमारी सरकार द्वारा दिए गए 65% आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने 17 वर्षों के कार्यकाल में बिहार के लिए कोई काम नहीं किया।

तेजस्वी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि 17 महीने के अपने अल्प कार्यकाल में हमने देश में पहली बार जातिवार गणना कराई और गणना की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत तक किया। लेकिन, एनडीए सरकार ने आरक्षण की बढ़ी सीमा पर रोक लगवा दी। हम सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक न्याय और उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। यहीं वजह है कि अपनी इच्छाशक्ति के बल पर पांच लाख युवाओं को नौकरी दी।

दावेदारी का दांव

विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए सर्वे कर रही एजेंसियों के प्रतिनिधि कर रहे दावेदारों से संपर्क, सर्वे में नाम ऊपर-नीचे कराने के नाम पर टिकट के दावेदार नेताओं से साधा जा रहा संपर्क

हरियाणा में कांग्रेस की सर्वे एजेंसियां नेताओं के साथ कर रही खेल

अनुराग अग्रवाल ● जागरण

चंडीगढ़ : हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकटों के लिए सर्वे कर रही एजेंसियां दावेदार नेताओं के साथ खेल करने में लगी हैं। इन सर्वे एजेंसियों के प्रतिनिधि दावेदार नेताओं से न केवल फोन पर संपर्क साध रहे हैं, बल्कि गोपनीय स्थानों पर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। खेल यह है कि टिकट के दावेदार नेताओं को कहा जा रहा है कि सर्वे में उनका नंबर दूसरे अथवा तीसरे स्थान पर है। इसे पहले स्थान पर लाया जा सकता है, बशर्ते कि उनकी बात मान ली जाए। टिकट के कुछ दावेदार सर्वे में पहले नंबर पर होने के लिए एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बात मान रहे हैं तो कुछ उन्हें नजरअंदाज भी कर रहे हैं।

सर्वे एजेंसियों के इस खेल का तब पता चला, जब जीटी रोड पर करनाल के एक टूरिस्ट परिसर में एक ही समय दो दावेदार सर्वे प्रतिनिधि से मिलने पहुंच गए। इन दोनों दावेदारों को सर्वे एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अलग-अलग समय में फोन कर कहा कि लोगों से हुई बातचीत व सर्वे के आधार पर उनका नंबर दूसरे व तीसरे स्थान पर है, जिसे पहले स्थान पर किया जा सकता है। टूरिस्ट परिसर में मुलाकात का समय निर्धारित होने से पहले टिकट के इन दोनों दावेदारों में आपसी समझदारी से एक-दूसरे से बात कर ली और सर्वे एजेंसी के प्रतिनिधि की इस बात को आपस में साझा कर लिया कि उनका नंबर दूसरे स्थान पर है, जिसे पहले स्थान पर कराया जा सकता है।

90 विधानसभा सीटों पर अब तक 2300 आवेदन, 10 अगस्त से आगे बढ़ाई जा सकती है अंतिम तारीख

सर्वे में भी तिकड़मी खेल। प्रतीकात्मक >>

करनाल से कांग्रेस के टिकट के दावेदार इन दोनों नेताओं की सर्वे एजेंसी के प्रतिनिधि से हुई बातचीत के अंश जब आपस में मिले-जुले नजर आए तो दोनों ने मिलने का समय निर्धारित कर लिया। एक प्रतिनिधि का समय शाम चार बजे तय हुआ तो दूसरा वहां अचानक पहुंच गया, जिसे देखकर सर्वे एजेंसी के प्रतिनिधि हक्का बक्का रह गए। कांग्रेस के बड़े नेताओं से सर्वे एजेंसी के इस असलियत को साझा किया गया तो पता चला कि ऐसी शिकायतें बाकी कुछ जिलों से भी आई हैं। हरियाणा में कांग्रेस का टिकट प्राप्त करने के लिए पार्टी नेताओं में जबरदस्त तरीके से मारामारी मची हुई है। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर अब तक करीब 2300 आवेदन आ चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त है, जिसे 15 अगस्त तक भी बढ़ाया जा सकता है। आवेदन करने के बाद से टिकट के दावेदार कई नेता यह खोजने में जुट गए थे कि सर्वे करने वाली एजेंसी कौन-सी है। कुछ नेताओं को एजेंसी के प्रतिनिधियों ने खोज लिया। प्रदेश में कांग्रेस का चार तरह का सर्वे चल रहा है। पहला सर्वे कांग्रेस हाईकमान द्वारा अधिकृत एजेंसी कर रही है। दूसरा सर्वे हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से कराया जा रहा है। एक सर्वे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी कर रही है तो एक सर्वे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की कमेटी कर रही है। सर्वे एजेंसियों के प्रतिनिधियों के इस खेल से टिकट के वास्तविक दावेदार नेताओं में सर्वे से भरोसा उठ गया है।

****

मनोहर लाल के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी से थाने में पूछताछ

जागरण संवाददाता, शिमला

▶ राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला

राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी से हिमाचल प्रदेश की शिमला पुलिस ने रविवार को बालूगंज थाने में पूछताछ की। तरुण भंडारी रविवार दोपहर थाने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक जांच के लिए गठित एसआइटी ने उनसे कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों की हेलीकाप्टर यात्रा और पंचकूला के होटल में रहने-खाने के खर्च उठाने से संबंधित प्रश्न किए। एसआइटी भंडारी को पूछताछ के लिए दोबारा भी तलब कर सकती है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद भंडारी दूसरी बार पुलिस के सामने पेश हुए।

इसी मामले में एसआइटी गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा व उनके पिता सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी व उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा, लाहुल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा से भी पूछताछ कर चुकी है। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह व तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था। हर्ष व कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को 34-34 मत मिले थे। पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम में हर्ष को विजेता घोषित किया गया था। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी व भुवनेश्वर गौड़ की शिकायत पर 10 मार्च को मामला दर्ज किया गया था।

1.54 लाख एकड़ भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार में कब्जों से मुक्त कराया गया है। साथ ही 2,464 कब्जेदारों को चिह्नित कर 187 भूमाफिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आरोपितों ने सुलह के लिए रुपयों का दिया था लालच

अयोध्या दुष्कर्म प्रकरण ▶ पीड़िता की मां ने एक चैनल से बातचीत के दौरान लगाया आरोप, श्मशान भूमि पर भी आरोपित का कब्जा

पीड़िता व उसकी मां से मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल, आर्थिक सहायता दी

जागरण संवाददाता, अयोध्या

नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म प्रकरण को लेकर रविवार को भी अयोध्या में सरगर्मी बनी रही। इस प्रकरण में एक नया तथ्य यह प्रकाश में आया है कि आरोपितों ने धमकी देने से पहले पैसे लेकर सुलह का दबाव बनाया था। आरोपित की बेकरी पर शनिवार को बुलडोजर चलाए जाने के बाद उसकी अन्य संपत्तियों को भी चिह्नित किया जा रहा है। श्मशान भूमि पर भी उसका अवैध कब्जा पाया गया है। रविवार को भदरसा चौकी के एक अन्य सिपाही रोहित यादव को भी लाइनहाजिर कर दिया गया। इस बीच भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल ने पीड़िता और उसकी मां से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार पीड़िता को न्याय दिलाएगी।

भाजपा का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार दोपहर करीब एक बजे पीड़िता के गांव पहुंचा। इसमें

अयोध्या में रविवार को उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचे। प्रेट्र

नरेंद्र कश्यप के साथ राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद व एमएलसी संगीता बलवंत शामिल थीं। उन्होंने पीड़िता की मां से भेंट की, उन्हें ढांढ़स बंधाया और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इसके बाद उस अस्पताल में पहुंचे, जहां पीड़ित किशोरी भर्ती थी। उससे मुलाकात की और उपचार आदि की जानकारी ली। वहां से सर्किट हाऊस आकर कश्यप ने पत्रकारों से कहा कि पीड़ित परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। हमने डीएम व एसएसपी से भी पूरी रिपोर्ट ली है। रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगे।

कश्यप ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा डीएनए व नार्को टेस्ट की मांग किए जाने को गलत ठहराया। कहा कि मुख्य आरोपित मोईद खान सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है।

सपा ने अब तक उसे पार्टी से निकाला भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि पार्टी उसका बचाव कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती के सरकार की कार्रवाई का समर्थन किए जाने के सवाल पर उनका कहना था कि योगी सरकार ने कदम ही ऐसा उठाया है कि सभी लोगों को सराहना करनी चाहिए।

रविवार को इन सब घटनाक्रमों के बीच पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि गुरुवार की रात अस्पताल में भर्ती उनकी बेटी को सपा नेता व नगर पंचायत अध्यक्ष मो.राशिद व सपा नेता जय सिंह राणा ने समझौता करने के लिए पैसों का लालच भी दिया था। उसके बाद में जान से मारने की धमकी दी गई। दुष्कर्म पीड़िता की मां ने यह बात एक चैनल से बात करते हुए कही। हालांकि, इस प्रकरण में उपरोक्त दोनों सपा नेताओं के अलावा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने का मामला पूराकलंदर पुलिस बीते शुक्रवार को ही दर्ज कर चुकी है।

पुलिस-प्रशासन आरोपित की अन्य संपत्तियों के परीक्षण में भी जुटा है। एसडीएम अशोक कुमार सैनी ने बताया कि श्मशान की भूमि पर भी आरोपित का अतिक्रमण पाया गया है। श्मशान भूमि करीब 630 वर्ग मीटर है, जिसमें 200 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जा है। इस पर दुकानें और पुलिस चौकी बनी है। जांच में आरोपित पक्ष की ओर से कोई संतोषजनक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

सांप्रदायिक उपद्रव में भी आ चुका है दुष्कर्म आरोपित सपा नेता का नाम

दुष्कर्म के आरोपित सपा नेता मोईद का दामन सांप्रदायिक उपद्रव में भी दागदार रहा है। यह उपद्रव वर्ष 2012 में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन भदरसा में हुआ था, जिसमें दुर्गा प्रसाद गुप्त की हत्या कर दी गई थी। मामले में 13 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें मोईद खान का भी नाम शामिल है। दुष्कर्म के बाद मोईद का आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस ने इस उपद्रव की फाइल भी पलटना शुरू कर दिया।

दुष्कर्म का आरोपित मोईद खान। सौ. पुलिस

ममता के मंत्री को महिला अधिकारी से दुर्व्यवहार पड़ा महंगा, देंगे इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- **अखिल गिरि ने महिला वन अधिकारी को धमकाते हुए डंडे से पीटने की बात कही थी**
- **भाजपा ने मुख्यमंत्री से मंत्री की गिरफ्तारी के साथ उन्हें मंत्रिमंडल से निकालने की मांग की थी**

ममता सरकार के जेल मंत्री अखिल गिरि को महिला वन अधिकारी से दुर्व्यवहार करना महंगा पड़ गया। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा है। मंत्री ने कहा है कि वह विधानसभा में पार्टी नेतृत्व को इस्तीफा पत्र सौंप देंगे। इस दौरान वह मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष भी रखेंगे। बता दें कि शनिवार को पूर्व मेदिनीपुर के ताजपुर समुद्र तट से अतिक्रमण हटाने से अखिल गिरि इस कदर आगबबूला हो गए थे कि उन्होंने एक महिला वन अधिकारी को जानवर और बदतमीज कहने के अलावा डंडे से पीटने की तक की बात कह दी थी। इस घटना के बाद भाजपा ने सीएम से मंत्री की गिरफ्तारी के साथ उन्हें मंत्रिमंडल से निकालने की मांग की थी। बंगाल में ममता बनर्जी के 13 साल के शासनकाल में अखिल गिरि पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है।

टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने दुर्व्यवहार के मामले में जेल मंत्री को पूर्व मेदिनीपुर के कांथी रेंज की वन अधिकारी मनीषा साव से माफी मांगने को कहा है। वह माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।

इसके बाद अखिल गिरि ने कहा कि तीखी नोकझोंक के दौरान आवेश में आकर उन्होंने महिला अधिकारी को कुछ गलत बातें कह दी थीं, लेकिन महिला अधिकारी से माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता।

दूसरी तरफ मंत्री के इस्तीफे पर भाजपा के राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि अखिल के खिलाफ सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप दर्ज किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री ने राष्ट्रपति के रंग-रूप पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसके बाद भी वह मंत्रिमंडल में बने रहे।

गिरि ने महिला अधिकारी वन अधिकारी मनीषा साव से कहा था कि आप सरकारी कर्मचारी हैं। बोलते वक्त सिर झुका कर बात करें। यही नहीं मंत्री ने यह कहकर धमकाया कि अगर आपने इस मामले में दोबारा दखल देने की कोशिश की तो वह यह सुनिश्चित करेंगे आप सही सलामत न लौट सकें।

बरेली में हिंदुओं का मतांतरण कराने का आरोप, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बरेली : बरेली जिले में ईसाई मिशनरी का प्रचारक ईश्वरी प्रसाद हिंदुओं को प्रलोभन देकर मतांतरण करा रहा था। रविवार दोपहर इसकी सूचना पर बिहिप के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बुला ली। आरोपित ईश्वरी प्रसाद को मौके से गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध प्रलोभन एवं धोखा देकर मतांतरण कराने की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। जिले के बहेड़ी में बिहिप के पदाधिकारियों को सूचना मिली कि ईश्वरी के मकान में धार्मिक सभा की आड़ में हिंदुओं का मतांतरण कराया जा रहा। इसकी पुष्टि होने पर उन्होंने इंस्पेक्टर प्रवीण सोलंकी को भी बुला लिया। इसके बाद मकान का दरवाजा खुलवाया गया तो ईसाई धर्म प्रचारक ईश्वरी प्रसाद भागने लगा, लेकिन पकड़ा गया। अंदर 50 से अधिक महिला, पुरुष एवं बच्चे थे। उनमें कई महिलाओं ने स्वीकारा कि प्रलोभन देकर बुलाया गया था। उनसे कहा गया था कि धार्मिक सभा में शामिल होने पर कई लाभ दिए जाएंगे। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित ईश्वरी प्रसाद हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। उन्हें प्रलोभन दे रहा था।

संभल में धमकियों से तंग वाल्मीकि परिवार ने लगाए पलायन के पोस्टर

जागरण संवाददाता, संभल

- **मुस्लिम बहुल गांव में रहता है अकेला वाल्मीकि परिवार, दो माह से चल रही तनातनी**

उत्तर प्रदेश में संभल के मुस्लिम बहुल गांव में रहने वाले अकेले वाल्मीकि परिवार ने पलायन की चेतावनी दी है। इस संबंध में रविवार को अपने मकान की दीवार पर पोस्टर भी लगा दिया। परिवार का आरोप है कि पिछले महीने एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लिखवाने पर हसनैन व उसके साथी रंजिश मान बैठे। आरोपित पक्ष के लोग लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं और धमकियां दे रहे। ऐसी स्थिति में गांव में रहना संभव नहीं है। जानकारी पर दोपहर को थानाप्रभारी रेनू सिंह पीड़ित परिवार से बात करने पहुंचीं। उन्हें भरोसा दिया कि धमकाने वालों पर कार्रवाई होगी।

नहरोली गांव की पीड़ित मुन्नी ने बताया कि दूसरे संप्रदाय के कुछ लोग काफी समय से परेशान कर रहे हैं। दो महीने पहले उनके पति पर गोहत्या का आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास हुआ था। उस समय जांच में पुष्टि नहीं होने पर पुलिस ने छोड़ दिया। 11 जून को गांव के ही हसनैन, रिजवान, जीशान, छिद्दू और इकराम ने घर पर धावा बोल दिया। घर में अकेली बेटी से मारपीट की। उसी दिन सभी आरोपितों पर मारपीट, एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी पंजीकृत कराई, लेकिन इसके बाद तनाव बढ़ता गया। आरोपित पक्ष के लोग समझौते का दबाव बना रहे। उनकी धमकियों के कारण घर से निकलने में डर लगता है। गांव में हमारे अलावा सभी परिवार मुस्लिम हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में रहना संभव नहीं, इसलिए पलायन कर जाएंगे। थानाप्रभारी रेनू सिंह ने बताया कि मुन्नी व उनके परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया है।

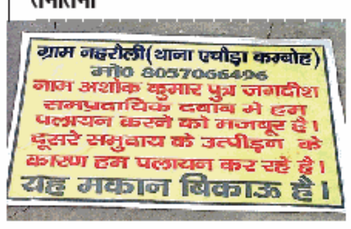

संभल के गांव नहरौली में अशोक कुमार के घर के आगे लगा मकान बिकाऊ का बैनर। जागरण

मेरठ जिले में पालीथिन न देने पर चाय विक्रेता के पुत्र की हत्या

जागरण संवाददाता, मेरठ : मेरठ जिले में पालीथिन न देने पर सात युवकों ने सरेबाजार चाय विक्रेता के पुत्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। भीड़ ने एक आरोपित तरुण को पकड़ लिया। अन्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने जाम लगाकर थाने का घेराव किया। फरार सभी हमलावर मुस्लिम बताए गए हैं। जिले के मवाना में किला बस स्टैंड पर विनोद सेन की चाय की दूकान है। दोपहर में उनके घर जाने पर उनका 26 वर्षीय बेटा रोहित चाय बना रहा था। दोपहर तीन बजे फारूक, उसका भाई, समीर, फैजान, तरुण व दो अज्ञात युवक आए। इन युवकों ने रोहित से पालीथिन मांगी। इन्कार करने पर विवाद हो गया। आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए रोहित की पीठ व गर्दन पर चाकुओं से कई प्रहार कर दिए। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। बस अड्डे व बाजार में अफरा-तफरी मच गई। भीड़ आती देख हमलावर भागने लगे। लोगों ने पीछा कर आरोपित तरुण को पकड़ लिया। रोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

घर की दीवार पर लिखे मिले पाक समर्थन में नारे, एजेंसियां सक्रिय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- **घंटों पूछताछ व जांच के बाद पाया कि मकान मालिक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं**

रोहिणी के अवंतिका सी-ब्लाक में एक मकान की दीवार पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे की जानकारी सार्वजनिक होते ही हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इंटेलीजेंस ब्यूरो समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि मकान मालिक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने मनोचिकित्सकों की निगरानी में रखने के लिए उसे अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल देश-विरोधी गतिविधियों का कोई एंगल सामने नहीं आया है।

अवंतिका सी-ब्लाक स्थित एक मकान की दीवार पर देश-विरोधी नारे लिखे होने की सूचना के बाद रविवार को कुछ युवक मौके पर पहुंचे। युवकों ने घर की दीवारों पर लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और पूरे मकान का वीडियो बनाया और इसके मालिक को पाक का स्लीपर सेल बताया। इसके बाद यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।

नई दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में अवंतिका सी-ब्लाक स्थित मकान की दीवार पर पाकिस्तान समर्थन में लिखा नारा। वीडियो ग्रैब

प्रसारित वीडियो की जानकारी के बाद रोहिणी जिले के विजय विहार थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और पूरे मकान की छानबीन की।मामला संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने मकान मालिक को पूछताछ के लिए अपने साथ ले आई। नारों को कागज पर लिखकर बाकायदा फ्रेम कराकर दीवार पर टांगा गया है। एक जगह उसने हिंसक व मार-काट की बात भी लिखी है।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में चलाएगा "हर घर तिरंगा" अभियान

नई दिल्ली, एएनआइ: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा देशभर के अल्पसंख्यक समुदाय में 11 से 14 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाएगा। इस दौरान घरों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, दरगाहों, मदरसों और अन्य धार्मिक स्थलों पर तिरंगा फहराया जाएगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने हर घर तिरंगा अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी और सह-प्रभारी की घोषणा की है। मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सैयद इब्राहिम को अभियान का राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया गया है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर इस साल भी भाजपा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 से 14 अगस्त तक देशभर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगी। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की, जिसमें मोर्चा के पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे।

झारखंड में शार्ट वीडियो बना रहे चार युवक नदी में कूदे, एक की मौत

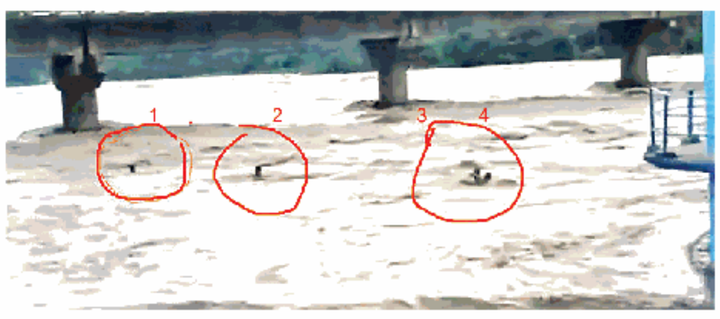

नदी में बहते चारों युवक का फाइल फोटो। सौजन्य वायरल वीडियो

जासं, तालगड़िया (बोकारो)

झारखंड के बोकारो जिले के सिलफोर के पास शार्ट वीडियो बनाने के चक्कर में पुल के ऊपर से दामोदर नदी में कूदे चार युवकों में एक की तेज धारा में बहकर मौत हो गई। मरने वाले युवक का नाम राकी था। घटना शनिवार शाम की है। नदी में बहे युवक का शव रविवार को अमलाबाद घाट के पास मिला। नदी की तेज धारा में बहते युवकों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है। उधर, राकी के स्वजन का कहना है कि वह नहाने के उद्देश्य से पुल के ऊपर से नदी में कूदा था। शार्ट वीडियो बनाने जैसी कोई बात नहीं थी। आसपास के लोगों के अनुसार ये सभी युवक सिलफोर निवासी हैं, शनिवार को गांव के मैदान में फुटबाल खेलने के बाद शाम में दामोदर नदी पर बने पुल पर घूमने गए थे। इसी दौरान चारों ने एक साथ नदी में छलांग लगा दी। चारों युवक नदी के तेज बहाव में बहने लगे। तीन युवक थोड़ी दूर जाकर किसी तरह किनारे आ गए, लेकिन एक युवक राकी आगे निकल गया और दूर जाकर गड्ढे और पत्थर के बीच फंस गया। रविवार को खोजबीन के दौरान राकी का शव मिला।

हिमाचल में अधिक बिल की शिकायतों पर निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना बंद

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला

- **सीएम सुक्खू बोले, 25 हजार में होने वाला हर्निया के आपरेशन होता था एक लाख में**
- **भाजपा सरकार ने बिना विचार किए निजी अस्पतालों में शुरू की थी योजना**

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना बंद करने पर कहा है कि उपचार के अधिक बिल की शिकायतें आने पर यह कदम उठाया गया। देखने में आया कि निजी अस्पतालों में हर्निया का आपरेशन करने पर एक लाख रुपये का बिल बन रहा था, जबकि यह 25 हजार रुपये में होता है। उन्होंने रविवार को यह बात शिमला स्थित विधानसभा पुस्तकालय में हिमाचल निर्माता डा. यशवंत सिंह परमार की जयंती पर आयोजित समारोह में पत्रकारों से बातचीत में कही।

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमकेयर योजना को बिना विचार किए निजी क्षेत्र के अस्पतालों में शुरू कर दिया था। रोगियों के उपचार में अधिक बिल बनाए जाने की शिकायतें सामने आने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। जोनल स्तर के सभी सरकारी अस्पतालों में हिमकेयर योजना को यथावत रखा है। सरकार ने योजना में कुछ सुधार करते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को चिकित्सा बिलों की सुविधा को देखते हुए हिमकेयर योजना से अलग कर दिया है। उन्होंने हैरानी जताई कि इस योजना के कारण ही प्रदेश में कई स्थानों पर निजी अस्पताल बड़ी संख्या में खुलते चले गए, जिसका परिणाम यह है कि हिमकेयर की कुल 1000 करोड़ रुपये की देनदारी में से 450 करोड़ रुपये का भुगतान निजी अस्पतालों का करना है। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने कर्मचारियों की एसीआर को परफारमेंस आधार पर भरने का निर्णय लिया है, इसी तरह का मापदंड अधिकारियों के लिए भी निर्धारित होगा। अब लक्ष्य प्राप्त करने वाले ही अधिकारी व कर्मचारी बढ़िया एसीआर के हकदार होंगे।

दो बजट में डा. परमार के विजन को धरातल पर उतारा: मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि डा. वाईएस परमार का विजन था कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाया जाए। प्रदेश सरकार ने अपने दो बजट में वह छाप छोड़ी है। सत्ता में आने के बाद सभी सरकारी विभागों में किए गए सुधारवादी बदलावों के परिणाम सामने आने लगे हैं। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को लगता था कि सुधार संभव नहीं है, लेकिन सरकार ने दृढ़ता के साथ हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने की नींव डाली है।

सत्ता में रहते भाजपा कोष लुटाती रही, हम बचा रहे : मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा सत्ता में रहते कोष को लुटाने रही, जबकि हम इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा सरकार में स्कूल खोलना ही प्राथमिकता थी, गुणात्मक शिक्षा की योजना नहीं थी। अब अनावश्यक खोले स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। यह ऐसे स्कूल हैं, जहां छात्रों की संख्या दो थी और शिक्षक अधिक थे। हमारे प्रयास से हिमाचल देश में गुणात्मक शिक्षा के मामले 18वें स्थान पर आ गया है।

विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर खाली ट्रेन के डिब्बे में लगी आग

आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में रविवार को तिरुमाला एक्सप्रेस के एक कोच में लगी आग को बुझाते अग्निशमन कर्मी। प्रेट्र

विशाखापत्तनम, प्रेट्र : विशाखापत्तनम में रविवार को एक खाली ट्रेन के डिब्बे में मामूली आग लग गई जिसे वाल्टेयर रेलवे डिवीजन के कर्मियों ने तुरंत बुझा दिया। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर कोरबा-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस (18517) ट्रेन में आग लग गई, जिससे चार खाली डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रेन के कोच में सुबह करीब 10 बजे आग लग गई। यह घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन विशाखापत्तनम स्टेशन यार्ड में सफाई के लिए खड़ी थी। रेलवे के अधिकारी ने कहा कि एक डिब्बे में आग लगने की मामूली घटना को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया। उन्होंने बताया कि यह खाली डिब्बा था। उन्होंने बताया कि घटना में कोई अन्य डिब्बा प्रभावित नहीं हुआ।

तैयारी

विपक्ष को उपचुनाव से पहले जनता को गुमराह करने का मौका न देने के लिए खुद भाजपा ने ही लटकाया विधेयक, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी प्रवर समिति की रिपोर्ट, पारित कराया जाएगा संशोधित विधेयक

उप्र में सार्वजनिक हित में अंतत : लागू होगा नजूल संपत्ति कानून

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

उप्र में विपक्ष ही नहीं 'अपनों' के विरोध के चलते भले ही विधान परिषद (उच्च सदन) में बहुमत होने के बावजूद उप्र नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक-2024 को अभी पारित नहीं कराया गया है, लेकिन योगी सरकार अंततः इस कानून को लागू करने से पीछे हटते नहीं दिखाई दे रही है। प्रदेश सरकार का मानना है कि पूर्व की सरकारों में अरबों रुपये की नजूल जमीन को कौड़ियों में फ्रीहोल्ड करने का बड़ा खेल किया जाता रहा है। इसमें लिप्त भू-माफिया से लेकर नेता और नौकरशाह ही जनहित को ढाल बनाकर अपने हितों को साधने के लिए विरोध कर रहे हैं। कानून के लागू होने से न केवल अरबों रुपये की नजूल जमीन का सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जा सकेगा बल्कि पूर्व में गड़बड़ी कर नजूल जमीन को फ्रीहोल्ड कराने का खेल भी उजागर होगा।

दरअसल, पिछले दिनों कड़े विरोध और हंगामे के बीच विधानसभा से पारित उप्र नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक-2024 के एक अगस्त को विधान परिषद में पहुंचने पर भाजपा ही उसे पारित कराने से पीछे हट गई। उच्च सदन में भी बहुमत के बावजूद विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग के पीछे विपक्ष द्वारा इस कानून को जनविरोधी बताते हुए बड़ा मुद्दा बनाने की धार को कुंद करना था। योगी सरकार से लेकर भाजपा संगठन नहीं चाहता था कि विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव से पहले विपक्ष को किसी तरह जनता को गुमराह करने का कोई मौका मिले। सूत्रों के मुताबिक, चूंकि विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे वास्तव में जनता में किसी तरह की नाराजगी बढ़े इसलिए सरकार अंततः इस कानून को लागू करेगी। जल्द ही प्रवर समिति का गठन होगा। वैसे तो प्रवर समिति के अध्यक्ष विभागीय मंत्री होते रहे हैं लेकिन चूंकि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही है इसलिए माना जा रहा है कि किसी और मंत्री को प्रवर समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। समिति की संस्तुतियों को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। संशोधित विधेयक को पारित कराकर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति पर कानून लागू होगा।

प्रदेश में लगभग 75 हजार एकड़ नजूल जमीन की कीमत दो लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। सर्वाधिक भूमि प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, सुलतानपुर, गोंडा, बाराबंकी आदि में है। कई कीमती व बड़ी जमीनों पर भूमाफिया व रसूखदारों का कब्जा है। मुख्यमंत्री ने भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए चार स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया था। बीते लगभग सवा चार साल में राजस्व व पुलिस विभाग ने भूमाफिया के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,54,249 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। 2,464 कब्जेदारों को चिह्नित कर 187 भूमाफिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

सरकारी जमीन की हेराफेरी पर रोक लगाने की रहेगी कोशिश। प्रतीकात्मक

वोहरा समिति ने जताई थी चिंता

लगभग तीन दशक पहले केंद्र सरकार द्वारा पूर्व गृह सचिव एनएन वोहरा की अगुआई में गठित समिति ने नजूल जमीन को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी। वर्ष 1993 में आई वोहरा समिति की रिपोर्ट में राजनेता, अपराधी, भूमाफिया, नौकरशाह व न्यायपालिका से जुड़े लोगों के संगठित गिरोह पर चिंता जताते हुए कहा गया था कि 'बड़े शहरों में आय का मुख्य स्रोत अचल संपत्ति से जुड़ा है।

****

हिमाचल में होम स्टे संचालक मर्जी से वसूल सकेंगे राशि

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला

- **होम स्टे में कमरों का किराया सुविधाओं के आधार पर तय होगा**
- **अब 5000 हजार रुपये तक कमरे का किराया ले सकेंगे**

हिमाचल प्रदेश में होम स्टे संचालन के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। नए नियमों के लागू होने के बाद होम स्टे मालिक मर्जी से सुविधा के आधार पर पर्यटकों से राशि वसूल सकेंगे। पहले होम स्टे के लिए अधिकतम 2500 रुपये की फीस निर्धारित थी। अब होटलों की तर्ज पर पैसे वसूले जाने का प्रविधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति के प्रस्ताव को सरकार मंजूरी प्रदान करेगी।

पहले आमतौर पर होम स्टे में 1000 रुपये न्यूनतम मूल्य पर कमरा मिल जाता था। अब तैयार की जा रही नई होम स्टे नीति में संचालक एक कमरा पांच हजार रुपये शुल्क पर दे सकेगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति की ओर से नई होम स्टे नीति का निर्धारण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनी होम स्टे नीति का दायरा बढ़ाकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग किया जा रहा है। प्रदेश में इस समय पांच हजार से अधिक होटल हैं, जोकि सरकार को कई तरह का शुल्क चुकाते हैं। शिमला सहित जिला मुख्यालयों के आसपास सैकड़ों की संख्या में होम स्टे खुल चुके हैं और लगातार खुलते जा रहे हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार प्रदेश में तीन हजार से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं, जिन्हें घरेलू दरों पर सस्ती बिजली और पानी की सुविधा प्राप्त है।

1300 से अधिक राहत व बचाव कर्मी वायनाड में रेस्क्यू आपरेशन में जुटे हैं। वायु सेना ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान को तेज करने को सियाचिन और दिल्ली से एक जावर और चार रीको रडार को हवाई मार्ग से मंगाया।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 5 अगस्त, 2024

सेना ने संभाला मोर्चा, 1275 को बचाया

कुदरत का कहर ▸ केदारनाथ धाम में अब भी करीब 400 यात्री फंसे, चिनूक नहीं भर पाया उड़ान

हिमाचल प्रदेश में चौथे दिन मिले पांच शव, मरने वालों की संख्या हुई 14

जागरण टीम, नई दिल्ली

उत्तराखंड में केदारघाटी में आई आपदा के बाद बचाव और राहत कार्य में अब सेना भी जुट गई है। ध्वस्त पड़े रास्तों और पैदल पुल को ठीक करने का काम किया जा रहा है। यात्रियों के जंगल में भटकने और पैदल मार्ग पर दबे होने की वास्तविकता का पता लगाने के लिए डाग स्क्वायड को भी लगा दिया गया है। सेना ने गौरीकुंड-सोनप्रयाग हाईवे पर फंसे 25 घायल, बुजुर्ग और दिव्यांगों को ट्राली के जरिये से निकाला। सेना, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के संयुक्त अभियान में रविवार को 1275 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। अब तक विभिन्न मार्गों पर फंसे 10374 यात्रियों निकाला जा चुका है। केदारनाथ धाम में अभी 400 यात्री फंसे हैं।

उधर, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, शिमला व मंडी जिलों में सात स्थानों पर बादल फटने के बाद बाढ़ आने से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है, जबकि 41 लोग अभी लापता हैं। रविवार को पांच शव मिले हैं।

हिमाचल प्रदेश में शिमला स्थित रामपुर गांव के समेज गांव में बादल फटने के बाद खोज एवं बचाव कार्य के लिए अस्थायी पुल का निर्माण करता भारतीय सेना का जवान। एएनआइ

केदारघाटी में 31 जुलाई की रात बादल फटने और भूस्खलन के बाद जगह-जगह फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियां जुटी हैं। खराब मौसम के कारण रविवार को भी वायुसेना के मालवाहक हेलीकाप्टर चिनूक और एमआइ-17 उड़ान नहीं भर पाए। छोटे हेलीकाप्टर और पैदल मार्ग से बचाव और राहत कार्य चलाया गया। सोमवार से सेना ने भी बचाव और राहत कार्य में मोर्चा संभाल लिया है। रविवार को विभिन्न मार्गों पर फंसे 640 यात्रियों को हेलीकाप्टर और 635 को पैदल मार्ग से सुरक्षित निकाला गया। गया।

हिमाचल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, सेना, आइटीबीपी व सीआइएसएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं।उधर, स्पीति की पिन घाटी के सगनम गांव में भी बाढ़ आने से एक महिला की मौत की सूचना है। आपदा के करीब 48 घंटे बाद कुल्लू के बिंदू ढाग व रायसन में कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर यातायात बहाल हो गया है। मंडी में पंडोह बांध के पांचों गेट अब खुल गए हैं।

गांदरबल में बादल फटने से श्रीनगर-लेह राजमार्ग बंद

मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में रविवार को बादल फटने से कई घर, सड़क और धान की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। सड़क पर चट्टानें आ जाने के कारण श्रीनगर-लेह राजमार्ग बंद हो गया। इसे खोलने में मशीनरी जुट गई है। बादल फटने से क्षेत्र में भूस्खलन शुरू हो गया। बड़ी-बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गईं और सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

एक ही परिवार के 16 लापता, चार के शव मिले

वायनाड में भूस्खलन

वायनाड, प्रेट्र : केरल के वायनाड में बीते मंगलवार को भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों में लापता लोगों की तलाश का काम छठे दिन भी जारी रहा। इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 308 पर पहुंच गया है। सेना और अन्य बचाव दल अभी भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। सर्वाधिक प्रभावित चार गांवों में से एक चूरलमाला गांव में एक ही परिवार के 16 सदस्य गायब हो गए, इनमें से अभी तक केवल चार के ही शव बरामद हुए हैं। भूस्खलन में चूरलमाला के अलावा तीन अन्य गांव मुंडक्कई, अट्टमाला और नूलपुझा भी पूरी तरह तबाह हो गए थे।

इस प्राकृतिक आपदा में चूरलमाला के रहने 42 वर्षीय निवासी मंसूर की तो सारी पारिवारिक बगिया ही उजड़ गई। अब वह अकेले और बेसहारा हो गए हैं। मंसूर ने अपने परिवार के 16 सदस्यों को खो दिया, जिसमें उनकी मां, पत्नी, दो बच्चे, बहन और उनकी भाभी के परिवार के 11 सदस्य शामिल हैं। बिना सोये और रो-रोकर हुई लाल हुई आंखे लिए मंसूर ने कहा- "मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ खत्म हो गया है।" वह खुद बाल-बाल बच गए क्योंकि घटना वाले दिन वह काम के चलते बाहर गए हुए थे। भारी मन से उन्होंने कहा- "मुझे अभी तक अपनी बेटी का शव नहीं मिला है। हमें चार शव मिले हैं मेरी पत्नी, बेटा, बहन और मेरी मां का।" मंसूर के भाई नासिर ने कहा- आज सुबह, उन्होंने अपनी मां के अवशेषों की पहचान की, जिससे बरामद शवों की कुल संख्या चार हो गई। परिवार के बारह सदस्य अभी लापता हैं। नासिर ने कहा- 'मैं पहले इस क्षेत्र में रहता था, लेकिन अब यहां से चला गया हूं। मेरा छोटा भाई और उसका परिवार, मेरी मां और बहन के साथ हमारे पारिवारिक घर में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि घटना से पहले क्षेत्र के निवासियों, जिसमें उनके भाई का परिवार भी शामिल है, को अधिकारियों से कोई चेतावनी नहीं मिली थी।

- बाहर होने की वजह से बच गए एकमात्र सदस्य ने कहा- मेरा तो सब कुछ उजड़ गया
- केरल में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 308 पर पहुंचा, राहत-बचाव कार्य जारी

वायनाड में भूस्खलन के बाद पांचवें दिन कलपेट्टा फारेस्ट रेंज के चार सदस्यीय दल द्वारा एक गुफा में फंसे आदिवासी बच्चों को बचाने के बाद उन्हें पानी पिलाते अधिकारी। खतरनाक चढ़ाई वाली चट्टानी पहाड़ी में आठ घंटों की मेहनत के बाद इन्हें बचाया गया। एएनआइ

शशि थरूर ने आलोचकों को बताई 'यादगार' की परिभाषा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उन पर पलटवार के लिए 'यादगार' (मेमोरेबल) शब्द की परिभाषा सामने रखी है, जिन्होंने वायनाड भूस्खलन राहत कार्यों में शिरकत करने के बारे में उनकी एक्स पर एक पोस्ट में इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए उनकी आलोचना की थी। ट्रोल करने वालों पर पलटवार करते हुए थरूर ने शुक्रवार देर रात एक पोस्ट में कहा- 'सभी ट्रोल्स के लिए : यादगार का अर्थ है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, जो हमेशा जेहन में रहेगा या जिसके याद रहने की संभावना है क्योंकि वह विशेष या अविस्मरणीय है।'

न्यूज गैलरी

सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान ने की आत्महत्या

जयपुर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात जम्मू-कश्मीर निवासी सीमा सुरक्षा बल के जवान बनारसी लाल ने रविवार सुबह करीब आठ बजे ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान सीमा पर स्थित वाच टावर पर तैनात था। बाखासर थाना पुलिस ने बताया कि जवान बीएसएफ की बी-3 बटालियन में तैनात था। शव को बाड़मेर मेडिकल कालेज की मर्चरी में रखा गया है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। (जासं)

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा, चार की मौत

जयपुर : राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर रविवार सुबह करीब सात बजे ट्रक की टक्कर में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के विक्रमगढ़ (आलोट) निवासी कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। हादसा सवाईमाधोपुर जिले के त्रिलोकपुरा गांव के पास हुआ। मृतकों के परिवार की एक महिला की पिछले दिनों उत्तराखंड के ऋषिकेश में मौत हो गई थी। वह वहां भागवत कथा के एक आयोजन में शामिल होने गई थीं। स्वजन ने वहीं महिला का अंतिम संस्कार किया और सभी रविवार को घर लौट रहे थे। इस दौरान कार चालक को झपकी आ गई और कार पीछे से ट्रक में घुस गई। (जासं)

त्रिपुरा में 12 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

अगरतला : अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 12 बांग्लादेशी नागरिकों को त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। घुसपैठ की खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने बीएसएफ कर्मियों के साथ शनिवार रात पश्चिम अगरतला के लंकामुरा, जायनगर और रामनगर में छापेमारी की। इन स्थानों से तीन महिलाओं सहित 12 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी कांति बर्धन ने कहा कि पूछताछ के दौरान उन्होंने वैध दस्तावेजों के बिना बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की। घुसपैठ बढ़ने से पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। (प्रेट्र)

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बस और कार में टक्कर, छह की मौत, 42 घायल

जागरण संवाददाता, इटावा

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात करीब एक बजे चालक को झपकी आने से कार डिवाइडर पार करते हुए विपरीत दिशा से आ रही बस से टकरा गई। बस भी अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे के किनारे की फेंसिंग तोड़ते हुए पलटकर करीब 50 फीट नीचे जा गिरी। दुर्घटना में कार और बस सवार तीन-तीन यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 42 यात्री घायल हो गए। एआरटीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि बस का तकनीकी निरीक्षण किया गया है। फिटनेस भी सही मिली है। बस नगालैंड के कोहिमा जिले में ओम बस ट्रैवल्स कंपनी के नाम पंजीकृत है।

दुर्घटना के वक्त कार 90 और बस 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। एक्सप्रेसवे पर कार की रफ्तार सीमा 100 और बस की 80 किमी प्रति घंटे तय है।

कार सवार मेंहदीपुर से बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे। जब वे ऊसराहार से गुजर रहे थे, तब रात करीब एक बजे कार चला रहे कन्नौज के मोनू सिंह को झपकी आ गई। कार डिवाइडर पर लगी जाली तोड़ते हुए विपरीत दिशा में लखनऊ से आगरा की ओर जा रही स्लीपर बस से टकरा गई। अचानक सामने कार को देख बस चालक स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रख पाया। बस सड़क के किनारे की फेंसिंग को तोड़ते हुए एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। बस में 60 से ज्यादा यात्री सवार थे। एक बस यात्री उछल कर पहले नीचे जा गिरा। फिर बस उसी के ऊपर पलट गई, जिससे उसकी दबकर मृत्यु हो गई। दुर्घटना में कार चालक मोनू, उसकी मां चंदा और सचिन की मौत हो गई। बस सवार लखीमरपुर खीरी निवासी ओम प्रकाश, अमेठी निवासी शानू शाह और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। घायलों में उत्तर प्रदेश के साथ ही जम्मू-कश्मीर व महाराष्ट्र के यात्री शामिल हैं।

- चालक को झपकी आने से कार डिवाइडर को पार कर विपरीत दिशा में पहुंची
- सामने से कार टकराने से बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से 50 फीट नीचे गिरी
- सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने जताई संवेदना

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हुई कार। जागरण

संभल जिले में मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने पर छात्र ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, संभल : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मोबाइल फोन और आनलाइन गेम खेलने की लत में छात्र की जान चली गई। रविवार को उसने मोबाइल फोन मांगा, मगर स्वजन ने इन्कार कर दिया। इससे नाराज होकर वह कमरे में गया और पढ़ने का बहाना करता रहा। इस बीच मौका मिलते ही फंदा लगाकर लटक गया। उसके वजन से पतली रस्सी टूट गई, मगर उसकी जान फिर भी नहीं बचाई जा सकी।

16 वर्षीय अनुज कुमार उर्फ छोटू 10वीं कक्षा का छात्र था। ग्रामीणों के अनुसार, वह मोबाइल फोन में आनलाइन गेम ज्यादा खेलने लगा था, इसलिए स्वजन ने सख्ती की। रविवार दोपहर को भी उसने गेम खेलने के लिए फोन मांगा। स्वजन ने इन्कार किया तो वह नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद स्वजन कमरे की ओर गए तो वह किताबें लिए बैठा था। पिता नरेश कुमार को लगा कि डांट के बाद बेटा सुधार कर रहा। उनकी निगाह बचते ही अनुज ने कमरा अंदर से बंद कर फंदा लगा लिया।

सोशल इंजीनियरिंग के लिए वर्षभर काम करेगा संघ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर

- संपर्क और सहसंपर्क प्रमुखों को प्रदान की गई जिम्मेदारी
- इस बार बैठक में महिलाओं की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक रही
- पिछले वर्ष हुए कार्य की रूपरेखा के आधार पर आगामी कार्ययोजना बनी

सोशल इंजीनियरिंग (सामाजिक अभियांत्रिकी) के कार्य वर्ष भर चलाने के संकल्प के साथ रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग की इंदौर में चल रही चार दिवसीय बैठक का समापन हुआ। सोशल इंजीनियरिंग के तहत मानव व्यवहार और सामाजिक पैटर्न का अध्ययन कर लोगों को विशिष्ट कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है।

बैठक में तय किया गया कि डाक्टर, इंजीनियर सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनलों को जोड़कर उन्हें सेवा कार्यों के लिए प्रेरित किया जाएगा। वर्षभर की कार्ययोजना पर गहन मनन के बाद अब इसे साकार रूप देने की जिम्मेदारी देशभर से आए करीब 180 संपर्क और सहसंपर्क प्रमुखों को प्रदान की गई। इसे क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष में होने वाले कार्यों, देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती उत्सव के आयोजन, महिला संगठन के माध्यम से महिला वर्ग और परिवार में पैठ बनाने आदि के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए।

इस बार बैठक में महिलाओं की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक रही। बैठक में पिछले वर्ष हुए कार्य की रूपरेखा के आधार पर आगामी कार्ययोजना बनाई गई। इसमें आनुषांगिक संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों के फीडबैक को भी रखा गया। अंतिम दिन संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सरकार्यवाह डा. कृष्णगोपाल और राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख रामलाल का भी संबोधन हुआ।

लखनऊ एयरपोर्ट से फर्जी पासपोर्ट के साथ बांग्लादेशी गिरफ्तार

जागरण टीम, लखनऊ : लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों ने चेकिंग के दौरान बांग्लादेशी नागरिक सुब्रेनिल सरकार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास जाली दस्तावेज और फर्जी पासपोर्ट भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया।

एसीपी विनय द्विवेदी के मुताबिक शुक्रवार को सुब्रेनिल मुंबई से लखनऊ आया था। मुंबई से ही उसकी यात्रा की जानकारी मिली थी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने जांच के दौरान पाया कि उसका पासपोर्ट जाली है। पासपोर्ट मध्य प्रदेश के बैतूल आंबेडकरनगर पथखेड़ा पंचशील बुद्ध विहार के पते पर बना है, जबकि आधार कार्ड बंगाल के पते पर बना हुआ है। दस्तावेज के आधार पर पता किया जा रहा है कि वह कब से और कहां रहा था? किन-किन लोगों के संपर्क में था? समेत अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है।

मुंबई पुलिस ने साइबर ठगों से बरामद किए 100 करोड़ रुपये

मुंबई, एएनआइ : मुंबई पुलिस ने साइबर ठगों से लगभग 100 करोड़ रुपये बरामद किए हैं। इस रकम को साइबर अपराधियों ने पिछले सात महीनों में लोगों से ठगा था।

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि जालसाजों द्वारा धोखाधड़ी के शिकार बनने के बाद पीड़ितों ने हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से मुंबई साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) दत्ता नलवाडे ने कहा कि इन शिकायतों के आधार पर आनलाइन धोखाधड़ी के 35,918 मामलों पर कार्रवाई की गई। ये मामले शेयर ट्रेडिंग, निवेश योजनाओं, कूरियर काल, डिजिटल अरेस्ट की धमकियों, आनलाइन लेनदेन से संबंधित थे। आरोपितों के खाते फ्रीज कर दिए हैं।

उन्होंने लोगों से वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित किसी भी शिकायत की रिपोर्ट करने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर जालसाज लोगों को फंसाने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। डीसीपी नलवाडे ने कहा, अगर किसी भी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो तुरंत 1930 पर काल करें।

- साइबर अपराधियों ने पिछले सात महीनों में लोगों से ठगी थी यह रकम
- मुंबई साइबर पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत, आरोपितों के खाते फ्रीज

नशे में क्रेटा सवार आबकारी उपायुक्त ने बाइक में मारी टक्कर, तीन किमी घसीटा

राकेश कुमार सिंह, जागरण

नई दिल्ली: नशे में क्रेटा कार सवार आबकारी उपायुक्त आरसी मीणा शनिवार देर रात झंडेवालान स्थित वीडियोकान टावर के पास एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। घर जाने के दौरान उन्होंने एक बाइक (रेपिडो) में जोरदार टक्कर मार दी। क्रेटा कार से जबरदस्त टक्कर लगने से बाइक सवार उछलकर साइड में गिर पड़ा, लेकिन बाइक कार में फंस गई।

घटना के बाद घबराकर मौके से भागने के क्रम में क्रेटा कारा चालक करीब तीन किलोमीटर तक बाइक को घसीटते हुए लेकर चले गए। जिससे रगड़ खाकर बाइक में आग लग गई। बाइक में आग लगने से क्रेटा में भी आग लग गई। कार के बोनट से आग की लपटें देखकर उन्होंने कार रोक दी और जल्दी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस हादसे में कार और बाइक जलकर राख हो गई। इस मामले में दिल्ली की करोलबाग थाना पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के कारण आबकारी उपायुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया। जली हुई कार और बाइक को जब्त कर लिया गया है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरसी मीणा दानिक्स अधिकारी हैं। इनकी तैनाती कुछ समय से आबकारी विभाग में उपायुक्त पद पर है। शनिवार को पश्चिमी दिल्ली के एक बार में उन्होंने शराब पी इसके बाद वह अपनी क्रेटा कार से सिविल लाइंस स्थित घर के लिए निकल पड़े। रात करीब दो बजे पटेल नगर होते हुए जब वह पूसा रोड पर झंडेवालान स्थित वीडियोकान टावर के पास आए, तब वहां उन्होंने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रेपीडो बाइक सवार गुरविंदर उछल कर वहीं साइड में गिर पड़ा। उसे मामूली चोटें आईं। भागने के क्रम में कार चालक आबकारी उपायुक्त बाइक को करीब तीन किलोमीटर तक घसीटते ले गए।

बताया जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आबकारी उपायुक्त का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें उनके नशे में होने की पुष्टि हुई। घटना के बाद मुकदमा व गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों से संपर्क किया।

- टक्कर लगने से आबकारी उपायुक्त आरसी मीणा की कार के नीचे फंस गई थी बाइक
- सड़क पर बाइक के घसीटे जाने से लगी आग, जलकर राख हो गई कार और बाइक

जागरण विशेष

ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग के अध्ययन को अब मिलेगी नई दिशा

केंद्र सरकार ने किया नवाचार, एक प्लेटफार्म पर आएंगे देश में अलग-अलग अध्ययन कर रहे संस्थान

रीना डंडरियाल • जागरण

रुड़की: जलवायु परिवर्तन के कारण जहां पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वहीं वर्षा का पैटर्न भी बदला है। ग्लेशियर पिघलने और भूजल के गिरते स्तर के पीछे भी जलवायु परिवर्तन की अहम भूमिका मानी जा रही है। यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग से पार पाने के लिए अपने देश में भी अनेक संस्थान अध्ययन कर रहे हैं। केंद्र की पहल से इस दिशा में एक नवाचार हुआ है, जिससे इसके अध्ययन को नई दिशा मिलेगी। पूर्व की भांति अब भी देश में अलग-अलग संस्थान अपने-अपने तरीके से ग्लेशियर (हिमनाद) पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अध्ययन तो जरूर करेंगे, पर एक कमेटी इसकी निगरानी करेगी। ऐसे में ये संस्थान एक राय होकर एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार ने एक ऐसे केंद्र की स्थापना की है, जहां दोनों ही विषयों पर एक साथ अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

हिममंडल एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र के प्रमुख विज्ञानी डा. सुरजीत सिंह ने बताया कि ग्लेशियर पर नेपाल, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, रूस व चीन आदि देश अध्ययन कर रहे हैं। भारत में भी इसरो, सैक अहमदाबाद, एनसीपीओआर, आइआइआरएस जैसे 12 से अधिक अनुसंधान, विकास और शैक्षणिक संस्थान इस पर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में कई बार कार्य में दोहराव, मानव शक्ति एवं बजट के अनावश्यक उपयोग की आशंका रहती है। डाटा साझा करने में भी कुछ दिक्कतें आती। ऐसे में किसी एक क्षेत्र विशेष के ग्लेशियर पर अध्ययन करके दूसरे क्षेत्र के ग्लेशियर के बारे में सटीक आंकड़े प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से स्टीयरिंग कमेटी फार मानिटरिंग आफ ग्लेशियर नाम से एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी न केवल विभिन्न संस्थानों से एकत्रित अद्यतन जानकारी के आधार पर रोडमैप और दिशा पर चर्चा करेगी बल्कि अध्यन को किस दिशों में ले जाना है, इसके बारे में भी बताएगी। इसके साथ ही प्रत्येक छह माह में केंद्र सरकार को अपडेट देगी।

ग्लेशियर और जलवायु पर एक ही केंद्र में अध्ययन: अब तक हिम और हिमनद अनुसंधानीय अध्ययन से संबद्ध समग्र जानकारी एकत्र करने वाले एकल संस्थान की कमी थी, जिसे दूर करने को जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआइएच) रुड़की में हिममंडल एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र की स्थापना की है। डा. सुरजीत सिंह ने बताया कि अपने देश में हिम और हिमनद अनुसंधानीय अध्ययन से संबद्ध ऐसा कोई एकल संस्थान नहीं था, जो अंतःविषयक अनुसंधान एवं विकास कार्यों में संलग्न हो। अनुसंधान एवं विकास के लिए नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और हस्तांतरित करने के लिए एक औपचारिक मंच की आवश्यकता थी। स्नो और ग्लेशियर प्रबंधन के लिए यह केंद्र बहुविषयक पद्धतियों के माध्यम से मौजूदा खाई को पाटने का कार्य करेगा। इसके लिए 20 सदस्यीय संचालन समिति का भी गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन जल शक्ति मंत्रालय के सचिव हैं। समिति में कई संस्थानों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। इस केंद्र में संस्थान के विज्ञानियों की 11 सदस्यीय टीम 16 से अधिक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है।

पोर्टल किया जा रहा विकसित

डा. सुरजीत सिंह

देश के विभिन्न संस्थान जलवायु परिवर्तन, स्नो एवं ग्लेशियर को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। सभी शोध कार्यों की जानकारी एक जगह उपलब्ध हो, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र को एक पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। डा. सुरजीत सिंह ने बताया कि सी-डैक पुणे यह पोर्टल तैयार करेगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि पोर्टल में अपना शोध डालने वाले संस्थान या शोधकर्ता की अनुमति के बिना उसकी डिटेल रिपोर्ट और आंकड़े नहीं देखे जा सकेंगे।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की में स्थापित हिममंडल एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र में कार्य करती विज्ञानियों की टीम • जागरण

हिमालयीय क्षेत्र में चार ग्लेशियरों की शुरू की गई निगरानी

एनआइएच रुड़की हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक उत्तरकाशी स्थित 30 किमी लंबे गंगोत्री ग्लेशियर की वर्ष 2002 से निगरानी कर रहा है। वहां पर आटोमैटिक वेदर स्टेशन भी स्थापित हुआ है। वहीं, हाल ही में संस्थान ने हिमालय के तीन और ग्लेशियर की निगरानी शुरू की है। इनमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित मिलम ग्लेशियर, टिहरी जिले का खतलिंग ग्लेशियर और हिमाचल प्रदेश का त्रिलोकीनाथ ग्लेशियर शामिल है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

चार जवानों की हत्या करने वाले सैनिक को उम्र कैद

जासं, बठिंडा : अति उच्च सुरक्षा वाले बठिंडा सैनिक छावनी में 12 अप्रैल, 2023 को चार साथी जवानों की गोली मारकर हत्या करने के दोषी सैनिक देसाई मोहन को जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सेना की कोर्ट आफ इंक्वायरी के बाद उसे सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है।

- अति उच्च सुरक्षा वाले बठिंडा सैनिक छावनी में 12 अप्रैल, 2023 को चार जवानों की हुई थी हत्या
- चारों सैनिकों को देसाई मोहन ने उस समय गोली मारी थी, जब वे सैन्य अपने कमरे में सो रहे थे

जानकारी के अनुसार, मामले में दोषी ठहराए गए गनर देसाई मोहन के अलावा घटना में मारे गए सैनिक सागर बन्ने, कमलेश आर, संतोष नागरल और योगेश कुमार जे सेना के तोपखाने की 80 मीडियम रेजिमेंट मेस में तैनात थे। चारों सैनिकों को दोषी ठहराए गए गनर देसाई मोहन ने उस समय गोली मारी थी, जब वे सैन्य अधिकारियों की मेस के पास अपने कमरे में सो रहे थे।

मारे गए चारों सैनिक दक्षिण भारत के अलग-अलग स्थानों के थे। देसाई मोहन को चारों सैनिकों की हत्या के अलावा एक सैन्य चौकी से इंसास राइफल और मैगजीन चोरी करने का भी दोषी पाया गया। राइफल का इस्तेमाल हत्याकांड में किया गया था। पुलिस जांच में आंध्र प्रदेश के रहने वाले देसाई मोहन ने शुरू में मृतक सैनिकों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। देसाई मोहन ने दावा किया कि चारों सहकर्मी उसके मोबाइल का उपयोग कर उसकी मंगेतर से बात करते थे। आपत्तिजनक तस्वीरें लेते और उसका मजाक उड़ाते। इसके बाद देसाई मोहन ने उनके खिलाफ रंजिश पाल ली और इस घातक घटना को अंजाम दे दिया।

****

कोटे में कोटा

आरक्षण का फायदा कुछ चुनिंदा जातियां ही उठा रही हैं, बाकी कमजोर जातियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बात पर लंबे समय से चर्चा हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों यानी एससी-एसटी समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया है। सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एससी-एसटी समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमजोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। एससी-एसटी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ न के बराबर मिला है। ऐसा इसीलिए हुआ है, क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियां उठाती हैं। यही स्थिति ओबीसी में है। एससी-एसटी समुदाय में उप वर्गीकरण का रास्ता साफ होने से अब तक आरक्षण के लाभ से वंचित रहीं जातियों का कितना कल्याण होगा, यह पड़ताल का बड़ा मुद्दा है।

गरीबों और वंचितों के सामाजिक उत्थान में मिलेगी मदद

हर्षवर्धन त्रिपाठी
राजनीतिक विश्लेषक

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और जो बेहतर जीवन जी रहे हैं, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ऐसा करके ही आरक्षण के लाभ से वंचित लोगों के सामाजिक उत्थान को संभव बनाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति में आरक्षण के लाभ को अनुसूचित जाति में शामिल सभी जातियों को समान रूप से न मिल पाने पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। सात न्यायाधीशों की खंडपीठ का यह निर्णय कई मायने में मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है। कानून की दृष्टि में बराबर होने के बावजूद आरक्षण के जरिये जिन जातीय समूहों को ऊपर उठाकर मुख्यधारा में लाना था, आरक्षण के बावजूद मुख्यधारा में नहीं आ सके हैं। इसके पीछे बार-बार यह कहा जाता है कि जिन्हें आरक्षण मिल गया, उन्हीं की अगली पीढ़ी को भी आरक्षण का लाभ मिलता रहा और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि, अनुसूचित जातियों में बड़े जातीय समूह को आरक्षण का लाभ ठीक से नहीं मिल सका। अब सभी जातियों को ठीक से आरक्षण का लाभ मिल सके, इसके लिए सातों न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बीस वर्ष पूर्व के सर्वोच्च न्यायालय के ही एक निर्णय को उलटकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि, अनुसूचित जातियों और जनजातियों में कुछ जातियों ने ही आरक्षण का पूरा लाभ लिया है, ऐसे में राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि, विवेकपूर्ण तरीके से पक्के आधार पर जिन जातियों को आरक्षण का अधिकार देने की आवश्यकता दिखती है, उन्हें दिया जाए। इसमें अनुच्छेद 341 की राष्ट्रपति सूची के प्रश्न को भी शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की खंडपीठ के निर्णय की मूल भावना को स्पष्टता से समझने के लिए न्यायाधीश बीआर गवई की कही एक बात देश में हर किसी को पता चलनी चाहिए। वैसे तो ओबीसी आरक्षण के मामले में क्रीमीलेयर पहले से लागू है, लेकिन लंबे समय से यह बात सामने आ रही है कि, ओबीसी में भी कुछ जातीय समूह ही हैं, जो आरक्षण का अधिकांश लाभ ले रहे हैं। इस पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी केंद्र सरकार के पास है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि, ओबीसी आरक्षण का अधिकांश लाभ सिर्फ 10 जातियों के लोगों को ही मूल रूप से मिल पा रहा है। ओबीसी में शामिल लगभग 1,500 जातियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास है, लेकिन लंबे समय से चर्चा के बावजूद केंद्र सरकार भी यह रिपोर्ट लागू करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में आरक्षण का उप वर्गीकरण का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश में आरक्षण की समीक्षा करके आरक्षण के लाभ से छूट गए लोगों को शामिल करने का सही रास्ता दिखा रहा है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के निर्णय का विरोध सवर्णों की ओर से जिस तरह से हुआ था, कुछ उसी तरह से पिछड़ों और अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण का लाभ ले रहे नव सवर्णों को सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय पच नहीं रहा है।

न्यायाधीश बीआर गवई ने निर्णय सुनाते हुआ कहा कि, जनरल कोच में ऐसा होता है कि जो पहले बाहर रहता है, वह भीतर आने के लिए संघर्ष करता रहता है, जब वह अंदर आ जाता है तो फिर कोशिश करता है कि बाहर वाला अंदर न आ पाए। उन्होंने इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि, एक शख्स जब आइएएस-आइपीएस बन जाता है तो उसके बच्चे गांवों में रहने वाले उसके समुदाय की तरह असुविधाओं का सामना नहीं करते, फिर भी उसके परिवार को पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद संपन्न लोगों को या एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेने वालों को आरक्षण का लाभ मिले या नहीं, इस पर निर्णय लेने में नरेन्द्र मोदी की सरकार को शक्तिशाली पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति, जनजाति के समूहों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। राहुल गांधी की अगुआई वाला विपक्ष आरक्षण समाप्त कर देने जैसा चुनावी अभियान फिर से शुरू करने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए, नरेन्द्र मोदी की सरकार इस पर कोई निर्णय करेगी, यह मुश्किल दिखता है, लेकिन मोदी सरकार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करके पिछड़ी जातियों में आरक्षण के लाभ से वंचित बड़े समूह को शामिल करके राजनीतिक नुकसान से बच सकती है। उसका अगला चरण यह अवश्य हो सकता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में आरक्षण न दिया जाए। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने समाज में समरसता, बराबरी का जो स्वप्न देखा था, उसे इसी तरह से पूरा किया जा सकता है। समाज में कोई भी सुधार मुश्किलों से होता है। जब आरक्षण आया तो सवर्णों को लगता था कि उनके हिस्से से छीना जाएगा। अब आरक्षण में आरक्षण आया तो अनुसूचित जाति, जनजाति में सवर्ण बन बैठी कुछ जातियों के लोगों को लग रहा है कि उनका हिस्सा छिन जाएगा। जो लोग आरक्षण में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वो ठेकेदार बन गए हैं। समाज में समरसता के विरोधी हैं और बाबा साहब के स्वप्न को पूरा नहीं होने देना चाहते।

दशकों पुरानी है आरक्षण का लाभ न मिल पाने की शिकायत

अनुसूचित जातियों में अधिक पिछड़ी जातियों की यह शिकायत सदी के छठे दशक से ही रही है कि उनमें से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत जातियां उनको आरक्षण के फायदे से वंचित कर रही हैं। हालांकि कानून बनाकर उनकी शिकायतों को दूर करने की पहल होने में बहुत समय लगा।

पहली बार आंध्र प्रदेश ने बनाया कानून

पहली बार आंध्र प्रदेश ने एपी शेड्यूल्ड कास्ट्स (रेशनलाइजेशन आफ रिजर्वेशंस) एक्ट,2000 बनाया। इस कानून में अनुसूचित जातियों यानी एससी को छह श्रेणी में बांटा गया और उनमें आरक्षण का विभाजन किया। ग्रुप ए को 1 प्रतिशत, ग्रुप बी को 7 प्रतिशत, ग्रुप सी को 6 प्रतिशत और ग्रुप डी को 1 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। हाई कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने ईवी चिन्नैया मामले में यह कहते हुए कानून को खारिज कर दिया कि एससी समरूप समूह है इनका उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।

पंजाब के कानून को हाईकोर्ट ने किया खारिज

2006 में, पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड बैकवर्ड क्लासेज (रिजर्वेशन इन सर्विसेज) एक्ट बनाया गया। इस कानून के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण एससी को दिया गया। इस 25 प्रतिशत आरक्षण में से 50 प्रतिशत एससी जातियों जैसे वाल्मीकि और मजहबी सिख को सीधी भर्तियों में दिए जाने का प्रविधान था। हाई कोर्ट ने 2010 में चिन्नैया फैसले के आधार पर इसे खारिज कर दिया। जब पंजाब ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। एससी समुदाय में जातियों के आरक्षण के फायदों से वंचित होने का इतिहास दशकों पुराना है।

एससी समुदाय को चार वर्गों में बांटने की सिफारिश

1997 में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायाधीश पी रामचंद्र राजू कमीशन गठित किया। कमीशन की राय थी कि एससी समुदाय में आरक्षण का फायदा कुछ खास जातियों को मिला है। इसलिए कमीशन ने एससी समुदाय को चार वर्गों में बांटने की सिफारिश की थी। 2001 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने हुकुम सिंह समिति का गठन किया। इस समिति ने पाया कि आरक्षण का फायदा सबसे कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंचा है। समिति ने एससी/ओबीसी की सूची के उप वर्गीकरण की सिफारिश की।

लहूजी साल्वे कमीशन

2003 में, महाराष्ट्र ने एससी की लिस्ट में मांग जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए लहूजी साल्वे कमीशन गठित किया। कमीशन ने एससी समुदाय के उप वर्गीकरण की सिफारिश की क्योंकि मांग जाति जातियों के पदानुक्रम में निचले पायदान पर थी और इसको आरक्षण का खास फायदा नहीं हुआ था।

न्यायाधीश सदाशिव पैनल

2005 में, कर्नाटक सरकार ने एससी समुदाय में आरक्षण का लाभ न पाने वाली जातियों की पहचान के लिए न्यायाधीश सदाशिव पैनल गठित किया। पैनल ने 101 जातियों को चार कटैगरी में बांट कर एससी के लिए कुल 15 प्रतिशत आरक्षण प्रत्येक श्रेणी में बांटने की सिफारिश की। 2007 में, बिहार के महादलित पैनल ने एससी की लिस्ट में से 18 जातियों को अत्यधिक कमजोर जातियों के तौर पर शामिल करने की सिफारिश की। इसी वर्ष, राजस्थान की न्यायाधीश जसराज चोपड़ा समिति ने गुज्जर जाति को अत्यंत पिछड़ा बताते हुए ओबीसी जातियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की सिफारिश की। 2008 में, तमिलनाडु के न्यायाधीश एमएस जनार्थनम पैनल ने सिफारिश की थी कि अरुंथथियर के साथ आरक्षण के मामले में अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।

एससी उप वर्गीकरण आंदोलन : 1994 से 2024

- **1994** एससी समुदाय में उप वर्गीकरण की मांग को लेकर आंदोलन अविभाजित आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। नेतृत्व मदीगा आरक्षण पोराता समिति के अध्यक्ष मंदा कृष्ण मडिगा ने किया।
- **1996** टीडीपी सरकार ने उप वर्गीकरण के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए न्यायाधीश पी रामचंद्रन राजू कमीशन नियुक्त किया।
- **1997** कमीशन ने एससी का उप वर्गीकरण चार समूहों में किए जाने की सिफारिश की। हर समूह के लिए अलग से आरक्षण का प्रस्ताव।
- **2004** संप्रग सरकार ने एससी उप वर्गीकरण के परीक्षण के लिए न्यायाधीश ऊषा मेहता पैनल बनाया।
- **2008** ऊषा मेहता कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी, एससी समुदाय में उप वर्गीकरण की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 341 में संशोधन की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे का हवाला देते हुए रिपोर्ट लागू करने से इन्कार कर दिया।
- **2014** तेलंगाना के गठन के बाद बीआरएस सरकार ने विधानसभा में एससी उप वर्गीकरण के पक्ष में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा।
- **2023** विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और भाजपा ने एससी उप वर्गीकरण का वादा किया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी भाजपा की ओर से उप वर्गीकरण का वादा किया।

सामाजिक न्याय पर एक राय बनाएं सभी दल

डा. एके वर्मा
राजनीतिक विश्लेषक

आरक्षण ही सामाजिक न्याय का एकमात्र उपकरण नहीं है। यदि राजनीतिक दलों में आरक्षण से इतर सामाजिक न्याय को और आगे ले जाने की सहमति बने तो सर्वाधिक गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित और वंचितों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है।

एक अगस्त, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने पंजाब बनाम दविंदर सिंह मुकदमे में अति-दलितों की आवाज बन कर इतिहास रच दिया। मुकदमे का मूल प्रश्न था कि क्या आरक्षण हेतु अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण संवैधानिक है? सर्वोच्च न्यायालय ने 6-1 से इसे संवैधानिक माना। लगभग 50 वर्ष पूर्व पंजाब सरकार ने दलितों का उप-वर्गीकरण कर आरक्षण का 50 प्रतिशत वाल्मीकि व मजहबी सिखों तथा 50 प्रतिशत अन्य-दलितों के लिए आवंटित किया था। लेकिन जब चिन्नैया बनाम आंध्र-प्रदेश मुकदमे (2004) में सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण को असंवैधानिक घोषित किया, तो पंजाब-हरियाणा उच्च-न्यायालय ने भी पंजाब सरकार का आदेश निरस्त कर दिया। वर्तमान निर्णय पंजाब सरकार के 50 वर्ष पहले आए आदेश की जीत है।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, आज अनुसूचित जाति समरूप नहीं है। पिछले 75 वर्षों में इसकी अनेक उप-जातियां ऊपर उठ चुकी हैं। उन्हें कमजोर-पिछड़ी उप-जातियों के लिए स्थान खाली करना होगा। राज्य अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर उन्हें समानुपातिक आरक्षण दे सकेंगे। लेकिन राज्य न तो किसी एक उप-जाति के लिए शत-प्रतिशत स्थान आरक्षित करेंगे, न मनमाने ढंग से उनका उप-वर्गीकरण करेंगे। नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन के आंकड़ों के आधार पर ही उप-वर्गीकरण होगा, जिसकी न्यायिक समीक्षा हो सकेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुसूचित-जातियों में भी 'क्रीमी-लेयर' की अवधारणा वैसे ही लागू होनी चाहिए जैसे 'अन्य-पिछड़े-वर्ग' में, भले ही उसके मानक भिन्न हों। सच्चे सामाजिक-न्याय की स्थापना हेतु क्रीमी लेयर वाली अनुसूचित जातियां आरक्षण से बाहर हों। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में क्रीमी लेयर पहले ही लागू कर चुका है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के अनुसार क्रीमी लेयर लागू करने से कोई एक उप-जाति आरक्षण पर एकाधिकार नहीं जमा सकेगी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में 'वास्तविक समानता' की मांग है कि आरक्षण का लाभ उनको मिले जो सबसे कमजोर हैं। इसीलिए न्यायमूर्ति मिथाई ने आरक्षण को नए सिरे से देखने और केवल एक-पीढ़ी तक उसका लाभ सीमित करने का सुझाव दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ऐतिहासिक है क्योंकि जिस देश में पहले अन्य पिछड़े वर्ग तक में उप-वर्गीकरण करना और समानुपातिक आरक्षण की बात करना गलत था। उसी देश में आज अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तक में उप-वर्गीकरण और समानुपातिक आरक्षण को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की सरकार ने हुकुम सिंह समिति (2001) की सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग में ऐसा उप-वर्गीकरण कर समानुपातिक आरक्षण की कोशिश की थी, पर विरोध के कारण वह लागू न हो सका जबकि मंडल-कमीशन मुकदमे (1992) में सर्वोच्च न्यायालय उप-वर्गीकरण को संवैधानिक मान्यता दे चुका था। आज अपने 20 वर्ष पुराने आदेश को पलट कर सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को पुनर्परिभाषित किया है, जो विगत 75 वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के बड़े हिस्से में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नयन को दर्शाती है और मांग करती है कि सामाजिक न्याय के लिए उन उप-वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जो आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इसे ही मुख्य-न्यायाधीश ने 'औपचारिक न्याय' से 'वास्तविक न्याय' की ओर जाने की संज्ञा दी है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सामाजिक न्याय, वास्तविक समानता और समावेशी समाज के संकल्पों को और दृढ़ करता है। आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संपन्न दलितों के अनेक उप-वर्ग आज समाज की मुख्य धारा में हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य-वर्ग के कंधे से कंधा मिला कर योगदान दे रहे हैं। वहीं, दलित-वर्ग की कुछ उप-जातियां 75 वर्षों से वही कर रही हैं जो उनके बाप-दादा किया करते थे। यह निर्णय इन उप- जातियों को भी उम्मीद देता है कि वे भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।

आपकी आवाज

एससी-एसटी में उप वर्गीकरण से इन समुदायों में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर अपनी स्थिति बेहतर बना चुकी जातियों के छंट जाने से अन्य वंचित जातियों को अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थितियां सुधारने का अधिक अवसर मिलेगा। बेहतर विकसित एवं समता मूलक भारतीय समाज के निर्माण के लिए इन समुदायों में क्रीमीलेयर वाला प्रविधान भी होना चाहिए। **गौरीशंकर अंतज**

एससी-एसटी समुदाय में ताकतवर जातियां ही लंबे समय से आरक्षण का फायदा उठाती रही हैं, वहीं कमजोर जातियों को इसका फायदा नहीं मिल पाया है। ऐसे में ताकतवर जातियां कभी नहीं चाहेंगी कि उनके समुदाय में उप वर्गीकरण हो। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारें भी इस दिशा में वोट की कीमत पर शायद ही जरूरी कदम उठाएं। **रमेश वर्मा**

राजनेताओं ने धर्म और जाति के भेदभाव को खत्म करने की बातें बहुत की, लेकिन इसे खत्म करके की दिशा में काम बहुत कम किया है। नेता और राजनीतिक दल कभी भी नहीं चाहेंगे कि देश में धर्म और जाति के भेदभाव की आग बुझे, और यह आरक्षण को हमेशा मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं। इससे उनको राजनीतिक रोटियां सेंकने का मौका मिलता है। **राजेश चौहान**

राष्ट्रीय फलक

अंग प्रत्यारोपण में एक दशक में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोतरी

प्रथम पृष्ठ से आगे

पिछले 10 साल में देश में अंग प्रत्यारोपण के मामलों में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। अधिकांश केस किडनी प्रत्यारोपण के हैं। 2023 में भारत में 18,378 अंग प्रत्यारोपण किए गए जोकि दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। 2013 में प्रत्यारोपणों की संख्या 4,990 दर्ज की गई थी। भारत ने 2023 में एक और मील का पत्थर हासिल किया। पहली बार एक वर्ष में 1,000 से अधिक अंग मृतक दानदाताओं के थे, ये अंग मृतकों के परिजनों ने दिए थे। 2023 में किडनी प्रत्यारोपण की संख्या 13,426 थी जबकि लीवर प्रत्यारोपण के केस 4,491, हार्ट प्रत्यारोपण के 221, फेफड़े प्रत्यारोपण के 197 मामले थे। जीवित दाताओं में 2023 में महिलाओं (9,784) की संख्या पुरुषों (5,651) से लगभग दोगुनी थी। हालांकि मृतक अंगदानदाताओं में पुरुषों की संख्या 844 जबकि महिलाओं की 255 थी। 2023 में जीवित अंग दाताओं की संख्या 15,436 व मृतक दाताओं की संख्या 1,099 थी। (स्रोत : नोट्टो)

मरीज के पेट में पथरी दायीं ओर, आपरेशन बायीं ओर कर दिया

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी

- महिला को दर्द से राहत नहीं मिली तो सामने आई डाक्टर की लापरवाही
- मरीज ने डाक्टर से बात की तो बोले.. दोबारा निश्शुल्क हो जाएगा आपरेशन

हरियाणा के रेवाड़ी में एक डाक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक प्राइवेट अस्पताल के सर्जन ने महिला मरीज का गलत आपरेशन कर दिया। महिला की दायीं किडनी में पथरी थी पर सर्जन ने बायीं किडनी का आपरेशन कर दिया। दर्द होने पर महिला ने दूसरे अस्पताल में दिखाया तो लापरवाही पकड़ में आई और महिला को दोबारा आपरेशन कराना पड़ा। मामला पांच माह पुराना है। पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम जिले के राठीवास गांव निवासी अजय की पत्नी गुड्डी को 13 फरवरी को पेट में दर्द हुआ। उन्होंने रेवाड़ी के एक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराया। रिपोर्ट में आया कि दाहिनी किडनी में पथरी है। चिकित्सकों की सलाह पर वह उजाला सिग्नस अस्पताल पहुंचे। वहां दोबारा सभी जांच कराई। रिपोर्ट देखकर विजिटिंग डाक्टर अशोक गुप्ता ने उन्हें आपरेशन कराने की सलाह दी। इस पर गुड्डी को अस्पताल में भर्ती कराया। आपरेशन के बाद गुड्डी घर पहुंची तो फिर दर्द होने लगा। इस पर आपरेशन की समरी देखी तो उसमें आपरेशन बायीं तीन अप्रैल को ही हमने अस्पताल में ज्वाइन किया है। यह मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं है। मामले की जानकारी लेने के बाद ही कुछ बता सकता हूं। अस्पताल प्रबंधन जांच में पुलिस की पूरी सहायता करेगा।

-डा. अंकित श्रीवास्तव, यूनिट हेड उजाला सिग्नस अस्पताल

किडनी का लिखा था जबकि पथरी दायीं किडनी में थी। अजय के मुताबिक जब उन्होंने चिकित्सक अशोक से बात की तो उन्होंने कहा, आपरेशन गलत नहीं हुआ है, पर दायीं किडनी का आपरेशन निश्शुल्क कर दिया जाएगा। उन्होंने पुष्पांजलि अस्पताल में पत्नी को भर्ती कराकर आपरेशन कराया। चिकित्सक की लापरवाही के कारण पत्नी का दो बार आपरेशन कराना पड़ा। आर्थिक के साथ-साथ मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। पुलिस को पांच माह पहले शिकायत दी थी, मामला अब दर्ज किया है। अस्पताल प्रबंधन से इसकी भी शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।

मानव शरीर के अंगों से मिलते-जुलते चुनाव चिह्न को जब्त करने की मांग

नई दिल्ली, आइएएनएस: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते चुनाव चिन्हों को हटाने, फ्रीज करने और रद करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में चुनाव आयोग निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी।

याचिका में कहा गया है कि वादी ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते या समान प्रतीकों के खिलाफ कई शिकायतें कीं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। जबकि, आदर्श आचार संहिता में स्पष्ट रूप से मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करने का उल्लेख है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर चुनाव चिन्ह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसे में मानव शरीर के अंगों को छिपाया नहीं जा सकता है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

वकील ने खुद को एसएसपी के बंगले का मालिक बता 19 वर्ष में वसूले लाखों रुपये

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

- एसआइटी करेगी कप्तान के बंगले को किराये पर देने वालों का पर्दाफाश
- पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी खुलेगी पोल

बात-बात पर प्राथमिकी लिखकर जेल भेजने वाली पुलिस अपने ही कप्तान के बंगले को लेकर वकील के हाथों का खिलौना बनी रही। वकील ने पिछले 19 वर्ष में 14 कप्तानों से खुद को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के बंगले का मालिक बताकर लाखों रुपये किराया वसूल लिया। वकील के अलावा भी कई लोग एसएसपी बंगले को किराये पर देने में शामिल रहे हैं। मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त प्रशासन की अगुआई में चार सदस्यीय एसआइटी गठित कर दी है। एसआइटी एसएसपी बंगले के रिकार्ड को खंगालकर इस गड़बड़झाले की पटकथा लिखने वालों की पहचान करेगी।

मुरादाबाद के सिविल लाइंस में करीब छह हजार वर्ग मीटर में फैला बंगला 1927 से एसएसपी आवास है। 2003 तक इस बंगले को लेकर कोई विवाद नहीं था। वित्तीय वर्ष 2003-04 में वकील संजय धवन ने बंगले पर अपना मालिकाना हक जताते हुए कोर्ट में दावा कर दिया। ठीक से पैरवी नहीं होने के कारण कोर्ट ने एकतरफा आदेश जारी कर दावा करने वालों को पांच हजार रुपये महीना किराया देने को कहा। तत्कालीन अधिकारियों ने कोर्ट में कहा कि बंगला न खाली कराया जाए, हम किराया देने को तैयार हैं। किराया मिलना शुरू होने के बाद संजय धवन ने बंगले में 20 से अधिक कमरे बताकर किराया बढ़ाने के लिए फिर से वाद दायर कर दिया। इसमें भी अधिकारियों की लापरवाही के कारण एकतरफा आदेश हो गया। इस बार किराया बढ़ाकर 51 हजार कर दिया गया। संपत्ति के बारे में सच पता लगने पर पांच महीने पहले एसएसपी हेमराज मीणा ने प्राथमिकी दर्ज करा दी थी।

हेमराज मीणा ने बंद किया किराया देना

2024 में तत्कालीन एसएसपी हेमराज मीणा को किराये का प्रकरण सामने आने पर शक हुआ। उन्होंने संजय धवन से मालिकाना हक के दस्तावेज मांगकर जांच कराई। धवन ने एसएसपी को 1903 की उर्दू भाषा की एक रजिस्ट्री दिखाई। जांच कराने पर रजिस्ट्री विभाग में इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। प्रपत्रों की जांच कराने पर पता लगा कि ब्रिटिश हुकूमत में एसएसपी बंगले की संपत्ति एक मुस्लिम परिवार की थी, जिसे उस समय एसएसपी आवास के लिए दिया गया था। 1903 में शाहू हरगुलाल ने अकबरी बेगम से इस संपत्ति को खरीदा था। इसके बाद ये संपत्ति उनके बेटे श्रीनाथ के पास गई। संजय धवन ने खुद को इसी परिवार का वंशज बताकर दावा किया था। विवेचक राजेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग से जमीन से संबंधित प्रपत्र इकट्ठे करके जांच कर रहा हूं। कुछ प्रपत्र मिल भी गए हैं। जल्द ही इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि एसआइटी का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संपत्ति का वास्तविक मालिकाना अधिकार और पूरे खेल में शामिल विभागीय लोगों का पता लगाना है।

****

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 5 अगस्त, 2024

दैनिक जागरण

आत्मा की शुद्धि से ही परमात्मा की सिद्धि संभव है

सुधार की सही पहल

केंद्र सरकार की ओर से विवाद का विषय बने वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी समय की मांग है। इस अधिनियम में व्यापक संशोधन-परिवर्तन किए जाने की संभावना है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि इस अधिनियम में किस तरह के संशोधन-परिवर्तन होंगे, लेकिन यह तय है कि वक्फ बोर्डों को संपत्ति के दावे संबंधी जो भी मनमाने अधिकार मिले हुए हैं, उनमें कटौती होगी। यह होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति यह है कि यदि किसी राज्य का वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो बिना सत्यापन वह उसके अधिकार क्षेत्र में मान ली जाती है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि संबंधित संपत्ति उसकी है। इस तरह की व्यवस्था न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वक्फ बोर्डों को कैसे मनमाने अधिकार हासिल हैं। इसका प्रमाण तमिलनाडु के उस मामले से मिलता है जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड ने एक गांव के मंदिर और उसके आसपास की जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया था। यह इसलिए हास्यास्पद था, क्योंकि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना अर्थात इस्लाम के उदय के पहले का था। वक्फ बोर्डों की मनमानी के ऐसे अन्य अनेक मामले भी हैं।

वक्फ अधिनियम में केवल इसलिए संशोधन नहीं किया जाना चाहिए कि वक्फ बोर्डों को संपत्ति के दावे संबंधी मनमाने अधिकार मिले हुए हैं, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए ताकि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग और उन पर अवैध कब्जे का सिलसिला थमे। देश भर में वक्फ बोर्डों के पास 8.5 लाख संपत्तियां हैं, जो नौ लाख एकड़ में फैली हुई हैं। इसके बावजूद राज्य सरकारों को वक्फ बोर्डों को अनुदान देना पड़ता है। स्पष्ट है कि वक्फ की संपत्तियों का सही तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन पर केवल अवैध कब्जे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन्हें गलत तरीके से बेचा भी जा रहा है। ऐसे कुछ मामलों की जांच भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे मामले की जांच सीबीआइ की ओर से की जा रही है। वक्फ की जमीन का उपयोग घोषित उद्देश्यों अर्थात मजहबी एवं मुस्लिम समाज के कल्याण के कार्यों में ही होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है और वक्फ संपत्तियों से होने वाली कमाई का बेजा लाभ वक्फ बोर्डों पर काबिज लोग उठा रहे हैं। इसी कारण वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का लाभ मुस्लिम समाज के निर्धन-वंचित लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन-परिवर्तन के विवरण से परिचित हुए बिना कई मुस्लिम नेताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। उनके पास ले-देकर यही कुतर्क है कि मोदी सरकार की नीयत ठीक नहीं। उनकी ओर से ऐसा ही कुतर्क तीन तलाक मामले में भी दिया जा रहा था। यदि मुस्लिम नेता यह नहीं चाहते कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग जारी रहे तो उन्हें वक्फ अधिनियम में सुधार की पहल का समर्थन करना चाहिए।

एससी-एसटी एक्ट

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि बात का बतंगड़ बनाकर फंसाए गए लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान करने वाला है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित नहीं जानता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है तो ऐसे विवादों में एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में यह परंपरा बन गई है कि छोटे से छोटे विवाद में भी यदि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है तो बिना यह विचार किए कि प्रकरण सार्वजनिक अपमान का बनता है या नहीं पुलिस इस अधिनियम की सख्त धाराएं लगा देती है। इसीलिए न्यायालय ने पुलिस की विवेचना पर भी सवाल उठाते हुए उसे सतही ठहराया है। कोर्ट ने कहा, किसी चश्मदीद गवाह का बयान नहीं लिया और यह पता करने की कोशिश नहीं की कि घटना पर एससी-एसटी एक्ट का अपराध बनता भी है अथवा नहीं? किसी के चोटिल होने की रिपोर्ट नहीं है और पहचान परेड भी नहीं कराई गई किंतु चार्जशीट दाखिल कर दी गई। एससी-एसटी एक्ट के तहत समाज के वंचित व कमजोर वर्ग के सदस्यों को संरक्षण प्राप्त है कि कोई उनका अपमान न कर सके। यह एक आदर्श व्यवस्था है, यह होना भी चाहिए किंतु हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय ने इसके दुरुपयोग के प्रति चिंता भी व्यक्त की है और कई निर्णय देकर दुरुपयोग वाले बिंदुओं पर स्पष्टता दर्ज की है। कई बार तो केवल विरोधी पक्ष को फंसाने या अपनी बचत की पेशबंदी की नीयत से ही इस अधिनियम का दुरुपयोग होता है। पिछले वर्ष भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वाद में निर्णय दिया था कि जानबूझकर अपमानित करने के किसी कृत्य के लिए एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध तभी बनेगा जब यह सार्वजनिक जगह पर किया गया हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे निर्णयों से दुरुपयोग रुकेगा और पुलिस भी संवेदनशीलता के साथ विवेचना करेगी।

जल निकासी में असहाय शहर

विवेक देवराय

यदि हमें अपने शहरों को रहने योग्य बनाना है तो शहरीकरण की योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण से जुड़े उपायों को प्राथमिकता सूची में रखना होगा

आदित्य सिन्हा

हर साल मानसून के दौरान हमारे शहरी ढांचे के हाल बेहाल दिखने लगते हैं। छोटे शहरों की बात छोड़िए, थोड़ी देर की बारिश में ही मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में हाहाकार जैसी स्थिति हो जाती है। सड़कों पर पानी का सैलाब आ जाता है। खुले नालों और मेनहोल में डूबने से लेकर करंट लगने से लोगों की जान चली जाती है। बस्तियां पानी में डूब जाती हैं। परिवहन व्यवस्था अवरुद्ध हो जाती है। कुल मिलाकर, जान-माल की भारी क्षति के साथ ही लोगों को भारी असुविधा की स्थिति से दो-चार होना पड़ता है। इसके पीछे के कारणों की पड़ताल करें तो अपर्याप्त ड्रेनेज यानी नाकाफी निकासी तंत्र, अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के चलते वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन जैसे पहलू सामने आते हैं। जहां देश के अधिकांश हिस्सों में ड्रेनेज व्यवस्था इतनी लुंजपुंज है कि वह पानी की समुचित निकासी नहीं कर पाती, वहीं जल राशियों पर अतिक्रमण ने स्थितियों को और खराब कर दिया है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम कालबाह्य हो चुका है और वह भारी बारिश की स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं। ऊपर से शहरों में बढ़ता कचरा, निर्माण के बाद बचा हुआ मलबा, नालों में जमा गाद बारिश में स्थितियों को और बिगाड़ देती है। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (सीपीएचईईओ) का मानक ढांचा भी बाढ़ नियंत्रण के पुराने मापदंडों पर आधारित है। इससे समस्या और विकराल हो जा रही है। अनियोजित शहरीकरण के चलते ड्रेनेज चैनलों और प्राकृतिक जल राशियों पर अतिक्रमण बढ़ा है। इससे अतिरेक पानी की निकासी के मोर्चे पर शहर असहाय होते जा रहे हैं। डूब क्षेत्र में निर्माण जारी हैं। मिसाल के तौर पर चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का सेकेंडरी रनवे अड्यार नदी पर बनाया गया है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम में भी ऐसे निर्माण के बहुतेरे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्हें जल राशियों को पाटकर बनाया गया। सिकुड़ता हरित आवरण भी पानी को सोखने की क्षमता घटा रहा है। मौसम के बदले मिजाज ने वर्षा के तेवर भी बदल दिए हैं। ऐसे में इन स्थितियों पर नियंत्रण के प्रभावी उपाय तलाशना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य हो गया है।

इस दिशा में सबसे पहला उपाय तो ड्रेनेज सिस्टम को उन्नत बनाने के रूप में करना होगा। इसके लिए आधुनिक हाइड्रोलाजिकल डाटा के आधार पर मौसम के पैटर्न और वर्षा के हालिया रुझान का आकलन करते हुए ड्रेनेज सिस्टम को नए सिरे से तैयार करना चाहिए। नियमित तौर पर उनका बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। समय-समय पर उसकी साफ-सफाई की जाए। इन गतिविधियों के लिए विशेष वित्तीय कोष की व्यवस्था की जाए। ड्रेनेज सिस्टम को सुचारु ढंग से चलाए रखने के लिए जीआइएस मैपिंग और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि कहीं भी उसके अवरुद्ध होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को नई परिस्थितियों के अनुरूप समय-समय पर उन्नत बनाते रहना चाहिए। अभी सीपीएचईईओ के जो मानक हैं वह बाढ़ नियंत्रण के दशकों पुराने एवं अप्रासंगिक प्रारूप पर आधारित हैं, जो जलवायु परिवर्तन के चलते मौसमी परिदृश्य पर आ रहे परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हैं। यही कारण है कि एकाएक हुई तेज वर्षा के समय हमारा समूचा तंत्र चरमरा जाता है।

इस समस्या के समाधान में उस स्पंज सिटी संकल्पना को अपनाना भी उपयोगी साबित हो सकता है, जो शहरों को वर्षा के पानी को संभालने, स्टोर करने एवं उसके शोधन में सक्षम बनाता है। इस दिशा में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए फुटपाथ के नीचे जल संरक्षण, ग्रीन रूफ, रेन गार्डन और शहरी आर्द्रभूमियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इससे भूजल रीचार्ज की मुहिम को भी मजबूती मिलेगी। नई शहरी परियोजनाओं में ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के समावेश को अनिवार्य किया जाए और पुराने ढांचे को नई तकनीक से उन्नत करने पर प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की जाए। ऐसे ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर का दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उसके प्रभावी रखरखाव की दिशा में स्पष्ट नियमावली तैयार की जाए।

प्राकृतिक जल राशियों और ड्रेनेज चैनलों का प्रभावी प्रबंधन भी शहरी बाढ़ के जोखिमों को कम करने में सहायक होगा। इन पर अतिक्रमण की स्थिति में शासन-प्रशासन को शिकंजा कसना होगा और डूब क्षेत्र में निर्माण को लेकर समग्र प्रभावों का संज्ञान लेने वाली किसी व्यापक योजना पर काम करना होगा। इसमें अवैध ढांचों से मुक्ति का भी कोई मार्ग निकालना होगा। जल राशियों के निकट प्राकृतिक पर्यावास और बफर जोन के निर्माण को भी प्रोत्साहन आवश्यक है। ड्रेनेज सिस्टम को अटकाने में एक बड़ी हद तक जिम्मेदार ठोस कचरे के उचित प्रबंधन का भी उपाय तलाशना जरूरी हो गया है। इसके लिए कचरे के संग्रह से लेकर उसके प्रभावी पृथक्करण और अंततः सही निपटान का एक कारगर तंत्र विकसित करना होगा। इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कड़ाई करनी होगी। इस मामले में जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना समय की आवश्यकता बन गई है कि इस मोर्चे पर हीलाहवाली का दुष्परिणाम अंततः उन्हें ही झेलना पड़ता है।

अवधेश राजपूत

अगर हमें अपने शहरों की क्षमताएं सुधारकर उन्हें रहने योग्य बनाना है तो शहरीकरण से जुड़ी योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण से जुड़े उपायों को प्राथमिकता सूची में रखना होगा। हमें एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जो एकाएक तेज बारिश से होने वाले जलभराव से राहत दिला पाए। इन नीतियों में अपेक्षाकृत ऊंची इमारतों से लेकर सक्षम ड्रेनेज प्रणाली जैसे पहलू निश्चित रूप से शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही मौजूदा ढांचे को भी नए समय की चुनौतियों के अनुरूप प्रभावी बनाना भी उतना ही आवश्यक है।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

लैंगिक समानता की दिशा में सही कदम

ऋतु सारस्वत

बजट में नारी उत्थान के प्रति सरकार की संवेदनशीलता तो झलकती है, मगर चुनौती क्रियान्वयन के मोर्चे पर है

कार्यबल में बढ़े महिलाओं की भागीदारी। फाइल

नारी सशक्तीकरण को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सरकार ने हालिया बजट में लड़कियों एवं महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। इस राशि का उपयोग महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम, स्वयं-सहायता समूहों के लिए बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाने और उन्हें विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार देने में होगा। इन कदमों से कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा और कौशल विकास तक बढ़ती पहुंच के चलते महिला श्रमशक्ति भागीदारी दर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में 'लैंगिक बजट' पर सरकार का खर्च अब तक व्यय की जाने वाली राशि में सर्वाधिक होगा। अब यह सरकार के कुल व्यय का 6.5 प्रतिशत हो चुका है। पिछले दो दशकों का यह औसत 4.8 रहा है।

भारत में लैंगिक बजट वित्त वर्ष 2005-06 में यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया कि विकास के लाभ से आधी आबादी वंचित न रहने पाए। अन्य अनेक देशों ने भी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बजट बनाने शुरू किए हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसे बजट बनाने की शुरुआत 1984 में आस्ट्रेलिया ने की, जिसका अनुसरण कई देशों ने किया। किसी भी देश के लिए लैंगिक समानता के सभी आयामों तक पहुंच बनाने के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बजट बनाना होता है, उतना ही आवश्यक लैंगिक समानता पर दृष्टि रखने के लिए व्यापक प्रणालियों को विकसित करना भी। सक्षम प्रणालियों के बिना देश लैंगिक समानता कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए संसाधनों का आवंटन और व्यय नहीं कर सकते। 2013 में मोरक्को के वित्त मंत्रालय ने लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बजट के लिए उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की, जो सांसदों को जानकारी प्रदान करता है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक नीतियां लैंगिक समानता की दिशा में कैसे काम कर रही हैं? आस्ट्रिया वैश्विक स्तर पर उन देशों में अग्रणी है, जिसने संविधान में लैंगिक समानता को शामिल किया। अपने देश में 2005-06 में लैंगिक बजट की शुरुआत के बाद मार्च 2007 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 'जेंडर बजट सेल' स्थापित किया। इसी क्रम में 2013 में लैंगिक रूप से संवेदनशील बजट को संस्थागत करने की दिशा में एक विस्तृत निर्देशिका जारी की गई।

लैंगिक समानता की बाधाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न घटकों पर काम किया जा रहा है। चूंकि लैंगिक समानता के सभी घटक अंतर्संबंधित हैं इसलिए किसी एक की अवहेलना दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसी कारण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण के विभिन्न आयामों पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। दुनिया भर में हुए शोध यह स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता नारी सशक्तीकरण की अपरिहार्य शर्त है। वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ा व्यवधान 'प्रणालीगत पूर्वाग्रह और धारणा संबंधी' चुनौतियां हैं, जो अक्सर वित्तपोषण करने की क्षमता सीमित कर देती हैं। समाज में परंपरागत भूमिकाएं भी महिलाओं की आत्मनिर्भरता के मार्ग को दुष्कर कर देती हैं। वित्तीय स्वावलंबन के दो आयाम हैं। पहला, किसी रोजगार में संलग्न होना और दूसरा, स्वरोजगार। इन दोनों ही क्षेत्रों की अपनी-अपनी मुश्किलें हैं। शहरी क्षेत्र में रोजगार में संलग्न महिलाओं के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा सुरक्षित और किफायती आवास है। इससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति कामकाजी माताओं की है। 'वुमेन इन इंडिया इंक एचआर मैनेजर्स सर्वे' के अनुसार 34 प्रतिशत महिलाएं कार्यजीवन में असंतुलन के कारण नौकरी छोड़ देती हैं। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने का प्रविधान करके कार्यबल में महिलाओं की अहम भूमिका को मान्यता दी है। इन छात्रावासों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित एवं अनुकूल परिवेश प्रदान करना है, जिससे वे सुविधा और सुरक्षा से समझौता किए बगैर कार्य कर सकें। इसके साथ ही कामकाजी माताओं के लिए पेशेवर और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने के लिए क्रेच की घोषणा यह स्पष्ट करती है कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने का है, जिससे वे सशक्त बन सकें।

इस बार बजट में उन महिलाओं की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो उद्यम स्थापित करना चाहती हैं। एमएसएमई क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, जो बिना किसी गारंटी के ऋण पाने के लिए संघर्ष करती हैं। इन महिलाओं के लिए मुद्रा ऋण की ऊपरी सीमा को दोगुना करके 20 लाख किया जाना उत्साहवर्धक है। आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं की बाजारों और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है और उनकी क्रयशक्ति बढ़ाता है। आत्मनिर्भर महिलाएं घर एवं बाहर, दोनों ही जगह निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। वित्तीय स्वतंत्रता घरेलू हिंसा से मुक्ति का मार्ग भी है। बजट 2024-25 की घोषणाएं लैंगिक समानता और नारी सशक्तीकरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को तो स्पष्ट कर रही हैं, पर उनकी असल चुनौती क्रियान्वयन के मोर्चे पर है। महिलाओं को कौशल प्रदान करने या उनके स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की ज्यादातर पहल नेक इरादों से शुरू होकर बाद में अपनी गति को प्राप्त हो जाती है, इसलिए धन आवंटित करना ही पर्याप्त नहीं। इसके साथ एक ऐसे तंत्र को भी स्थापित करने की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करे कि लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के बजट में प्रस्तावित वित्तीय सुविधाएं प्राप्त हों।

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर दर्शन

अपनी श्रद्धा से हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, वह कहां है? यदि वह है तो हमें दिखता क्यों नहीं? सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। बुद्धि इंद्रियों के द्वारा लाई गई जानकारी को सत्य मानती है। जबकि ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियों की सीमा से परे है। संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता जैसे कि सर्दी-गर्मी, दुख-सुख इत्यादि, किंतु वे नहीं हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उनका अनुभव किया है।

सूक्ष्म परमाणुओं या जीवाणुओं को देखने के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ईश्वर को हम अपनी स्थूल इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकते। हमें अपने मन और बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म बनाना होगा। यदि तालाब जलकुंभी से भरा हुआ हो तो उसके नीचे का जल दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के विकारों ने, संसार के प्रति अतिशय आसक्ति ने हमारे आत्मा को आच्छादित कर रखा है, तो अपने भीतर परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? मन सदैव विषयों के चिंतन में लगा हुआ है। वह एक लक्ष्य पर बड़ी कठिनाई से स्थिर हो पाता है। निरंतर बहिर्मुखी रहना उसका स्वभाव बन चुका है। विषयों में, भोग में मन डूबा भी रहे और परमात्मा के दर्शन भी हो जाएं, आखिर दो विरोधाभासी बातें कैसे संभव है? ईश्वर को देखने के लिए बहिर्मुखी प्रवृत्ति को त्याग कर अपने अंतरतम में देखने की विद्या विकसित करनी होती है, जिसमें साधक वर्षों बिता देते हैं। यदि किसी छोटी कक्षा का विद्यार्थी कोई ऐसा प्रश्न करता है, जिसके अनुकूल उसके पास अभी ज्ञान ही नहीं है, तो उसे उस प्रश्न का उत्तर समझाया नहीं जा सकता। वह उसकी बुद्धि की सीमा से परे का उत्तर है। इसी प्रकार ईश्वर संबंधी किसी भी जिज्ञासा के समाधान के लिए बुद्धि को बहुत परिपक्व करना होता है। सच्चा जिज्ञासु राह ढूंढ़ ही लेता है।

टिंकल तोमर सिंह

ठगी का नया ठिकाना

सुनीता मिश्रा

साइबर ठग मेट्रोमोनियल वेबसाइटों पर फर्जी एकाउंट बना महिलाओं को आर्थिक, भावनात्मक रूप से शिकार बना रहे हैं

बीते दिनों मुंबई से अमीर तलाकशुदा महिलाओं को पहचान बदल-बदलकर अपने प्रेम जाल में फंसाने और उन्हें ठगने वाले फिरोज अहमद नियाज शेख को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने मेट्रोमोनियल वेबसाइटों पर विनय राजपूत और फिरोज शेख के नाम से दो फर्जी एकाउंट बनाए थे, जिसके माध्यम से देश की लगभग 30 से 40 तलाकशुदा हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को अपना निशाना बनाया।

वर्तमान में मेट्रोमोनियल वेबसाइटें ठगी का नया ठिकाना बन रही हैं। यहां साइबर ठग फर्जी एकाउंट बनाकर महिलाओं और उनके परिवार वालों को न केवल आर्थिक, बल्कि भावनात्मक रूप से भी ठग रहे हैं। ठगों को इन साइटों पर तलाकशुदा महिलाओं को फंसाना बेहद आसान लगता है, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। वे फर्जी प्रोफाइल बेहद आकर्षक तरीके से बनाकर साइट पर डालते हैं। इनमें वे खुद को बड़ा बिजनेसमैन, एनआरआइ या फिर एक उच्चाधिकारी के रूप में पेश करते हैं। जैसे ही कोई महिला या उसके परिवार के सदस्य उसे देखते हैं तो प्रभावित होकर बातचीत शुरू कर देते हैं। बढ़िया रिश्ता हाथ से न चला जाए यह सोचकर महिला और उसके परिवार वाले भी ज्यादा जांच पड़ताल किए बिना एक-दूसरे को जानने के बहाने अपना मोबाइल नंबर साझा कर लेते हैं। जैसे ही बातचीत शुरू होती है ठग महिलाओं को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसके बाद वे अपनी तरह-तरह की मजबूरी बताकर उनसे आनलाइन रुपये मांगना शुरू कर देते हैं। रुपये मिलने के बाद ठग अपना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं और नए शिकार की तलाश में जुट जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में शादी के रिश्तों के लिए मेट्रोमोनियल साइटों पर निर्भरता बढ़ गई है, लेकिन इस तकनीक ने जहां लोगों को सहूलियत दी है, वहीं इसके नुकसान भी हैं। इसलिए सोच-विचार कर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। साइट पर अगर रिश्ता तय कर रहे हैं तो गहनता से पड़ताल के बाद ही बात आगे बढ़ानी चाहिए। अगर लड़का या उसके परिवार का कोई सदस्य रुपये मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। किसी को भी ई-बैंकिंग या ई-वालेट से रुपये न भेजें। खासतौर पर अपने लिए नए जीवनसाथी की तलाश कर रहीं तलाकशुदा महिलाओं को किसी भी रिश्ते में जुड़ने से पहले सूझबूझ से काम लेना होगा। भावुक होकर कोई भी कदम उठाने से बचना होगा। मेट्रोमोनियल वेबसाइट पर बिना तहकीकात किए किसी पर भी विश्वास करने से बचना होगा। फर्जी एकाउंट बनाने वाले की प्रोफाइल अगर बार-बार एडिट हो रही है, तो उस पर नजर रखना होगा। लड़के को उसके नाम से इंटरनेट मीडिया पर जरूर सर्च करें।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सराहनीय पहल का न हो दुरुपयोग

'एससी-एसटी आरक्षण पर उचित फैसला' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त ने उचित ही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरक्षण की व्यवस्था का सही मायनों में विस्तार होकर सामाजिक न्याय की अवधारणा और सशक्त होगी। इस मामले में एक न्यायाधीश ने उचित ही कहा कि ट्रेन के जनरल डिब्बे में जगह पाने के संघर्ष में सफल होने के बाद जब कोई उसमें स्थान पा जाता है तो वह पूरी कोशिश करता है कि उसमें कोई और न चढ़े, क्योंकि उससे भीड़ बढ़ने की स्थिति बन सकती है। उनके कहने का आशय यही है कि एक बार किसी को कोई लाभ मिल जाए तो वह उसे साझा करने को लेकर संकोच करता है। आरक्षण के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आरक्षण के माध्यम से कुछ वर्गों का सशक्तीकरण संभव हुआ है, लेकिन यह प्रविधान अभी तक अभीष्ट की पूर्ति नहीं कर पाया है, क्योंकि इसका लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। उपवर्गीकरण के माध्यम से इसके अपेक्षित विस्तार की राह खुली है, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस सुधारवादी कदम का किसी प्रकार से दुरुपयोग न किया जाए।

रवि वार्ष्णेय, बुलंदशहर

वायनाड की अनहोनी

केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के कारण हुई भूस्खलन घटना में लगभग तीन सौ लोगों की जान जाना देश, समाज एवं पीड़ित परिजनों के लिए अपूरणीय क्षति है। कुछ समय पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जारी सावधानी सूचक आंकड़ों के अनुसार केरल में कई जिले भूस्खलन के हाटस्पाट चिह्नित हुए हैं। केरल सरकार उद्योगों और स्थानीय समुदायों के बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन को तो बढ़ावा देना चाहती है लेकिन पर्यावरण एवं भौगोलिक आकलनों पर विशेषज्ञों की चेतावनियों को नजरंदाज किया गया।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

आरक्षण का पुनर्मूल्यांकन

सुप्रीम कोर्ट का एससी-एसटी आरक्षण पर निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस पर बहस करें और इसके प्रभावों को समझें। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना है, लेकिन आज यह प्रणाली कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है। आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह देखा गया है कि शहरी और आर्थिक रूप से सक्षम लोग इस व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं, जबकि ग्रामीण और अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों के लोग इससे वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आरक्षण प्रणाली में धांधली और भ्रष्टाचार के कारण इसका उद्देश्य विकृत हो गया है। इसलिए, एक सख्त और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को मिले, जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसके लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया जा सकता है, जो इस प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करे। आरक्षण की प्रणाली का दुरुपयोग रोका जाए। आरक्षण एक अस्थायी उपाय है और इसका उद्देश्य समाज में समानता लाना है, न कि स्थायी रूप से वर्ग भेद को बढ़ावा देना। इस परिप्रेक्ष्य में, आरक्षण की अवधि और उसकी समीक्षा पर विचार करना आवश्यक है। इसके साथ ही, हमें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जानी चाहिए, जो विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचाएं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में विशेष शिक्षा और रोजगार कार्यक्रम लागू किए जा सकते हैं। अंततः, आरक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसे सही ढंग से लागू करना आवश्यक है।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

97 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी है पूरे देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात की।

आजकल

खनिज संपदा पर अधिकार का फैसला

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को खदानों तथा खनिज वाली भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के पास ऐसा करने की विधायी क्षमता तथा शक्ति है। रायल्टी को कर नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह खनन पट्टे के लिए पट्टेदार द्वारा भुगतान किया गया एक तरह का संविदात्मक प्रतिफल है। यानी खनन का पट्टा अथवा ठेका लेने के बदले दिया जाने वाला भुगतान होता है। अदालत के फैसले से खनिज एवं खदान संपन्न राज्य ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा होगा

राहुल लाल
आर्थिक मामलों के जानकार

राजस्व का बड़ा स्रोत हैं खनन गतिविधियां। फाइल

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने खदान एवं खनिज संपन्न राज्यों को भारी राजस्व के प्रोत्साहन वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आठ-एक के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि राज्यों को खदानों और खनिज वाली भूमि एवं खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के पास ऐसा करने की विधायी क्षमता और शक्ति है। रायल्टी को कर नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह खनन पट्टे के लिए पट्टेदार द्वारा भुगतान किया गया एक संविदात्मक प्रतिफल है। यानी खनन का पट्टा या ठेका लेने के बदले दिया जाने वाला भुगतान होता है। इस प्रकार से अदालत ने 1989 में इंडिया सीमेंट मामले में रायल्टी को टैक्स मानने की व्यवस्था देने वाले अपने ही फैसले को पलट दिया। इस फैसले से खनिज एवं खदान संपन्न ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा होगा।

क्या था इंडिया सीमेंट का मामला : दरअसल खदानों और खनिज वाली भूमि पर रायल्टी या टैक्स लगाने वाले राज्य सरकारों के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले को नौ जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। वैसे 1989 में तमिलनाडु सरकार और इंडिया सीमेंट के बीच भी इसी तरह का एक विवाद हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया था। इंडिया सीमेंट ने तब राज्य से खनन पट्टा हासिल किया था। कंपनी मुनाफे के एवज में राज्य सरकार को रायल्टी भरती थी, लेकिन राज्य सरकार इसके ऊपर एक उपकर (सेस) लगा रही थी। इंडिया सीमेंट इससे सहमत नहीं थी। फलतः मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कंपनी की दलील थी कि यह अतिरिक्त शुल्क असल में टैक्स ही है, जो केवल केंद्र सरकार लगा सकती है। राज्य सरकार केवल किराया वसूल सकती है, क्योंकि राज्य की जमीन इस्तेमाल में है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि यह जो अतिरिक्त शुल्क है, वह कोई टैक्स नहीं है, बल्कि उसके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए कंपनी से लिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या राज्य सरकार खनन पर रायल्टी के अलावा अतिरिक्त शुल्क वसूल सकती है? क्या यह अतिरिक्त शुल्क असल में छुपा हुआ एक टैक्स ही है? 1989 में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने तमिलनाडु सरकार के तर्क को खारिज कर दिया और इंडिया सीमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत खनन विनियमन पर केंद्र का प्राथमिक अधिकार है। राज्यों को केवल रायल्टी वसूलने की अनुमति है। अतिरिक्त करारोपण की अनुमति नहीं है। तब न्यायालय ने रायल्टी को कर रूप में वर्गीकृत किया और उस पर कोई भी उपकर लगाना राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया था।

सुप्रीम कोर्ट को क्या-क्या करना था तय : सुप्रीम कोर्ट को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआरए), 1957 की धारा नौ में निर्धारित रायल्टी के दायरे की जांच करना था। यह तय करना था कि क्या इसे 'टैक्स' कहा जा सकता है। यह भी देखना था कि क्या इस कानून की धारा 15(1) के तहत राज्य सरकारों के पास खनिजों से जुड़े नियम बनाने का अधिकार है? क्या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टि 50 राज्य सरकारों को खनिज पर टैक्स लगाने का अधिकार देती है? क्या सूची दो की प्रविष्टि 49 के तहत राज्य सरकारें जमीन और इमारतों पर टैक्स लगा सकती हैं? इंडिया सीमेंट वाला 1989 का निर्णय सही था या नहीं? एमएमडीआरए, 1957 देश में खनिज और खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है।

अब ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1989 के निर्णय को खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि वह निर्णय गलत था, जिससे खनिजों पर रायल्टी को एमएमआरडीए, 1957 के तहत कर रूप में वर्गीकृत किया गया था। राज्य विधानमंडल के पास खनिज पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति है। संसद केवल खनिज विकास में बाधाओं को रोकने के लिए सीमाएं लगा सकती है। राज्यों को खनन या संबंधित गतिविधियों पर उपकर लगाने की शक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 246 के तहत दूसरी सूची की प्रविष्टि 49 में साफ-साफ लिखा है कि खनिजों पर केवल राज्य सरकारें ही कर लगा सकती हैं। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि रायल्टी टैक्स है। इसलिए एमएमडीआरए के मुताबिक राज्य सरकारें खनिजों पर टैक्स नहीं लगा सकतीं। सूची दो की प्रविष्टि 49 के तहत ''जमीन'' में खनिज वाली जमीन शामिल नहीं होगी, क्योंकि इससे खनिज अधिकारों पर दोहरा टैक्स लगेगा। राज्यों को खनिजों पर टैक्स लगाने की इजाजत देने से राष्ट्रीय संसाधनों पर कर की एकरूपता में कमी आएगी। इससे संघीय ढांचा चरमरा सकता है। स्पष्टतः जस्टिस नागरत्ना ने 1989 के इंडिया सीमेंट वाले फैसले को सही ठहराया है, जबकि शेष आठ जजों ने उस फैसले को गलत ठहराया है।

खनन रायल्टी का फैसला कब से होगा लागू : पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कब से लागू किया जाए, इस पर सुनवाई की। कई राज्यों ने इस फैसले को पहले से ही अर्थात 1989 से लागू करने की मांग की है, जबकि केंद्र ने फैसले वाली तारीख यानी 25 जुलाई, 2024 से ही इसे लागू करने का अनुरोध किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद से शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यदि पूर्व से लागू किया जाता है, तो इससे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर 70 से 80 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। लिहाजा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह अनुच्छेद 142 का उपयोग कर राहत प्रदान करे, क्योंकि इसका प्रभाव देश के आम आदमी पर पड़ेगा। यदि इसे पूर्व से लागू किया जाता है, तो ब्याज के बिना एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम से 35 हजार करोड़ रुपये की मांग बनती है, जबकि उसका कुल नेटवर्थ 14 हजार करोड़ रुपये ही है। केवल मूलधन 35 हजार करोड़ रुपये है और ब्याज के साथ यह राशि 55 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। इस तरह एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम को उसकी संपत्ति से तीन गुना अधिक राशि की मांग का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश ने भी इस निर्णय को फैसले की तारीख से ही लागू करने की मांग की है।

वहीं ओडिशा ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू करने की मांग की है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था खराब है। खनिज समृद्ध राज्य झारखंड का भी कहना है कि फैसले को पूर्व प्रभाव रूप से लागू किया जाना चाहिए। झारखंड का कहना है कि पिछले बकाया को किस्तों के माध्यम से चरणबद्ध रूप से निपटाया जा सकता है। केंद्र द्वारा आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उठाई गई चिंताओं के बारे में झारखंड ने कहा है कि राज्यों द्वारा एकत्र किया गया धन भी आम आदमी के कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फैसले को पूर्व प्रभाव अर्थात 1989 से लागू करने की मांग की है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश का कहना है कि हिंडाल्को और कनेरिया केमिकल्स को छोड़कर सभी कंपनियां राज्य कर का भुगतान कर रही हैं। ऐसे में इस निर्णय को पूर्व प्रभाव से लागू करने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर अभी निर्णय को सुरक्षित रखा है।

राज्यों का भरेगा खजाना

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से खनन भूमि एवं खनिजों पर कर लगाने को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष समाप्त हो सकता है और राजकोषीय संघवाद की राह खुल सकती है। निर्णय में भी कहा गया है कि उचित राजकोषीय संघवाद बनाए रखने के लिए कर लगाने के राज्यों के अधिकारों को संघ के हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे खनिज प्रधान राज्यों का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। यह सच है कि खनिज संसाधनों से समृद्ध इन राज्यों को अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खनिजों से प्राप्त कर राजस्व से इन राज्यों की वित्तीय शक्ति बढ़ेगी। इसका उपयोग ये लोक कल्याण और सेवाओं के कामों में कर सकेंगे, लेकिन खनन उद्योग की चिंता भी बढ़ी है। इससे केंद्र और राज्य स्तर पर दोहरी कर व्यवस्था की मार पड़ने से खनन कंपनियों पर लागत बढ़ने से वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, जिससे उनकी नकदी प्रवाह बाधित हो सकती है और वित्तीय दायित्वों में वृद्धि हो सकती है।

हालांकि खनन उद्योग अभी इंतजार कर रहा है कि यह निर्णय 1989 से लागू होगा या 25 जुलाई, 2024 से। वैसे झारखंड ने एक अच्छा सुझाव प्रस्तुत किया है कि अगर यह 1989 से लागू किया जाता है, तो इससे बकाया राशि के ब्याज में राज्य शिथिलीकरण कर सकते हैं तथा बकाया राशि को किस्तों में भरा जा सकता है। मूलतः इस निर्णय से खनिज प्रधान राज्यों की आर्थिक स्थिति बदलने की संभावना है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि महज सात राज्यों की पूरे देश के खनिज उत्पादन में 97 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी है। ये राज्य हैं-छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। इनमें से कई राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो मजबूत हो सकती है, लेकिन अब खनिज उत्पादक राज्यों एवं केंद्र को यह भी ध्यान रखना होगा कि खनन क्षेत्र में विदेशी निवेश आता रहे और करों में अत्यधिक विषमता जैसी स्थितियां पैदा नहीं हों। इस समय केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय पर सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। ऐसे में खनन उद्योग को भी बूस्टर डोज की जरूरत होगी।

खरी-खरी

श्रीमान जी का साहित्य चिंतन

प्रभुनाथ शुक्ल

अजी! सुनते हो। जी देवी जी। आहिस्ता बोलिए, दीवार को भी कान होते हैं। देवी जी, घर में वैसे भी सिर्फ आपका शोर सुनाई देता है। संसद की तरह आप सिर्फ कहना चाहती हैं सुनना नहीं। घर का सभापति यानी मैं कितना भी आपसे निवेदन करूं, लेकिन आप हैं कि मानती नहीं हैं। एक अच्छी-खासी बहस को आप गुड़गोबर कर देती हैं। वैसे भी इस मानसून सत्र में आपके साथ अगर मेरा नाम कोई जोड़ दिया तो आपके भीतर का महिला अधिकार जाग जाता है। आप सभापति जी से तुरंत हस्तक्षेप पर उतर आती हैं। आपके साथ मेरा जुड़ना आपको अच्छा नहीं लगता। शायद, आप सहअस्तित्व को नहीं पसंद करती हैं। चलिए भाई, अब आपकी मर्जी।

हां तो आप बोलिए। आप कहना क्या चाहती हैं। बेमतलब बात की दिशा संसद के मानसून सत्र की तरफ मुड़ गई। श्रीमान साहित्यकार जी, दूधवाला आया था सुबह-सुबह धमकी देकर गया है, उसका तीन महीने का बकाया है। कल से दूध बंद और चाय को भी तरसोगे। नगर निगम से जलकर वालों ने नोटिस भेजा है। उसका छह माह का बकाया है। बिजली वाले ने बिल भुगतान न होने पर कनेक्शन काट दिया है। जनाब अब अंधेरे में साहित्य साधना करनी होगी। सौ में से अस्सी जगह से रचनाएं संपादक सखेद लौटा देते हैं। आएं हैं बड़े साहित्यकार बनने।

श्रीमान जी! देश बदल रहा है, लेकिन लल्लू लाल बदलने से रहे। दिन-रात कंप्यूटर बाबा के साथ बंद कमरे में साहित्य साधना करते रहते हैं। मौसम का मिजाज देख बदलना सीखो। जमाना प्रयोगवादी है। अब सिर्फ प्रगतिवादी सोच से नहीं, प्रयोगवादी व्यवस्था से काम चलेगा। कंप्यूटर पर अंगुलियां घिसते रह जाओगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। जुगाड़ लगाओ। आज कल सब काम जुगाड़ से होता है। अब अपना नजरिया बदलो। साहित्य को साधना नहीं, आराधना का माध्यम बनाओ। फिर देखो क्या होता है। तमाम पुरस्कार आपकी झोली में होंगे। बड़े-बड़े साहित्यकार आपकी चरण वंदना में होंगे। इसीलिए कहती हूं साधना नहीं आराधना करो।

पोस्ट

पेरिस ओलिंपिक में निशानेबाज मनु भाकर का सफर स्वर्णिम सफलता वाला रहा। किसी भी खिलाड़ी के लिए यह बेहद दुर्लभ होता है कि वह एक ही ओलिंपिक में दो पदक हासिल करने के साथ ही तीसरे पदक से बहुत मामूली अंतर से चूक जाए। वह अभी महज 22 साल की हैं और उनसे 2028 के लास एंजिलिस ओलिंपिक खेलों समेत एशियाई खेलों में बड़ी उम्मीदें होंगी।

द सोशल साइंटिस्ट@socially321

बैडमिंटन में दो बार के ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता विक्टर एक्सेलसन का खेल दर्शाता है कि चैंपियन खिलाड़ी सेमीफाइनल जैसे निर्णायक मुकाबलों में कैसे वापसी करते हैं। हालांकि, लक्ष्य सेन की क्षमताओं पर किसी को कोई संदेह नहीं। लक्ष्य को खेलते देखने का अनुभव अद्भुत होता है।

हर्षा भोगले@bhogleharsha

ओलिंपिक में भारतीय हाकी के लिए गौरवशाली अध्याय। एक खिलाड़ी के शुरू में ही बाहर होने के बावजूद भारत जीता। गोलकीपर श्रीजेश हाकी की अभेद्य दीवार हैं। यह भारतीय टीम सोना जीत सकती है। हार से इसे नफरत है। जबरदस्त टीमवर्क दिख रहा है।

सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या ईरान-इजरायल टकराव पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करके सही किया?

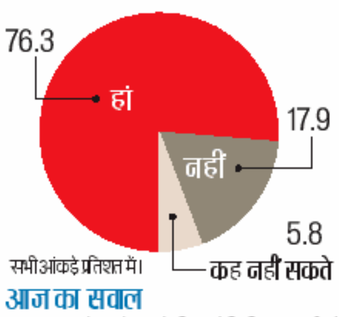

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आपको भरोसा है कि ओलिंपिक हाकी में गोल्ड मेडल का इंतजार खत्म होने वाला है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पीढ़ी दर पीढ़ी मिला आरक्षण का क्रीम,
पूरा होने दीजिए औरों का भी ड्रीम।
औरों का भी ड्रीम पहल खुद करिए भाई,
वंचित को भी आज मिले नौकरी-पढ़ाई।
स्वयं मलाई खाय हड़प लोगे यदि सीढ़ी,
कैसे आगे जाय गरीबों वाली पीढ़ी?

- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

नजूल जमीन हथियाने का खेल और बैकफुट पर भाजपा

अजय जायसवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, उत्तर प्रदेश

नजूल मतलब सरकारी जमीन यूं तो देशभर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति को लेकर प्रस्तावित कानून पर इन दिनों राजनीतिक माहौल गर्म है। करोड़ों रुपये की नजूल जमीन को कौड़ियों में हथियाने के वर्षों से चल रहे 'खेल' पर कड़ाई से अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने आगे कदम बढ़ाया तो 'विरोधी' ही नहीं, 'अपने' भी सरकार का साथ देते नहीं दिखाई दिए। विरोधियों से ज्यादा अपनों की मुखालफत देख योगी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ जब उच्च सदन (विधान परिषद) में बहुमत होने के बावजूद किसी विधेयक को पारित न कराया गया हो। भाजपा सरकार बैकफुट पर आई तो अब विधेयक के भविष्य को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को करीब से जानने वालों का स्पष्ट तौर पर मानना है कि अंततः उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) कानून, राज्य में लागू होकर रहेगा, भले ही अपने भी क्यों न रूठे दिखाई दें।

नजूल जमीन है क्या? आजादी के पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वालों में से बहुतों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। अंग्रेज विद्रोह करने वाले आम आदमी से लेकर राजाओं तक की जमीन पर कब्जा कर लेते। स्वतंत्रता के बाद जिन जमीनों के वारिस अंग्रेजों द्वारा कब्जाई अपनी जमीन को वापस लेने के लिए नहीं आए, उनका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास हो गया। यही जमीनें नजूल भूमि कहलाईं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लगभग दो लाख करोड़ रुपये की 75 हजार एकड़ से अधिक जमीन बतौर नजूल सरकारी दस्तावेज में दर्ज है। 1993 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्व गृह सचिव एनएन वोहरा की अगुआई में गठित समिति ने नजूल जमीन को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था 'बड़े शहरों में आय का मुख्य स्रोत अचल संपत्ति से जुड़ा है। भूमि/भवनों पर जबरन कब्जा करना, मौजूदा निवासियों/किराएदारों को बाहर निकालकर सस्ते दामों पर ऐसी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त हो रही है।'

वोहरा समिति की रिपोर्ट पर तीन दशक के दौरान कुछ नहीं हुआ, पर इस बीच बड़े पैमाने पर नजूल भूमि पर अवैध कब्जे होते रहे। पूर्व में चाहे सपा-बसपा की सरकार रही हो या फिर भाजपा गठबंधन की, सभी में भ्रष्टाचार के दम पर दस्तावेजों में हेरा-फेरी कर नजूल जमीन को फ्रीहोल्ड कर कब्जाने का 'खेल' खेला गया। फर्जी दस्तावेजों के दम पर करोड़ों रुपये की नजूल भूमि को सर्किल रेट का सिर्फ 10 प्रतिशत देकर फ्रीहोल्ड कराने का खेल चलता रहा। लखनऊ के अलावा प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, गोंडा आदि जिलों में नजूल की खूब जमीन है। प्रयागराज का लगभग पूरा सिविल लाइंस क्षेत्र ही नजूल की जमीन पर है। कहते हैं कि यहां के एक-एक बंगले 100 से 250 करोड़ रुपये तक के हैं। सर्किल रेट 50 करोड़ रुपये ही होने से लोग सिर्फ 10 प्रतिशत यानी पांच करोड़ रुपये में फ्रीहोल्ड कराकर 100 करोड़ रुपये के बंगले के मालिक बनते रहे हैं। नजूल जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में 2500 से अधिक केस लंबित हैं। योगी का ध्यान जब नजूल जमीन के खेल की ओर गया तब पता चला कि नजूल एक्ट में तो फ्री होल्ड करने जैसा कोई प्रविधान ही नहीं है। इसके बावजूद अब तक अरबों रुपये की कम से कम 25 प्रतिशत नजूल जमीन को जैसे-तैसे फ्री होल्ड किया जा चुका है। अब इस पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने पहले-पहल उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश-2024 को सात मार्च से लागू किया जिससे नजूल भूमि का बारा-न्यारा करने वालों में मची खलबली की झलक विधानमंडल के मानसून सत्र में देखने को मिली।

नजूल जमीन को कब्जाने के 'खेल' पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने बढ़ाया कदम। फाइल

अध्यादेश को अधिनियम बनाने के लिए विधानसभा में तो विपक्ष के कड़े विरोध एवं सत्तापक्ष के संशोधन प्रस्ताव के साथ विधेयक पारित हो गया, लेकिन अगले दिन विधान परिषद में उसे पारित कराने से सत्ताधारी भाजपा ही पीछे हट गई। बहुमत के बावजूद विधेयक प्रवर समिति को भेजकर अटकाने के पीछे कहा जा रहा है कि विपक्ष द्वारा प्रस्तावित कानून को जनविरोधी बताते हुए बड़ा मुद्दा बनाने से पहले ही उसकी धार कुंद करने के लिए ऐसा किया गया। चूंकि विधानसभा की 10 सीटों के जल्द ही उपचुनाव होने हैं। हाल ही के लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जनता को गुमराह कर भाजपा का नुकसान न कर सके इसलिए फिलहाल अपनों की बात मानते हुए योगी पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं। चूंकि विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे वास्तव में आम जनता में किसी तरह की नाराजगी बढ़े इसलिए माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में इसे पारित कराया जा सकता है।

प्राकृतिक आपदा

समय पूर्व चेतावनी की जरूरत

ज्ञानेंद्र रावत
पर्यावरण मामलों के जानकार

कमजोर होते पहाड़ों के कारण बढ़ रहीं भूस्खलन की घटनाएं। फाइल

भूस्खलन, भूकंप और बादल फटने की घटनाएं अब रोजमर्रा की बात हो गई हैं। फिर पहाड़ों पर रहने वालों के लिए तो ये अभिशाप की तरह हैं, क्योंकि इन आपदाओं के शिकार सबसे ज्यादा पहाड़वासी ही होते हैं। वह बात दीगर है कि इन घटनाओं के पीछे मानवीय गतिविधियों की अहम भूमिका होती है। विकास के नाम पर पहाड़ों का बेदर्दी से विनाश वर्तमान की सबसे बड़ी विडंबना है। वनों का बेतहाशा कटान, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं और वहां बहुमंजिला भवनों का निर्माण इसका अहम कारण है। पहाड़ों के विनाश के साथ उनको दरकने से बचाने के जो उपाय किए जाने चाहिए थे, उनका अभाव भी इन आपदाओं की भयावहता को और बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कहने को देश में इस बाबत दिशा-निर्देश हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते उनका सही मायने में क्रियान्वयन न होना ऐसी आपदाओं से हुई तबाही की विकरालता को भयावह बना देता है।

सबसे बड़ी दुखदायी और विकट समस्या समय पूर्व चेतावनी प्रणाली का अभाव है जिसे सरकारें देश में पूरी तरह स्थापित कर पाने में आज तक नाकाम रही हैं। इससे जान-माल के नुकसान से बचा जा सकता है। केरल में वायनाड की ताजा घटना इस बात की जीती-जागती मिसाल है कि यदि वहां समय पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित होता तो भूस्खलन से हुई भयावह तबाही से बचा जा सकता था। समझ नहीं आता कि सरकारें इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं। यह अच्छी बात है कि राहत के काम में राज्य की सभी सरकारी एजेंसियों के अलावा सेना की टुकड़ियां चिकित्सा कर्मियों के साथ रात-दिन जुटी हैं और मलबे में दबे लोगों को निकालने के साथ राहत एवं बचाव कार्य को बखूबी अंजाम दे रही हैं। यहां यह विचारणीय है कि इस घटना से राज्य में दो दिन के शोक, मृतकों को दो लाख एवं घायलों को 50 हजार रुपये देने की सरकारी घोषणा आपदा का स्थायी उपचार नहीं है। केरल के मुंडक्कई, चूरतमाली, अट्टमाला और नूलपुझा गांवों की भूस्खलन की चपेट में आने के बाद तस्वीर ही बदल गई है। अब वहां खंडहर हुए मकान, उफनती नदी और उखड़े पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के मकान तो अब भी हिल रहे हैं।

गौरतलब है कि बरसात के इस मौसम में पहाड़ों पर दबाव काफी बढ़ जाता है और पहाड़ भरभराकर गिरने लगते हैं। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पिछले दिनों यही हुआ है। ऐसी स्थिति में पहाड़ पर कितना दबाव है, इसका पता लगाने के लिए दबाव मापी यंत्र लगाना चाहिए, जिससे दबाव की स्थिति मालूम पड़ सके। वहां आस-पास के लोगों को पहाड़ के दरकने की पूर्व सूचना देकर जानमाल के खतरे को कम से कम किया जा सके, ताकि वहां के रहवासी समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंच अपनी जान बचा सकें। ताइवान ने अपने यहां इस तंत्र का प्रयोग वर्षों पहले कर लिया है, लेकिन दुखद यह कि हमारी सरकारें दूसरों से कुछ सीखने और कुछ करने को तैयार ही नहीं हैं। उस स्थिति में भी, जबकि हिमाचल के 42,093 वर्ग किलोमीटर भूस्खलन प्रभावित चिह्नित क्षेत्र में 17,102 स्थानों पर भूस्खलन की आशंका व्यक्त की गई है। यही नहीं, 6,420 सक्रिय भूस्खलन और उच्च संवेदनशीलता के 26 प्रतिशत क्षेत्र खतरनाक स्थिति में हैं। वहां कभी भी भूस्खलन भीषण तबाही का सबब बन सकता है। इसकी जानकारी तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग हिमाचल सरकार को 2022 में ही दे चुका है। यह तो तब है, जबकि राज्य के लोग बीते साल आई प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से वैसे ही भयभीत हैं। फिर उत्तराखंड में मसूरी रोड पर स्थित पहाड़ी पर भूस्खलन का दायरा 95 मीटर तक फैल चुका है जिससे लोगों में काफी दहशत है। हालात की भयावहता का आलम यह है कि एक भूस्खलन संभावित क्षेत्र का उपचार किया जाता है, तभी दूसरा क्षेत्र सक्रिय हो जाता है। चिंता इस बात की है कि यदि 17,102 भूस्खलन संभावित क्षेत्र में यह दबाव बढ़ा तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा और उस स्थिति में तबाही का आंकड़ा भयावहता की सीमा को पार कर जाएगा।

सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वायनाड की घटना एक चेतावनी है, क्योंकि इस तथ्य से सभी भलीभांति परिचित हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक के पहाड़ों के चरित्र में कोई खास बदलाव नहीं है। उसमें कमोबेश एकरूपता ही परिलक्षित होती है। वह बात दीगर है कि उत्तर के मुकाबले दक्षिण के पहाड़ों की मिट्टी थोड़ी सख्त है, लेकिन जब हम पहाड़ों की मिट्टी को थामने वाले प्राकृतिक तत्व कहें या साधनों का ही विनाश करते जाएंगे, उस दशा में पहाड़ों को दरकने से कोई नहीं रोक सकता। जब पत्थर पहाड़ से टूटकर सड़क, गांव या नदी में आकर गिरते हैं और सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने, गांव के गांव को जमींदोज करने और नदी के प्रवाह में भयावह स्तर पर तेजी का सबब बनते हैं, उस दशा में भूस्खलन को रोक पाना किसी के बूते के बाहर की बात है। जब तक पूरे देश में आपदा पूर्व सूचना प्रणाली तंत्र स्थापित नहीं होता, तब तक ऐसे हादसों के निदान की कल्पना ही बेमानी है।

****

101 हवाई अड्डों के रखरखाव पर 796 करोड़ खर्च

नई दिल्ली: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) ने बीते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 101 हवाई अड्डों की मरम्मत और रखरखाव पर 796 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसमें इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एएआइ ने हवाई अड्डों की मरम्मत और रखरखाव पर 663.42 करोड़ रुपये खर्च किए थे। पिछले वर्ष 20 हवाई अड्डों पर मरम्मत और रखरखाव पर कोई राशि खर्च नहीं हुई। (प्रेट्र)

मार्च 2026 तक हमने 100 शोरूम खोलने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 50 शोरूम मार्च 2025 तक खोले जाएंगे।

— अरविंद मणी, सीईओ, रिवर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड

एक नजर में

आठ कंपनियों का पूंजीकरण 1.28 लाख करोड़ घटा

नई दिल्ली: बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से आठ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण बीते सप्ताह 1.28 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। इस दौरान टीसीएस के पूंजीकरण में सबसे ज्यादा 37,971 करोड़ रुपये की गिरावट रही है। इसके अलावा टीसीएस, आइटीसी, एसबीआइ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, आइसीआइसीआइ बैंक और एचयूएल का पूंजीकरण घटा है। (प्रेट्र)

32 स्टार्टअप्स ने 34 करोड़ डालर की राशि जुटाई

नई दिल्ली: बीते सप्ताह भारतीय स्टार्टअप्स ने 34.1 करोड़ डालर की राशि जुटाई है। इस दौरान ग्रोथ स्टेज के छह स्टार्टअप्स ने 21.6 करोड़ डालर जुटाए हैं। इसमें 12 करोड़ डालर की राशि के साथ मोबिलिटी स्टार्टअप रेपिडो शीर्ष पर रहा है। पैसा जुटाने वाले अन्य स्टार्टअप्स में फिनटेक फर्म नावी, भारतपे और स्पोर्ट्स टेक कंपनी खेलोमोर शामिल हैं। (आइएएनएस)

डेयरी उद्योग के राजस्व में 13-14% की वृद्धि संभव

नई दिल्ली: रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय डेयरी उद्योग के राजस्व में 13-14 प्रतिशत की वृद्धि रह सकती है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि उपभोक्ता मांग मजबूत बनी हुई है और कच्चे दूध की आपूर्ति में भी सुधार हुआ है। एजेंसी के वरिष्ठ निदेशक मोहित मखीजा का कहना है कि होटल, रेस्त्रां और कैफे से भी डेयरी उद्योग की राजस्व वृद्धि में मदद मिलेगी। (एएनआइ)

चालू वित्त वर्ष में 7-8% बढ़ सकती है सीमेंट की मांग

नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में सीमेंट की मांग में 7-8 प्रतिशत की वृद्धि रह सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पूरे देश में निर्माण गतिविधियों में वृद्धि से सीमेंट मांग बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए उद्योग अगले वर्ष तक उत्पादन क्षमता में 3.5 से चार करोड़ टन प्रति वर्ष की वृद्धि कर सकता है। (प्रेट्र)

सरकारी बैंकों की विलय प्रक्रिया में फिर तेजी संभव

वित्तीय क्षेत्र के लिए तीन से छह माह में जारी हो सकता है विजन डाक्यूमेंट, बजट में हुई थी घोषणा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वर्ष 2019 में सरकारी क्षेत्र के 10 बैंकों को मिलाकर चार बैंकों में बदलने के बाद बैंकिंग विलय पर सरकार की चुप्पी अब टूट सकती है। आम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन उन्होंने देश के वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधार व बदलाव के लिए एक विजन डाक्यूमेंट और रणनीति जारी करने की बात कही थी। सरकार के भीतर होने वाले इस विमर्श की जानकारी रखने वालों का कहना है कि वित्तीय क्षेत्र की यह रणनीति देश के भावी वित्तीय क्षेत्र के विस्तार, नियमन, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, बैंकिंग पेशेवरों के प्रशिक्षण के साथ ही यह भी बताएगा कि सरकारी क्षेत्र में कितने बैंक होने चाहिए और इन बैंकों का आकार क्या होना चाहिए। यह तय है कि अभी सरकार की मंशा बैंकिंग सेक्टर से पूरी तरह से बाहर निकलने की नहीं है। वित्त मंत्रालय यह प्रपत्र तीन से छह महीनों में जारी कर सकता है।

- वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधार का रोडमैप देगा विजन डाक्यूमेंट
- सरकारी बैंकों की जरूरी संख्या और आकार भी बताएगा यह प्रपत्र

10 बैंकों को मिलाकर चार बड़े बैंक बनाए गए थे वर्ष 2019 में

12 बैंक इस समय काम कर रहे हैं देश में सार्वजनिक क्षेत्र के

वित्तीय सेक्टर की भूमिका में बदलाव का रोडमैप देगा प्रपत्र

यह डाक्यूमेंट बताएगा कि वित्तीय क्षेत्र किस तरह से देश के सभी उद्योगों, स्टार्टअप और छोटे व मझोली औद्योगिक इकाइयों को विकास के लिए कर्ज मुहैया करा सकता है। साथ ही युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए वित्तीय सेक्टर की मौजूदा भूमिका में भी बदलाव का रोडमैप देगा। यह बताएगा कि सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की भूमिका क्या होगी। यह वित्तीय सेक्टर में विदेशी निवेश को आसान बनाएगा और इनमें प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर भी एक स्पष्ट दिशानिर्देश का संकेत होगा। इस रोडमैप को लागू करने में आरबीआइ की अहम भूमिका होगी। दूसरी अन्य नियामक एजेंसियां जैसे सेबी, आइआरडीए आदि के लिए भी अलग-अलग रोडमैप होगा। इस प्रपत्र के आधार पर ही भावी नियमन के लिए उक्त एजेंसियां कदम उठाएंगी।

वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2019 में सरकारी क्षेत्र के दस बैंकों को मिलाकर चार बैंक बना दिया गया था। इसके पहले भारतीय स्टेट बैंक में सभी सात सब्सिडियरी बैंकों और बैंक आफ बड़ौदा व देना बैंक को मिलाया गया था। इस बीच वर्ष 2022 के आम बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी, लेकिन वह भी नहीं हो पाया है। विलय की वजह से सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घट कर 12 रह गई है। इसके बावजूद विश्व के 50 सबसे बड़े बैंकों में सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) 48वें स्थान पर है। ऐसे में माना जाता है कि भारतीय बैंकों का मौजूदा ढांचा वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की जरूरत के अनुरूप आवश्यक फंड उपलब्ध नहीं करा सकता। वित्त मंत्री ने इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेक्टर के लिए विजन डाक्यूमेंट पेश करने का ऐलान किया था। अधिकारियों के मुताबिक, भारत के वित्तीय सेक्टर को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भावी विजन डाक्यूमेंट एक अहम कदम होगा।

ब्याज दरों में कमी के लिए लंबा हो सकता है इंतजार

नई दिल्ली, प्रेट्र: ब्याज दरों में कमी करने वालों का इंतजार और लंबा हो सकता है। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि इस सप्ताह होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में भी आरबीआइ रेपो रेट को एक बार फिर 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रख सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में कटौती करने से पहले अधिक व्यापक आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर सकता है। एमपीसी की बैठक छह अगस्त को शुरू होगी। गवर्नर शक्तिकांत दास आठ को एमपीसी के फैसलों की जानकारी देंगे।

- छह से आठ अगस्त के बीच होगी मौद्रिक नीति समिति की बैठक
- विशेषज्ञ बोले, रेपो रेट फिर 6.5% पर बरकरार रहने की उम्मीद

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बीते सप्ताह हुई बैठक में ब्याज दरों पर यथास्थिति बनाए रखते हुए संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में मौद्रिक नीति में ढील दी जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई के दबाव के बीच आरबीआइ अपना रुख बदलने से पहले अमेरिकी मौद्रिक नीति पर बारीकी से नजर रखेगा। एमपीसी भी दर में कटौती से परहेज कर सकती है। इसका कारण यह है कि भले ही रेपो रेट 6.5 प्रतिशत तक बढ़ा हो, लेकिन आर्थिक वृद्धि अच्छी बनी है।

बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने उम्मीद जताई है कि आगामी नीतिगत समीक्षा में आरबीआइ यथास्थिति बनाए रखेगा। महंगाई आज भी 5.1 प्रतिशत के उच्चस्तर पर बनी हुई है और आने वाले महीनों में इसमें कमी आएगी।

लाभ वाले कारोबार पर ध्यान दें सरकारी साधारण बीमा कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों से कहा है कि वे लाभ वाले कारोबार पर ध्यान दें और लाभप्रदता में सुधार लाने का लक्ष्य रखें। सरकार ने हाल ही में तीन साधारण बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को किस्तों में 7,250 करोड़ रुपये दिए हैं।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा कि हम इन कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रख रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उनमें सुधार आने लगा है। इस वर्ष भी उनके प्रदर्शन पर नजर रखेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन कंपनियों को और पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि बजट में कोई प्रविधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों कंपनियों ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार किया है।

दूरसंचार कंपनियों को पसंद नहीं आए सेवा में सुधार के नए नियम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में दूरसंचार का बड़ा नेटवर्क है लेकिन इसकी गुणवत्ता अभी भी संतुष्टि से कोसों दूर है। अब टेलीकाम रेग्युलेटर ट्राई ने गुणवत्ता सुधारने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें मोबाइल सेवा 24 घंटे से ज्यादा बाधित रहने पर उसकी भरपाई करने, गुणवत्ता को लेकर गलत सूचना देने पर दंड लगाने जैसे प्रविधान शामिल किए गए हैं। यह दिशा-निर्देश कंपनियों को रास नहीं आ रहे हैं।

मोबाइल सेवा देने वाली कंपनियों के संगठन सीओएआइ ने रविवार को इस बारे में अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि नए नियमों से उनकी लागत बढ़ेगी। यानी इसका असर काल व डाटा दरों पर भी हो सकता है। सीओएआइ के महानिदेशक ले. जनरल एसपी कोचर का कहना है कि ट्राई लगातार सेवा गुणवत्ता सुधारने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करता है। लेकिन कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। सीओएआइ का कहना है कि काल की गुणवत्ता उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए वह संबंधित एजेंसियों से लगातार विमर्श करते रहेंगे। मोबाइल कंपनियों का कहना है कि अभी वह 5जी सेवाओं के विस्तार में जुटी हैं, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ गैर-कानूनी तौर पर बूस्टर लगाने, मशीनों की चोरी होने की समस्या जस की तस बनी हुई है। ट्राई का नया दिशा-निर्देश चिंताजनक है। नए नियमों के मुताबिक, कंपनियों को हर महीने सेवा गुणवत्ता रिपोर्ट देनी होगी।

- दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआइ ने जताई नाराजगी
- कहा, समस्याओं के समाधान पर कोई कदम नहीं उठाता ट्राई

2034 तक 55 अरब डालर हो सकता है विदेशी पर्यटन पर खर्च

नई दिल्ली, प्रेट्र: विदेशी पर्यटन पर भारतीयों का खर्च 2034 में बढ़कर 55.39 अरब डालर तक पहुंच सकता है जिसके 2024 में 18.82 अरब डालर रहने का अनुमान है। नांगिया एनएक्सटी और फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के विदेशी पर्यटन बाजार में अभी भी पैकेज्ड टूर की बड़ी हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में कुल विदेशी पर्यटन में पैकेज्ड टूर की 39.20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय या शाकाहारी भोजन के विकल्पों की उपलब्धता के साथ विशिष्ट पर्यटन के बारे में जागरूकता आने वाले वर्षों में विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगी। डिजिटल प्लेटफार्म ने यात्रियों के लिए योजना बनाना और बुकिंग करना आसान बना दिया है। इंटरनेट मीडिया ने भारतीयों को आकर्षित करने के नए अवसर खोले हैं।

एफएंडओ को हतोत्साहित करने से बैंक जमा बढ़ाने में होगी मदद

मुंबई, प्रेट्र: एसबीआइ के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का कहना है कि वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) या डेरिवेटिव बाजार से खुदरा निवेशकों को हतोत्साहित करने से बैंकिंग प्रणाली को बेहद जरूरी जमा जुटाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि शार्ट-टर्म और लांग-टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर बजट में किए गए बदलावों से जमा बढ़ाने के नजरिये से ज्यादा फायदा नहीं होगा।

खारा ने कहा कि रेग्युलेटरों की ओर से खुदरा निवेशकों के लिए एफएंडओ (वायदा और विकल्प) जैसी चीजों को हतोत्साहित किया जा रहा है। जो लोग इस तरह के साधन का सहारा ले रहे हैं, वे बैंकिंग प्रणाली में वापस आ सकते हैं। बता दें कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में 90 प्रतिशत निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में यह आशंका पैदा हो रही है कि परिवारों की बचत उत्पादक उद्देश्यों में लगने के बजाय सट्टेबाजी में उड़ रही है। एसबीआइ के चेयरमैन ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से जमा वृद्धि ऋण में बढ़ोतरी के साथ तालमेल बैठाने में असमर्थ है। यह पैसा वैकल्पिक साधनों मसलन पूंजी बाजार में जा रहा है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंक खाता परिवारों की बचत को जमा करने का प्रमुख साधन है और इस पर ब्याज मिलता है।

दिनेश कुमार खारा

एसबीआइ चेयरमैन ने कहा, बजट में कैपिटल गेन्स में बदलाव करने से जमा बढ़ाने के नजरिये से ज्यादा फायदा नहीं होगा

स्वच्छ तकनीक की नीतिगत रूपरेखा का इंतजार : भार्गव

नई दिल्ली, प्रेट्र: मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआइ) के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि कंपनी एक ऐसी नीतिगत रूपरेखा का इंतजार कर रही है, जो सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे, जिससे पेट्रोल और डीजल कारों के स्थान पर ऐसी पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले वाहन आ जाएं।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में भार्गव ने कहा कि औद्योगिक वृद्धि के लिए नीतियों में स्थिरता और पूर्वानुमानित कार्य वातावरण की आवश्यकता होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण, राजकोषीय विवेक बनाए रखने, महंगाई को नियंत्रण में रखने, विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने वाले सुधारों को लागू करने और निजी क्षेत्र पर भरोसा करने पर अपना जोर जारी रखेगी।

राष्ट्रीय फलक

भारत में रहते हुए बांग्लादेशी ने बदल ली पहचान, विदेश से लौटे तो सामने आई सच्चाई, गिरफ्तार

गौतम कुमार मिश्रा ● जागरण

नई दिल्ली: आइजीआइ एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान दो ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो खुद को भारतीय नागरिक बताकर विदेश गए थे। इन्होंने अपने असली पासपोर्ट के सहारे बांग्लादेश से भारत में तो प्रवेश पा लिया लेकिन यहां से जब वे विदेश के लिए निकले तो इन्होंने अपनी बांग्लादेशी पहचान छिपाकर भारतीय पहचान का सहारा लिया और निकल गए। अब जब ये वापस लौटे तो इनकी असलियत सामने आई। बहरहाल आइजीआइ थाना पुलिस दोनों ही मामलों की जांच में जुटी है। पुलिस के रडार पर फिलहाल कई एजेंसियों से जुड़े लोग हैं। इनमें पासपोर्ट कार्यालय, बंगाल पुलिस सहित कई एजेंसी शामिल हैं।

पहले मामले में 30 जुलाई की रात रिपन राय नामक यात्री कोरिया से भारत लौटा। अराइवल इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान जब इसके कागजात पर गौर किया गया तो पता चला कि इसे कोरिया से डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट का कारण फर्जी दस्तावेजों के सहारे कोरिया की यात्रा करना था। जब इमिग्रेशन वालों ने इससे पूछताछ कि तो पहले तो इसने अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन सघन पूछताछ में इसने सच्चाई बयां कर दी। इसने बताया कि इसका असली नाम सोहेल बरुआ सुमन है। यह वर्ष 2016 में बांग्लादेशी पहचान पर भारत में दाखिल हुआ। यहां लंबा समय बिताने के बाद यह एक एजेंट के संपर्क में आया और उसने इसके लिए भारतीय पहचान से जुड़े दस्तावेज बना दिए। बाद में इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इसका पासपोर्ट बन गया। पासपोर्ट में इसका पता बंगाल का 24 परगना जिला दर्शाया गया, जबकि यह मूल रूप से बांग्लादेश के काक्स बाजार का रहने वाला था। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो गलती कोरिया में इमिग्रेशन वालों ने पकड़ी वह गलती शुरूआत में ही क्यों नहीं पकड़ी गई। दूसरे मामले में 31 जुलाई को बैंकाक से आई उड़ान से आयुष्मान बरुआ नामक यात्री नई दिल्ली पहुंचा। यहां इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान अधिकारियों ने इससे जब सवाल पूछने शुरू किए तो यह सही तरीके से प्रश्नों का सामना करने की स्थिति में नहीं था। इससे अधिकारियों को संदेह हुआ और सवाल पर सवाल पूछने का सिलसिला चला। इसी दौरान वह टूट गया और अधिकारियों को बताया कि यह भारतीय नहीं बांग्लादेशी नागरिक है। वर्ष 2015 में वह बंगाल आया और यहां इसने फर्जी दस्तावेज बना लिए। इसी के आधार पर इसका पासपोर्ट भी बन गया।

- एक को कोरिया तो दूसरे को थाइलैंड से लौटने पर किया गया गिरफ्तार
- आइजीआइ थाना पुलिस कर रही दोनों मामले की जांच

पीएम ने रिकार्ड गैस उत्पादन की सराहना की

नई दिल्ली, आइएएनएस: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को रिकार्ड गैस उत्पादन की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक और कदम बताया। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इस उपलब्धि के लिए देश के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। यह रिकार्ड गैस उत्पादन इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 36.43 अरब क्यूबिक फीट (बीसीएम) गैस उत्पादन किया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 28.7 बीसीएम था। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 तक देश में गैस उत्पादन 45.3 बीसीएम तक पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारत नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आंकड़े इसका सुबूत हैं।

2025 से सरकारी संस्थानों में ही होगी नीट यूजी परीक्षा

जागरण संवाददाता, पटना

एनटीए नीट यूजी 2025 में केंद्र चयन का तरीका बदलेगा। अब सरकारी संस्थान में ही परीक्षा केंद्र होगा। केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी और पहचान प्रक्रिया के लिए नई टेक्नोलाजी का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जाएगा। शिकायतों की जांच और निपटाने के लिए अलग से पोर्टल विकसित किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा की तैयारी भी होगी। एनटीए अभ्यर्थियों, परीक्षा केंद्र के कर्मी और शिक्षकों की काउंसलिंग कराएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाएगा। एनटीए बताएगा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर एनटीए की कड़ी नजर है।

उमंग व डिजिलाकर से डाउनलोड कर सकेंगे नीट यूजी की ओएमआर सीट: अब उमंग व डिजिलाकर प्लेटफार्म से भी अभ्यर्थी नीट यूजी की ओएमआर शीट को डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने उम्मीदवारों का डाटा उमंग और डिजिलाकर प्लेटफार्म पर अपलोड करने का निर्णय किया है। यह निर्णय एजेंसी ने नीट ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद लिया है। जिन उम्मीदवारों ने नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वह उमंग व डिजिलाकर प्लेटफार्म पर पुष्टिकरण पृष्ठ, स्कोर कार्ड और ओएमआर उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई तस्वीर भी डाउनलोड कर सकेंगे। यदि किसी उम्मीदवार को समस्या होती है तो वह 011- 40759000/011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं या neet@nta.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

- ओएमआर डाउनलोड करने में समस्या हो तो 011- 40759000 और 011-69227700 पर करें संपर्क
- neet@nta.ac.in पर भी कर सकते हैं ई-मेल

नकली क्रिप्टोकरंसी मामले में लेह में ईडी ने एक करोड़ रुपये जब्त किए

राज्य ब्यूरो, जागरण ● जम्मू : लद्दाख की राजधानी लेह में ईडी ने नकली क्रिप्टोकरेंसी बेंच कर लोगों को सात करोड़ का चूना लगाने के मामले में फिर छापेमारी की है। फर्जी क्रिप्टोकरेंसी निवेश कंपनी के संचालकों के ठिकानों से एक करोड़ रुपये की राशि और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी के मुताबिक, धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रविधानों के तहत दो अगस्त को सोनीपत, लेह और जम्मू सहित छह जगहों पर छापे मारे थे। एमोलिएंट काइन नाम के नकली क्रिप्टोकरेंसी में 10 महीने की छोटी अवधि में निवेश की राशि को दोगुना करने का झांसा दिया था। सोनीपत के नरेश गुलिया ने एमोलिएंट काइन लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से इसका प्रचार किया था। जम्मू के अजय चौधरी, चरणजीत सिंह उर्फ चुन्नी और अतीउल रहमान मीर ने लेह में इसका बिजनेस बढ़ाया। उन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनका निवेश 10 महीने में दोगुना हो जाएगा।

राजनीतिक बदला लेने को वाझे का इस्तेमाल कर रहे फडणवीस : देशमुख

नागपुर, प्रेट्र : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने रविवार को कहा कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। फडणवीस राजनीतिक बदला लेना चाहते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने गृह मंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान पुलिस अधिकारियों से बार और रेस्तराओं से प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूलने को कहा था। इस आरोप के बाद देशमुख ने 2021 में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देशमुख के आरोपों पर फडणवीस ने कहा कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) के नेता निरर्थक काल्पनिक बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट तब सौंपी गई थी, जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी। उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई।

देशमुख ने मीडिया से कहा कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति चांदीवाल ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों की 11 महीने तक जांच की थी। न तो मैंने और न ही मेरे निजी सहायक ने उनसे पैसे मांगे थे। एक दिन पहले ही वाझे ने देशमुख के खिलाफ रिश्वतखोरी का आरोप को दोहराया था।

देशमुख ने फडणवीस पर वाझे के माध्यम से आरोप लगवाकर राजनीतिक प्रतिशोध लेने एवं चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि हाल में देशमुख ने आरोप लगाया था कि जब वह महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में गृह मंत्री थे तब बतौर विपक्षी नेता फडणवीस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एवं कुछ मंत्रियों समेत नेताओं को फंसाने के लिए दबाव डालने की कोशिश की थी।

- फडणवीस ने कहा, राकांपा नेता कर रहे अर्थहीन और काल्पनिक बातें

माउंट मुकुट फतेह करेंगी बीएसएफ की महिला पर्वतारोहण टीम

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को उत्तराखंड में स्थित एक चोटी पर अभियान के लिए सोमवार को दिल्ली से रवाना किया जाएगा। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि 12 महिला पर्वतारोहियों की टुकड़ी का लक्ष्य 7,130 मीटर (23,392 फीट) की ऊंचाई पर स्थित माउंट मुकुट ईस्ट को फतह करना और शिखर पर राष्ट्रीय और बल के झंडे फहराना है।

बीएसएफ के कार्यवाहक महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी सोमवार को दिल्ली स्थित बीएसएफ मुख्यालय से टीम को हरी झंडी दिखाएंगे। बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि यह अभियान महिला सशक्तीकरण का संदेश देता है। गौरतलब है कि लगभग 2.65 लाख कर्मियों की ताकत वाले बीएसएफ को मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कर्तव्य निभाने के अलावा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय मोर्चों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है।

आनलाइन ट्रांसफर के लिए चीनी ठगों ने बनाया एप

विनय त्रिवेदी ● जागरण

गुरुग्राम: कई बार गुरुग्राम पुलिस की जांच में यह सामने आ चुका है कि चीन या दूसरे देश में बैठे ठग भारत के लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं।लेकिन ठगी का पैसा कैसे अपने पास पहुंचाते हैं इसका तरीका भी अब सामने आ रहा है। चाइनीज ठगों ने अपने पास तक रकम पहुंचाने के लिए एक अलग एप बनाया है। इस एप पर बैंक खाता जोड़ने पर वे इसका एक्सेस ले लेते हैं। इसके बाद रकम ट्रांसफर करते हैं।

शनिवार को सेक्टर 46 स्थित एक होटल से पकड़े गए राजस्थान के उदयपुर निवासी अनिल साहू व जयपुर निवासी प्रदीप सिंह से पूछताछ व जांच में इस बात की जानकारी मिली कि चाइनीज सिंडिकेट किस तरह से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा है। पता चला कि चाइनीज सिंडिकेट टेलीग्राम व अन्य माध्यमों से लोगों को अपने जाल में फंसाता है। इसके बाद उन्हें कमीशन पर अपने साथ जोड़ता है। इन दोनों को भी मोटा कमीशन मिलता था। इनका काम यहां के गरीब लोगों के खातों को लेकर उन पर आई ठगी की रकम को ट्रांसफर करना था। पुलिस को ठगी की रकम के ट्रांसफर होने की जानकारी न मिले, इसके लिए चाइनीज ठगों ने एक एप भी बनाया था। चाइनीज सिंडिकेट के साथ जुड़ने पर लोगों के मोबाइल में यह एप इंस्टाल कराया जाता था। इस एप पर सिर्फ बैंक खातों को जोड़ा जाता था। बैंक के डेबिट कार्ड, आनलाइन बैंकिंग से संबंधित सारी जानकारी इस एप पर साझा की जाती थी। इसके बाद चाइनीज ठग इस खाते का एक्सेस लेकर इसका सारा पैसा क्रिप्टोकरेंसी में डाल देते थे। क्रिप्टोकरेंसी एप के माध्यम से ये रकम अपने यहां आसानी से खातों ट्रांसफर कर लेते थे।

गुरुग्राम से पकड़े गए दोनों आरोपितों से पूछताछ और जांच में कई जानकारियां सामने आई हैं। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपित भी पकड़े जाएंगे।

– प्रियांशु दीवान, एसीपी साइबर क्राइम

इसी सिंडिकेट से जुड़े आरोपित को मानेसर पुलिस ने पकड़ा था: जिस आरोपित की बेल के लिए अनिल और प्रदीप गुरुग्राम आए थे। वह भी इसी चाइनीज सिंडिकेट से जुड़ा था। मानेसर साइबर पुलिस ने बीते दिनों आरोपित संस्कार मेहता को गुजरात के महेसाणा से पकड़ा था। वह कई महीने टेलीग्राम से चाइनीज सिंडिकेट से जुड़ा। इसके बाद इन दोनों साथियों को भी इससे जोड़ दिया।

महाराष्ट्र, बिहार समेत चार राज्यों के बैंक खाते थे इनके पास: पकड़े गए दोनों आरोपितों के पास से 16 चेक बुक व 10 एटीएम कार्ड बरामद किए थे। जांच के दौरान पता चला कि ये 16 बैंक खाते महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा व उप्र के लोगों थे। साइबर पुलिस ने संबंधित थाना पुलिस को भी इसकी जानकारी दी है।

लिफ्ट में दो बच्चों को महिला ने पीटा, वीडियो प्रसारित

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: सेक्टर 70 स्थित एक सोसायटी में बच्चों में हुए झगड़े के बाद एक महिला ने दूसरे के बच्चों के साथ गाली-गलौज किया। महिला बच्चों को कालर से पकड़कर लिफ्ट में ले गई। अंदर उनके साथ मारपीट की गई। जब एक बच्चे की मां आई तो उसके साथ भी गाली-गलौज किया गया। बच्चे के पिता ने बादशाहपुर थाने में महिला के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है।

28 जुलाई की इस घटना का वीडियो फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। महिला के बेटे का सोसाइटी में ही रहने वाले बच्चे के साथ झगड़ा हो गया था।बच्चे ने झगड़े के बारे में अपनी मां को बताया। इसके बाद महिला आई और दो बच्चों को लिफ्ट में ले जाकर गाली-गलौज किया और मारपीट की। आरोपित महिला की पहचान फरहान वारसी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि यह वकील है। मारपीट के बाद जब पीड़ित बच्चे ने मां को जानकारी दी और मां ने विरोध किया तो उनके साथ भी गाली-गलौज की गई। एक बच्चे के पिता प्रशांत प्रांडेय ने थाने में लिखित शिकायत की है।

****

2011 में लंदन में दंगों में पांच की मौत हुई थी। 205 लोग घायल हुए थे और तीन हजार की गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही 2815 घरों तर हमला किया गया था।

ब्रिटेन के कई हिस्सों में भड़की हिंसा, दुकानें फूंकीं, 100 किए गए गिरफ्तार

लिवरपूल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, नाटिंघम और मैनचेस्टर में झड़प

ब्रिटेन की गृहमंत्री यवेटे कूपर ने कहा, आपराधिक कृत्य की कीमत चुकानी होगी

- ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
- 2011 में भी पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था

ब्रिटेन में जारी हिंसा के दौरान रविवार को रादरहैम के एक होटल के बाहर आग लगाने के बाद इसमें लकड़ी फेंकता एक प्रदर्शनकारी। रायटर

लंदन, प्रेट्र : साउथपोर्ट में तीन बच्चियों की हत्या के बाद से ब्रिटेन में हिंसा रुक नहीं रही है। लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, स्टोक-आन-ट्रेंट, बेलफास्ट, नाटिंघम और मैनचेस्टर में कई स्थानों पर पुलिस और इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंट और पटाखे फेंके, दुकानों पर हमला बोला, उसमें तोड़फोड़ और लूटपाट की और आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसक भीड़ ने रविवार को एक होटल में भी घुसने की कोशिश की, जिसके बारे में माना जाता है कि वहां ब्रिटेन में शरण चाहने वाले लोग रह रहे हैं। पुलिस ने देशभर से 100 गिरफ्तारियां की हैं। ब्रिटेन की गृहमंत्री यवेटे कूपर ने चेतावनी दी कि इस तरह के आपराधिक कृत्य और गुंडागर्दी की कीमत चुकानी होगी। इससे पहले पूरे ब्रिटेन में हिंसक विरोध प्रदर्शन 2011 में हुआ था, जब लंदन में पुलिस की गोली से एक अश्वेत व्यक्ति की मौत के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे।

हालात को देखते हुए डाउनिंग स्ट्रीट में शनिवार को प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर वालों और व्यवसायों को बाधित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जो भी करना होगा करेंगे।

इस बीच, ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों की ओर से सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। कई लोग मस्जिदों में जाने से डरते हैं। ब्रिटेन की पुलिस मंत्री डायना जानसन ने बताया कि लोग भयभीत हैं और यह सही नहीं है। मैंने लोगों को दुकानों में लूटपाट करते देखा। इसका वास्तविक विरोध या इमिग्रेशन के बारे में अलग-अलग राय रखने वालों से कोई लेना-देना नहीं है। यह एक आपराधिक व्यवहार है। ऐसे लोगों के लिए सही स्थान जेल है।

गौरतलब है कि साउथपोर्ट में हमलावर ने डांस क्लास में चाकू मारकर तीन बच्चियों की हत्या कर दी थी। इस दौरान आठ अन्य लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद से ही हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए हैं। दरअसल, आनलाइन प्रसारित किया जा रहा है कि संदिग्ध खांडा मूल का है और ब्रिटेन में शरण चाहता है। पुलिस ने वेल्स में जन्मे 17 वर्षीय एक्सल मुगनवा रुदाकुबाना को इस मामले में गिरफ्तार किया है।

बहुमत का फैसला संविधान की अनदेखी : पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट

- जजों ने असहमति नोट में कहा- बहुमत के फैसले ने की नियमों, कानून और संविधान की अनदेखी
- सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित सीटों के मामले में बहुमत से इमरान के पक्ष में सुनाया था फैसला

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। फाइल

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए संसद और प्रांतीय असेंबली में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों को लेकर शीर्ष अदालत के बहुमत के फैसले पर असहमति जताई है।

दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि बहुमत के फैसले ने नियमों, कानून और संविधान की अनदेखी की। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने शीर्ष अदालत की पूर्ण पीठ द्वारा घोषित बहुमत के फैसले में असहमति नोट जारी किया है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआइ) द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का चुनाव चिह्न पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने छीन लिया था। जीतने के बाद वे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआइसी) में शामिल हो गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली। हाई कोर्ट ने पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के उस निर्णय को बरकरार रखा था, जिसमें एसआइसी को महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट नहीं देने का निर्णय लिया गया था।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष 12 जुलाई को आठ- पांच के बहुमत से फैसला सुनाया था कि इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ संसद में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 20 से अधिक सीट के लिए पात्र है।

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान समेत पांच जजों ने बहुमत के आदेश से असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अफगान ने असहमति नोट में बहुमत के आदेश को जारी करने में हुई देरी पर भी आश्चर्य जताया है।

दाखिले को फर्जी दस्तावेज का सहारा लेने वाले छात्र को भारत भेजा जाएगा

न्यूयार्क, प्रेट्र : एक 19 वर्षीय भारतीय छात्र को अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए रिकार्ड में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के साथ किए गए एक समझौते के तहत अब उसे भारत लौटना पड़ेगा।

आर्यन आनंद ने 2023-2024 शैक्षणिक वर्ष के लिए पेंसिल्वेनिया के एक निजी अनुसंधान विश्वविद्यालय (लेहाई विश्वविद्यालय) में प्रवेश पाने के लिए नकली और झूठे दस्तावेज जमा किए थे। आनंद की जालसाजी तब सामने आई जब उसने इंटरनेट मीडिया साइट रेडिट पर 'मैंने अपना जीवन और करियर झूठ पर बनाया है' शीर्षक से एक पोस्ट साझा की थी। उस पोस्ट में उसने धोखाधड़ी का पूरा विवरण दिया था।

अमेरिकी पुलिस जांच में पाया गया कि आर्यन आनंद ने प्रवेश और वित्तीय सहायता दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया था। प्रवेश और छात्रवृत्ति पाने के लिए पिता की झूठी मौत की जानकारी दी। उसके पिता जीवित हैं और भारत में हैं।

आर्यन आनंद पर 12 जून को मुकदमा चलाया गया और जालसाजी के मामले में दोषी ठहराया गया। दलील समझौते के हिस्से के रूप में उसे नार्थम्प्टन काउंटी जेल की सजा सुनाई गई। समझौते के तौर पर आर्यन आनंद को भारत लौटना आवश्यक है। लेहाई विश्वविद्यालय ने 85,000 डालर की क्षतिपूर्ति नहीं मांगने का फैसला लिया है।

हैरिस के रनिंग मेट की रेस में टिम वाल्ज, जोश शापिरो और मार्क केली शामिल

- कमला हैरिस आज अपनी पसंद की घोषणा कर सकती हैं

फिलाडेल्फिया में रनिंग मेट के साथ उपस्थिति की उम्मीद

वाशिंगटन, रायटर : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को आम तौर पर अपने रनिंग मेट चुनने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को कुछ हफ्तों के भीतर ही अपनी तलाश पूरी करनी पड़ी है। हैरिस अपने रनिंग मेट पर अंतिम निर्णय लेने से पहले वाशिंगटन डी.सी. स्थित आवास पर तीन शीर्ष उम्मीदवारों मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज, एरिजोना के अमेरिकी सीनेटर मार्क केली और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो का साक्षात्कार लेंगी। मंगलवार को फिलाडेल्फिया में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साथ अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति से पहले हैरिस द्वारा सोमवार को अपनी पसंद की घोषणा करने की उम्मीद है।

मिनेसोटा के गवर्नर वाल्ज अपनी लोकप्रिय शैली व ट्रेड यूनियनों से संबंधों के कारण लोकप्रिय पसंद के रूप में उभरे हैं। वह एक पूर्व स्कूल शिक्षक हैं, जिन्होंने कई कार्यकालों तक प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।पेंसिल्वेनिया के गवर्नर शापिरो को राज्य में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए शीर्ष दावेदार के रूप में देखा गया है, जो हैरिस के लिए व्हाइट हाउस में पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है। हैरिस वर्तमान में इस राज्य में ट्रंप से 2.7 प्रतिशत अंकों से पीछे हैं। केली एरिजोना से आते हैं और हैरिस को 270 इलेक्टोरल कालेज वोटों तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। हैरिस यहां ट्रंप से चार प्रतिशत अंकों से पीछे है। वह पूर्व लड़ाकू पायलट और अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं।

ट्रंप के चार सितंबर के प्रेसिडेंशियल डिबेट प्रस्ताव को हैरिस ने ठुकराया

वाशिंगटन, प्रेट्र : कमला हैरिस ने चार सितंबर को फाक्स न्यूज चैनल पर प्रेसिडेंशियल डिबेट के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप और जो बाइडन के बीच मई में दो प्रेसिडेंशियल डिबेट में भाग लेने के लिए सहमति बनी थी। पहला जून में सीएनएन द्वारा आयोजित किया गया था और दूसरा 10 सितंबर को एबीसी न्यूज पर आयोजित होना है। बाइडन के रेस से हटने के बाद ट्रंप ने यह बहस चार सितंबर को फाक्स न्यूज पर कराने का प्रस्ताव रखा था। हैरिस ने कहा कि वह मूल रूप से नियोजित बहस में भाग लेने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वह ट्रंप को वहां पाएंगी।

हैरिस के पति ने पहली शादी के दौरान विवाहेतर संबंध की बात मानी

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति डग एम्हाफ ने अपनी पहली शादी के दौरान विवाहेतर संबंध होने की बात स्वीकारी है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि हैरिस से मिलने और शादी से कई साल पहले उनका अपने बच्चे के स्कूल में एक शिक्षिका के साथ संबंध था। 2009 में शिक्षिका गर्भवती हो गई थी। हालांकि, उसका कोई बच्चा नहीं है। शिक्षिका का गर्भपात हो गया था। बाद में डग अपनी पहली पत्नी क्रस्टीन एम्हाफ से अलग हो गए। एम्हाफ एंटरटेनमेंट वकील के तौर पर काम करते थे। उनकी पहली शादी से दो बच्चे एला और कोल हैं। वहीं, क्रस्टीन ने कहा कि कई साल पहले हमने रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया था। क्रस्टीन ने कहा कि उनकी अच्छी दोस्ती है। क्रस्टीन ने 2009 में तलाक की अर्जी दी थी। 2010 के अंत में दोनों का तलाक हो गया था। डग के साथ संबंधों से पहले हैरिस को उनके अफेयर के बारे में पता था।

गाजा में इजरायली सेना के हमलों में 44 लोग मारे गए

- हमले में दो घायल, तनाव के बीच इजरायल में हमला
- तेल अवीव में फलस्तीनी ने छुरे से दो बुजुर्गों को मारा

इजरायल-लेबनान सीमा पर लेबनान के एक क्षेत्र में रविवार को हमले के बाद उठता धुएं का गुबार। एपी

तेल अवीव, एपी : हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिस्र की राजधानी काहिरा में गाजा में युद्धविराम के लिए चल रही वार्ता पटरी से उतर गई है। इसके बाद रविवार को इजरायली सेना ने गाजा में अपने हमले बढ़ा दिए। हमलों में स्कूलों, अस्पताल परिसर और अन्य स्थानों में शरण लिए लोगों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कुल 44 लोग मारे गए हैं। सबसे ज्यादा 25 लोग गाजा सिटी के दो स्कूलों में मारे गए हैं। दीर अल-बलाह शहर के अस्पताल परिसर में लगे टेंट में रहने वाले चार लोग मारे गए हैं। जबकि इजरायल की राजधानी तेल अवीव के उपनगर में एक फलस्तीनी ने धारदार हथियार (छुरे) से हमला कर दो इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी।

ईरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और लेबनान में हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर फुआद शुकर के मारे जाने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में इजरायल की राजधानी में एक फलस्तीनी आदमी द्वारा दो लोगों की हत्या कर देने से स्थिति की गंभीरता और बढ़ गई है। मारे जाने वालों में 70 वर्ष की वृद्ध महिला और 80 वर्ष के वृद्ध हैं। हमले में दो लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि यह हमला एक फलस्तीनी उग्रवादी ने किया था जिसे मौके पर ही गोली मार दी गई।

उधर, लेबनान से इजरायल पर राकेट और मिसाइल के हमले जारी हैं, रविवार को ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला ने इजरायल पर करीब 50 राकेट दागे। इनमें से ज्यादातर को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ से नुकसान होने की सूचना है। इजरायल के जवाबी हवाई हमले में लेबनान में एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना है। इजरायल व लेबनान के बीच दस महीने से जारी लड़ाई अब बढ़ने की आशंका है। इसके कारण भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने के लिए कहा है।

भारत के साथ जलमार्ग, रेलवे का विस्तार चाहते हैं नेपाल के पीएम

- हनुमाननगर से त्रिवेणी और देवघाट तक स्टीमर सेवाओं के लिए योजना का मसौदा तैयार करने का दिया निर्देश

पूर्व-पश्चिम रेलवे लाइन के विकास का रखा प्रस्ताव, इससे नेपाल के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीयों को भी होगा फायदा

केपी ओली। फाइल

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच जलमार्ग और रेलवे का विस्तार चाहते हैं। सड़क विभाग की वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने सिविल सेवकों को भारतीय सीमा के पास हनुमाननगर से त्रिवेणी और देवघाट तक स्टीमर सेवाओं के संचालन के लिए योजना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि 1970 से नेपाल में स्टीमर सेवाओं की अनुमति देने वाले कानून के बावजूद, ऐसे बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ओली ने अधिकारियों को देश में जल्द ही स्टीमर संचालित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया। ओली ने कहा, हमें हनुमाननगर में बंदरगाह, सीमा शुल्क कार्यालय और बीजा केंद्र स्थापित करना चाहिए। ओली ने नेपाल की रेलवे सेवाओं के विस्तार किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया और मौजूदा जनकपुर-कुर्था रेलवे लाइन में दो रेलवे लाइनें जोड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल में पूर्व-पश्चिम रेलवे लाइन के विकास का भी प्रस्ताव रखा। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि इससे नेपाल के रास्ते गुवाहाटी (असम) से दिल्ली और सिलीगुड़ी (बंगाल) से हरिद्वार तक यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को भी फायदा होगा।

यूक्रेन ने अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-16 का शुरू किया इस्तेमाल

- रूस उन ठिकानों को निशाना बना रहा, जहां जेट के रखे जाने की संभावना है
- रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन को इस विमान का इंतजार था

यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-16 को रविवार को आसमान में उड़ते देखते राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। रायटर

कीव, रायटर : यूक्रेन ने अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-16 का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि पायलटों ने इसके संचालन में महारत हासिल कर ली है। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका निर्मित इस लड़ाकू विमान का यूक्रेन को इंतजार था। जेलेंस्की ने कहा कि एफ-16 यूक्रेन में है। हमने यह कर दिखाया। मुझे अपने लोगों पर गर्व है, जो इन फाइटर जेट पर महारत हासिल कर रहे हैं और देश के लिए उनका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। कई महीनों के इंतजार के बाद जेट विमानों का आगमन यूक्रेन के लिए एक मील का पत्थर है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनकी संख्या कितनी है।

रूस उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जहां उसे रखे जाने की संभावना है। रूस ने कसम खाई है वह इसे मार गिराएगा, ताकि युद्ध पर असर न डाल सके। यूक्रेन के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के अनुसार, यूक्रेन रूसी हमलों से बचाने के लिए कुछ एफ-16 विमानों को विदेशी ठिकानों पर रख सकता है। वहीं, पुतिन ने चेतावनी दी है कि यदि नाटो देशों ने यूक्रेन में इस्तेमाल युद्धक विमानों की मेजबानी की तो मास्को नाटो देशों की सुविधाओं पर हमले शुरू करने पर विचार कर सकता है।

एफ-16 अपनी विनाशकारी शक्ति और वैश्विक उपलब्धता के कारण लंबे समय से यूक्रेन की सूची में था। विमान 20 मिमी तोप से लैस है और बम, राकेट और मिसाइल ले जाने में सक्षम है। हालांकि, जेलेंस्की ने पर्याप्त प्रशिक्षित पायलटों को लेकर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास अब भी एफ-16 या जेट विमानों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित पायलट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम और एफ-16 की उम्मीद कर रहे हैं। अब कई लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं।

बता दें, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन द्वारा छोड़े गए कम से कम 76 ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। इसमें रोस्तोव के सीमावर्ती क्षेत्र में 36 और ओर्योल क्षेत्र में 17 ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा उसने कुर्स्क और बेलगोरोद क्षेत्रों में क्रमशः आठ और नौ ड्रोनों को निष्क्रिय कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने पिछले सप्ताह यूक्रेन पर हमला करने के लिए 600 से अधिक निर्देशित हवाई बमों का इस्तेमाल किया। वहीं, रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के पूर्वी शहर पोक्रोवस्क पर दबाव बढ़ा दिया है।

प्रधानमंत्री हसीना ने स्थिति की समीक्षा के लिए सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक की

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधानमंत्री हसीना ने स्थिति की समीक्षा के लिए सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक की है। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों, अर्धसैनिकों बलों, पुलिस और खुफिया संगठनों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में दो हफ्तों के भीतर दोबारा भीषण हिंसा भड़कने के मूल कारणों का पता लगाने और उसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सरकार ने तीन दिनों के अवकाश की घोषणा की है। इससे पहले जुलाई में आरक्षण के विरोध में देशव्यापी हिंसा हुई थी जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 93 प्रतिशत स्थान अनारक्षित किए जाने के बाद स्थिति शांत हो गई थी। पूर्व सेनाध्यक्ष इकबाल करीम भुइयां ने सरकार से सुरक्षा बलों को सड़कों से हटाने की मांग की है। कहा है कि राजनीतिक विषयों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए।

'पिच ब्लैक 24'

ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में रविवार को बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'पिच ब्लैक 24' के अवसर पर कतार में खड़े भारतीय वायुसेना के जवान। यह सैन्य अभ्यास 12 जुलाई से दो अगस्त किया गया है, जिसमें 20 देशों ने भाग लिया है। प्रेट्र

राष्ट्रीय फलक

चीनी सीमा से दो साल से लापता हैं अरुणाचल प्रदेश के दो युवक

- माना जाता है पीएलए की हिरासत में हैं दोनों युवक, पर चीन ने नहीं माना
- जड़ी-बूटी की तलाश में अंजा के चगलगाम गए थे दोनों

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीनी सीमा के नजदीक से अरुणाचल प्रदेश के लापता हुए दो युवकों का अब तक पता नहीं चला है। युवकों का पता लगाने के लिए दो साल से तलाशी अभियान जारी है। माना जाता है कि दोनों युवक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की हिरासत में हैं, लेकिन चीन ने अब तक दोनों की अपने क्षेत्र में होने की बात को स्वीकार नहीं की है। दोनों युवक बेटिलम टिकरो और बेइंग्सो मन्यु 19 अगस्त 2022 को जड़ी-बूटी की तलाश में अंजा के चगलगाम के लिए रवाना हुए थे। तबसे वह लापता हैं।

33 साल के बेटिलम टिकरो और 35 वर्षीय बेइंग्सो मन्यु औषधीय पौधों (जड़ी-बूटी) की तलाश में अंजा के चगलगाम के लिए रवाना हुए थे। मगर वह वहां पहुंचे ही नहीं और नाही अपने घर वापस आए। उसके बाद से उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। परिजनों ने काफी तलाश करने के बाद नौ अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दी थी। टिकरो के भाई दिशांसो चिकरो ने बताया कि उन्हें पता चला है कि उनके भाइयों को चीनी सेना ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने इस संबंध में कई बार सैन्य अधिकारियों से संपर्क किया। भारतीय सेना ने अपने चीनी समकक्षों के साथ इस मुद्दे को उठाया है। मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अंजा विधायक और राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री दसांगलू पुल ने बताया कि चीन ने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया कि दोनों युवक उसकी हिरासत में हैं। मगर जानकारी मिली है कि वे अब भी जिंदा हैं।

टिकरो डोइलियांग का रहने वाला है और मन्यु अरुणाचल के अंजा जिले के मनयू चिपरोगम का रहने वाला है। टिकरो की शादी नहीं हुई, जबकि मन्यु शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है। सितंबर 2020 में भी चीनी सेना पीएलए ने अरुणाचल के सुबनसिरी जिले से पांच युवकों का अपहरण कर लिया था और एक हफ्ते बाद उन्हें रिहा किया था। भारत लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ 3,400 किलोमीटर लंबी एलएसी साझा करता है।

हिमाचल में नशा तस्करी के आरोपित के घर से 59 लाख रुपये बरामद

जागरण संवाददाता, नाहन : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में पुलिस ने एक नशा तस्करी के आरोपित के घर से 59 लाख रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के आने से पहले आरोपित घर से फरार हो गया, जिसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपित ने घर में मादक पदार्थ रखे हैं। इसके बाद पुलिस ने रविवार को संजय कुमार और उसकी पत्नी के घर में दबिश दी थी। इस दौरान एक कमरे की तलाशी ली तो अलमारी से 59,10,100 रुपये बरामद हुए हैं।

संजय कुमार के विरुद्ध नशा तस्करी के दो मामले पांवटा साहिब पुलिस थाना में दर्ज हैं। मामले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पांवटा साहिब की अदालत में विचाराधीन हैं। पुलिस ने नशा तस्कर के घर से 59 लाख रुपये पकड़े जाने की पुष्टि की है।

अंग्रेजों के लिए 'अभेद्य दीवार' बने श्रीजेश

भारतीय टीम के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन ने 28 शाट लगाए लेकिन केवल एक गोल किया

पेनाल्टी शूटआउट में गोल बचाते पीआर श्रीजेश ● एपी

नई दिल्ली, जेएनएन: अपने करियर का अंतिम टूर्नामेंट खेल रहे गोलकीपर पीआर श्रीजेश को भारतीय हाकी की दीवार क्यों कहा जाता है, ये रविवार को ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में दिखा। पेनाल्टी शूटआउट में मैच और सेमीफाइनल में जगह दांव पर थी। ग्रेट ब्रिटेन के सामने आठ सेकेंड के भीतर 'श्रीजेश' नाम की दीवार को भेदने का लक्ष्य था। ग्रेट ब्रिटेन इस अभेद्य दीवार को भेद नहीं पाया और शूटआउट में 2-4 से हारकर पेरिस ओलिंपिक से बाहर हो गया। इस मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने 21 शाट लगाए, 11 पेनाल्टी कार्नर जीते, लेकिन एक ही गोल किया। यह एक मास्टर क्लास गोलकीपिंग थी। पीआर श्रीजेश ने 92 प्रतिशत की दक्षता के साथ 11 सेव किए।

यह श्रीजेश का 23वां पेशेवर पेनाल्टी शूटआउट और उसमें भारत ने 13वीं बार जीत दर्ज की थी। यही कारण है कि ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध जब भारतीय खिलाड़ियों ने निर्धारित समय में मैच ड्रा कराया और मैच शूटआउट में गया तो उन्होंने जीत की तरह जश्न मनाया। टीम को पता था कि पेनाल्टी शूटआउट में उनका गोलकीपर उन्हें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि लगभग दो दशक से श्रीजेश यही कर रहे हैं।

टूर्नामेंट से पहले ही श्रीजेश ने घोषणा की थी कि यह उनके करियर का अंतिम ओलिंपिक होगा। पूरी टीम ने भी घोषणा की थी कि वे श्रीजेश के लिए खेलेंगे। पेरिस में श्रीजेश अर्जेंटीना और आयरलैंड के विरुद्ध डिफेंस की कमजोरियों को शानदार बचाव से छुपाया, तो आस्ट्रेलिया के विरुद्ध अच्छी शुरुआत की और मजबूत किया, लेकिन उनका जादुई प्रदर्शन क्वार्टर फाइनल में आया। श्रीजेश ने पूरे मैच में विपक्षी टीम की गेंद को कभी पैर से रोका, कभी डाइव लगाकर पकड़ा, कभी आगे निकलकर शाट को विफल किया तो कभी पीछे हटकर रिफ्लेक्स का कमाल दिखाया। भारत को जवाबी हमले में 22वें मिनट में पेनाल्टी कार्नर मिला जिसे हरमनप्रीत ने गोल में बदला। शानदार प्रदर्शन कर रहे भारतीय डिफेंस में पहली बार चूक देखी गई और 27वें मिनट में सर्कल पर से गोल के सामने मिली गेंद को मोर्टन ने गोल के भीतर डाला। पेनाल्टी शूटआउट में भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल ने गोल दागे जबकि इंग्लैंड के जेम्स अलबेरी और जाक वालांस ही गोल कर सके। इसके बाद कोनोर विलियमसन का निशाना चूका और फिलिप रोपर का शाट श्रीजेश ने बचाकर टीम को जीत दिलाई।

> एक गोलकीपर का यह रोज का काम है। कई बार अलग स्थिति होती है, लेकिन आज हमारा दिन था। जब मैं मैदान पर आया तो मेरे सामने दो ही विकल्प थे। यह मेरा आखिरी मैच होता या मुझे दो मैच और खेलने का मौका मिलता। आखिरकार अब मुझे दो मैच और मिलेंगे। - **पीआर श्रीजेश**, गोलकीपर भारत

> भारतीय टीम ने शानदार हौसला दिखाया। टीम इंडिया और हाकी की दीवार श्रीजेश के लिए एक शानदार जीत जिन्होंने शानदार खेल दिखाया। अगले मैच के लिए पूरी टीम को हमारी शुभकामनाएं। - **पीटी ऊषा**, अध्यक्ष, आइओसी

> वाह। यह मैच कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इतने लंबे समय तक 10 खिलाड़ियों के साथ डिफेंड बेजोड़ है। श्रीजेश आपने शानदार प्रदर्शन किया। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। - **रवि शास्त्री**, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

रणनीति बदलकर भारत को मिली जीत : अजीत पाल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : भारतीय हाकी टीम के पूर्व कप्तान राजपाल सिंह ने कहा, क्वार्टर फाइनल में भारत ने परिस्थिति के हिसाब से तुरंत रणनीति बदलकर जीत हासिल की। आस्ट्रेलिया के विरुद्ध आक्रामक खेल खेलने वाली भारतीय टीम ने रोहिदास को रेड कार्ड मिलने के बाद आक्रमक खेलने के बजाए डिफेंस को प्राथमिकता दी और ब्रिटेन को गोल नहीं करने दिया। कप्तान हरमनप्रीत जानते थे कि अगर मैच पेनाल्टी शूटआउट में जाता है तो भारत मैच जीत सकता है। रोहिदास को रेड कार्ड मिला। यह टीम के लिए मुश्किल स्थिति थी, इसका असर मैदान पर भी देखने को मिला, ब्रिटेन की टीम पूरे मैच हावी रही। श्रीजेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और ब्रिटेन का दूसरा गोल नहीं करने दिया।

हाकी इंडिया ने 'खराब' अंपायरिंग पर की शिकायत

नई दिल्ली, जेएनएन : हाकी इंडिया ने रविवार को भारत और ग्रेट ब्रिटेन के मैच के बाद आधिकारिक तौर पर अंपायरिंग की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज कराई। हाकी इंडिया ने शिकायत में कहा कि रोहिदास को रेड कार्ड दिखाए जाने के निर्णय ने वीडियो समीक्षा प्रणाली पर भरोसा खत्म कर दिया। शूटआउट के दौरान गोलपोस्ट के पीछे से गोलकीपर को कोचिंग देना और शूट आउट के दौरान गोलकीपर द्वारा वीडियो टैबलेट का उपयोग करना। इन घटनाओं ने खिलाड़ियों, कोचों और प्रशंसकों के बीच अंपायरिंग प्रक्रिया में विश्वास को कम कर दिया है।

लक्ष्य की फुर्ती पर भारी पड़ा विक्टर का अनुभव

- भारतीय युवा शटलर को सेमीफाइनल में मिली हार, अब कांस्य पदक के मुकाबले में उतरेंगे

सेमीफाइनल मुकाबले में जीत केबाद बाद लक्ष्य सेन को सांत्वना देते डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ● प्रेट्र

पेरिस, प्रेट्र: पेरिस ओलिंपिक में अपने शानदार खेल से प्रभावित करने वाले लक्ष्य सेन रविवार को अपने सबसे कड़े प्रतिद्वंद्वी विक्टर एक्सेलसेन के सामने थे, जिन्होंने टोक्यो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। लक्ष्य ने विक्टर के विरुद्ध अपनी फुर्ती से दोनों गेम में शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन वह डेनमार्क के इस खिलाड़ी के अनुभव के आगे हार गए। एक्सेलसेन ने पहले गेम में तीन मैच प्वाइंट बचाते हुए 22-20 से जीत दर्ज की, जबकि दूसरे गेम में 0-7 से पिछड़ने के बाद उन्होंने 21-14 से गेम और मैच जीता। दोनों खिलाड़ी लंबी, तीव्र रैलियों में लगे रहे। इसने कभी-कभी एक्सेलसन की सटीकता को बाधित कर दिया, जिससे लक्ष्य को प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिली।

एक्सेलसेन की रणनीति भारतीय शटलर के स्मार्ट खेल के बावजूद लक्ष्य को शक्तिशाली स्मैश से लुभाने के इर्द-गिर्द घूमती रही। एक्सेलसेन का अनुभव और लचीलापन सामने आया क्योंकि उन्होंने कई शक्तिशाली हमले किए। लक्ष्य, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इसका सामना नहीं कर सके और गेम हाथ से निकल गया।

एक्सेलसेन की जीत ने उन्हें लगातार दूसरे ओलिंपिक सिंगल्स के फाइनल में जगह दिलाई। लक्ष्य सेन के लिए यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। सोमवार को कांस्य पदक मैच में उनका सामना मलेशिया के ली जि जिया से होगा, जो उनके ओलिंपिक अभियान को उच्च स्तर पर समाप्त करने का मौका है। मैच के बाद खुद एक्सेलसेन ने लक्ष्य की प्रशंसा करते हुए कहा, लक्ष्य एक अद्भुत खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस ओलंपिक में दिखाया है कि वह एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं और मुझे यकीन है कि अब से चार साल बाद वह स्वर्ण पदक जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक होंगे।'

आज के कार्यक्रम

निशानेबाजी: स्कीट मिक्स्ड टीम क्वालीफिकेशन, दोपहर 12 :30 बजे (**अनंतजीत नरूका और महेश्वरी**)

टेबल टेनिस: महिला टीम राउंड आफ 16, दोपहर 1:30 बजे (**भारत बनाम रोमानिया**)

एथलेटिक्स: महिला 400 मीटर राउंड 1, दोपहर 3 :25 बजे (**पूहल किरन**), पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज, रात 10 :34 बजे (**अविनाश साबले**)

सेलिंग: महिला डिंगी दोपहर 3 :45 बजे (**नेत्रा कुमानन**), पुरुष डिंगी रेस 9 व 10, शाम 6 :10 बजे (**विष्णु सरवनन**)

बैडमिंटन: पुरुष सिंगल्स कांस्य पदक मुकाबला, शाम 6 बजे (**लक्ष्य सेन बनाम जिजिया ली**)

कुश्ती: महिला 68 किग्रा, शाम 6 :30 बजे (**निशा बनाम सोवा रिझको**)

तालिका

देश	सोना	चांदी	कांस्य	कुल
1 चीन	19	15	10	44
2 अमेरिका	17	26	25	68
3 फ्रांस	12	14	17	43
4 आस्ट्रेलिया	12	9	7	28
5 ग्रेट ब्रिटेन	10	12	15	37
6 द. कोरिया	10	7	7	24
7 जापान	8	5	10	23
8 इटली	7	9	5	21
9 नीदरलैंड्स	6	5	4	15
10 जर्मनी	5	5	2	12
57 भारत	0	0	3	3

पदक तालिका *रात 12 :00 बजे तक

टोक्यो में मिली सफलता को नहीं दोहरा पाईं लवलीना

पेरिस, प्रेट्र : मुक्केबाजी में भारत की पदक की अंतिम उम्मीद लवलीना पर थीं। टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना 75 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीन की ली कियान से हारकर बाहर हो गईं। उनकी हार के साथ ही मुक्केबाजी में भारत का अभियान बिना पदक ही समाप्त हो गया। भारत के छह मुक्केबाजों ने पेरिस में क्वालीफाई किया था। लवलीना को कड़े मुकाबले में ली कियान से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों मुक्केबाजों को बार-बार 'क्लिंचिंग और होल्ड' करने के लिए चेतावनी दी गई।

प्रतिद्वंद्वी को मुक्का लगातीं लवलीना ● रायटर

फाइनल में नहीं पहुंच सके जेस्वीन एल्ड्रिन और पारुल चौधरी

पेरिस: भारत का एथलेटिक्स में निराशाजनक प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा जब राष्ट्रीय रिकार्डधारक पारुल चौधरी और जेस्वीन एल्ड्रिन अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में क्वालीफाई करने में विफल रहे। 3000 मीटर स्टीपलचेज में पारुल अपनी हीट रेस में आठवें और कुल मिलाकर 21वें स्थान पर रहीं। पुरुषों की लंबी कूद क्वालीफिकेशन में एल्ड्रिन पहले दो प्रयासों में फाउल कर गए, जबकि तीसरे प्रयास में 7.61 मीटर तक ही पहुंच पाए। वह ग्रुप बी क्वालीफिकेशन में 13वें और कुल 26वें स्थान पर रहे।

स्कीट स्पर्धा में महेश्वरी और राइजा ढिल्लों फाइनल से चूकीं

पेरिस: भारतीय निशानेबाज महेश्वरी चौहान और राइजा ढिल्लों रविवार को महिला स्कीट स्पर्धा में क्रमश : 14वें और 23वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। पांच सीरीज के क्वालीफिकेशन की अंतिम दो सीरीज रविवार को खेली गई जिसके बाद महेश्वरी का कुल स्कोर 118 रहा। राइजा का कुल स्कोर 113 रहा। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल स्पर्धा में विजयवीर सिद्धू और अनीश भानवाला ने भी निराश किया। सिद्धू नौवें और अनीश 13वें स्थान पर रहे। इस स्पर्धा से शीर्ष छह निशानेबाजों ने फाइनल में जगह बनाई थी।

महेश्वरी चौहान ● एएफपी

पेरिस में जोकोविक ने पूरा किया करियर का 'गोल्डन स्लैम'

नोवाक जोकोविक ● एपी

नई दिल्ली, जेएनएन : टेनिस में पुरुष सिंगल्स इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने अंततः 16 वर्षों के बाद अपना सपना पूरा कर लिया है। यह स्वर्णिम जीत उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह उनकी भावनाओं से प्रकट हो गया। 24 ग्रैंडस्लैम विजेता के लिए हर जीत विशेष रही है, परंतु रविवार को जब उन्होंने ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीता वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके। 16 वर्षों के करियर में अगर कुछ शेष था तो वह ओलिंपिक में स्वर्ण पदक। इस जीत के साथ जोकोविक ने करियर को 'गोल्डन स्लैम' भी पूरा कर लिया। चारों ग्रैंडस्लैम के बाद ओलिंपिक स्वर्ण जीतने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले नडाल, आंद्रे अगासी, स्टेफी ग्राफ और सेरेना विलियम्स ने केवल यह उपलब्धि प्राप्त की है।

सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविक ने रविवार को खेले गए पुरुष सिंगल्स के रोमांचक फाइनल में स्पेन के युवा स्टार कार्लोस अलकराज को सीधे सेटों में 7-6(3), 7-6(2) से हराकर पेरिस ओलिंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

16 वर्षों के करियर में 24 ग्रैंडस्लैम जीतकर इतिहास रचने वाले सर्बियाई खिलाड़ी ने इससे पहले केवल 2008 में ओलिंपिक में कांस्य जीता था। पांचवां ओलिंपिक खेल रहे 37 वर्षीय नोवाक जोकोविक 2012 में लंदन में चौथे स्थान पर, जबकि 2016 में रियो डि जनेरियो में पहले ही बाहर हो गए थे। 2021 में टोक्यो में भी वह कांस्य पदक के मुकाबले में हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस वर्ष फ्रेंच ओपन और विंबलडन के विजेता रहे 21 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी के विरुद्ध फाइनल में भी उन्होंने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पहले सेट से ही अलकराज ने जोकोविक की कड़ी परीक्षा ली। हालांकि, जोकोविक ने अपना धीरज नहीं खोया और आठ ब्रेकप्वाइंट बचाए। उन्होंने पूरे मैच के दौरान अद्भुत धैर्य और जज्बे को दर्शाया और टाई ब्रेक के दौरान अलकराज की गलतियों का लाभ उठाया। दोनों टाई ब्रेक के दौरान जोकोविक का अनुभव और जीतने की भूख ने उन्हें मैच में आगे रखा।

लेडेस्की ने चौथा स्वर्ण जीत रचा इतिहास

पेरिस, रायटर : अमेरिकी तैराक केटी लेडेस्की पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 800 मीटर फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। वह लगातार चार ओलिंपिक खेलों में एक प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले फेल्प्स लगातार चार ओलिंपिक खेलों में एक ही स्पर्धा जीतने वाले एकमात्र तैराक थे। उन्होंने एथेंस, बीजिंग, लंदन और रियो डी जनेरियो में 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में स्वर्ण पदक जीता था। लेडेस्की का पेरिस ओलिंपिक में दूसरा, जबकि कुल नौवां स्वर्ण पदक है। वह ओलिंपिक इतिहास में नौ या इससे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली केवल छठी खिलाड़ी है। लेडेस्की ओलिंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में तैराक मार्क स्पिट्ज, ट्रैक स्टार कार्ल लुईस, सोवियत जिमनास्ट लारिसा लैटिनिना और फिनलैंड के धावक पावो नूरमी के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। ओलिंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकार्ड अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स (23 स्वर्ण पदक) के नाम है।

ओलिंपिक में विश्व

केटी लेडेस्की ● रायटर

क्या विवादित स्कोरिंग का शिकार हुए निशांत

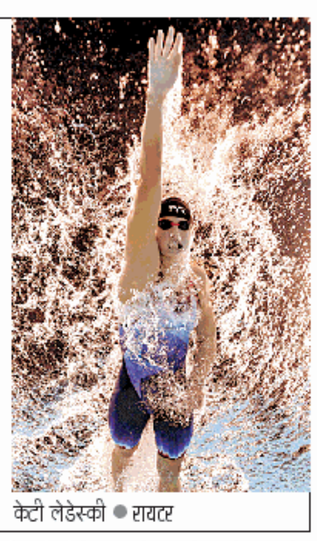

71 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मार्को पर हावी रहे थे भारत के मुक्केबाज, बावजूद उनके पक्ष में नहीं रहा परिणाम

क्वार्टर फाइनल के दौरान निशांत देव (लाल जर्सी में) ● प्रेट्र

नई दिल्ली, जेएनएन : मुक्केबाजी में विजेता का निर्णय एक दूसरे पर घूंसों की बरसात से होता है, लेकिन इसकी स्कोरिंग प्रणाली आज तक किसी को समझ में नहीं आई और ताजा उदाहरण पेरिस ओलिंपिक में भारत के निशांत देव का क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। निशांत 71 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दो दौर में बढ़त बनाने के बाद मेक्सिको के मार्को वेरडे अलवारेज से 1-4 से हार गए तो सभी हैरान रह गए।

हर ओलिंपिक में यह बहस होती है कि आखिर जज किस आधार पर निर्णय लेते हैं। निशांत का मामला पहला नहीं है और न ही अंतिम होगा। लास एंजिलिस में 2028 ओलिंपिक में मुक्केबाजी का होना तय नहीं है और इस तरह की विवादित स्कोरिंग से मामला और खराब हो रहा है। टोक्यो ओलिंपिक 2020 में एमसी मेरीकोम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला हारने के बाद रिंग से मायूसी में बाहर निकली थीं क्योंकि उन्हें जीत का भरोसा था। उन्होंने उस समय कहा था ,'सबसे खराब बात यह है कि कोई रिव्यू या विरोध नहीं कर सकते। मुझे भरोसा है कि विश्व ने इसे देखा होगा। इन्होंने हद कर दी है।' निशांत के हारने के बाद कल पूर्व ओलिंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह ने एक्स पर लिखा, 'मुझे नहीं पता कि स्कोरिंग प्रणाली क्या है लेकिन यह काफी करीबी मुकाबला था। उसने अच्छा खेला। कोई ना भाई।' अमेच्योर मुक्केबाजी की स्कोरिंग प्रणाली बीते बरसों में इस तरह बदलती आई है और धीरे-धीरे जजों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इससे पहले भी ओलिंपिक में मुक्केबाजी में स्कोरिंग विवादों में रही है। 2016 रियो ओलिंपिक में बैंटमवेट विश्व चैंपियन माइकल कोनलान ने फाइनल में पूरे समय दबदबा बनाए रखा ता, लेकिन उन्हें विजेता घोषित नहीं किया गया था। पांच वर्ष बाद एआइबीए ने जांच में पाया कि सभी जजों ने पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया था।

'सुपर ओवर' नहीं कराना नियमों की अनदेखी

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

आइसीसी मैच अधिकारियों की लापरवाही पर अब तक नहीं दिया गया स्पष्टीकरण, भारत-श्रीलंका के बीच पहला वनडे हुआ था टाई

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में चल रही तीन मैचों की सीरीज के पहले रोमांचक वनडे मैच में टाई के बाद आइसीसी मैच अधिकारियों ने सुपर ओवर नहीं कराया। उनके इस निर्णय को लेकर उस दिन से ही बहस शुरू हो गई है। पहले यह माना जा रहा था कि टाई-ब्रेकर ओवर केवल आइसीसी और बहुराष्ट्रीय सीरीज में लागू होता है, जहां परिणाम अनिवार्य होता है।

हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि आइसीसी की दिसंबर 2023 की वनडे खेलने की शर्तों के अनुसार 'सुपर ओवर' वास्तव में एक विकल्प था। यह प्रविधान इस दौरे के लिए दोनों बोर्डों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में भी शामिल है, जो इसे इस सीरीज पर लागू करता है।

आइसीसी पुरुष वनडे खेलने की शर्तों में अंतिम बार दिसंबर 2023 में संशोधन किया गया था। इसके खंड 16.3.1.1 में कहा गया है कि सभी वनडे मैच जो टाई पर समाप्त होंगे, उनमें 'सुपर ओवर' होगा जब तक कि परिणाम न निकल जाए। नियम के अनुसार, 'यदि दोनों पारियां पूरी होने के बाद टीम के स्कोर बराबर हों, तो सुपर ओवर खेला जाएगा। यदि सुपर ओवर बराबर होता है, तो जब तक कि असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न न हों, तब तक सुपर ओवर खेले जाएंगे जब तक कि कोई विजेता न निकल जाए। यदि विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक सुपर ओवर खेलना या पूरा करना संभव नहीं है, तो मैच टाई होगा।'

'सुपर ओवर' की अप्रत्याशित चूक ने प्रशंसकों और अन्य हितधारकों को खेल की शर्तों के उल्लंघन के पीछे के कारण पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। यह आइसीसी मैच अधिकारियों, मैच रेफरी रंजन मदुगले, आन फील्ड अंपायर जोएल विल्सन और रवींद्र विमलसिरी, रिजर्व अंपायर रुचिरा पल्लयागुरगे और टीवी अंपायर पाल रीफेल की सामूहिक जिम्मेदारी थी कि वे पहले से तय खेल की शर्तों का पालन करें। अब तक, शुक्रवार के खेल में 'सुपर ओवर' की चूक के बारे में मैच अधिकारियों या आइसीसी की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। अगर यह एक चूक थी, तो इसे आइसीसी मैच अधिकारियों द्वारा एक गंभीर गलती माना जाएगा, क्योंकि इसने दोनों टीमों और उनके प्रशंसकों को अपडेट किए गए नियमों के अनुसार एक रोमांचक खेल के उचित समापन से वंचित कर दिया।

इस बीच, 'द मार्निंग टेलीग्राफ' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, एक आइसीसी अधिकारी ने कहा कि अगर चल रही वनडे सीरीज में एक और टाई होता है, तो नवीनतम खेल नियमों के अनुसार 'सुपर ओवर' लागू किया जाएगा। आइसीसी अधिकारी ने कहा, 'दो गलतियां एक सही नहीं बनातीं।'

पुरुषों के टाई हुए वनडे मैचों के पहले भी 'सुपर ओवर' से तय होने के कई उदाहरण रहे हैं। सबसे मशहूर उदाहरण इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2019 आइसीसी पुरुष वनडे विश्व कप फाइनल था। इसके अलावा, पाकिस्तान और जिंबाब्वे के बीच 2020 के वनडे मैच का निर्णय पीसीबी और जिंबाब्वे क्रिकेट के बीच द्विपक्षीय समझौते के कारण 'सुपर ओवर' के जरिये ही हुआ था। अंतिम वनडे जिसमें 'सुपर ओवर' हुआ था, वह 26 जून, 2023 को वेस्टइंडीज और नीदरलैंड्स के बीच हरारे में विश्व कप क्वालीफायर था, जहां डच टीम ने विश्व कप 2023 के लिए क्वालीफाई किया था।

दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने भारतीय टीम को 32 रनों से हराया, जेफरी ने झटके छह विकेट

पदार्पण कर रहे वेंडर्से बने भारत के लिए अबूझ पहेली

विराट कोहली को आउट करने के बाद जेरेमी वेंडर्से (बाएं) ● प्रेट्र

नई दिल्ली, जेएनएन : श्रीलंका के लिए पदार्पण करने वाले 34 वर्षीय दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज जेफरी वेंडर्से भारतीय बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली साबित हुए। रविवार को कोलंबो में हुए दूसरे वनडे मैच के दौरान आधे से अधिक टीम को पवेलियन की राह दिखाने वाले इस गेंदबाज ने तीन मैचों की सीरीज में श्रीलंका को 1-0 से आगे कर दिया है। कप्तान असलंका के पहले बल्लेबाजी के निर्णय को भले ही टीम के शीर्ष बल्लेबाजों ने गलत साबित किया, परंतु निचले क्रम के बल्लेबाजों ने लंबी साझेदारी कर टीम के स्कोर को 240 पहुंचा दिया। केवल 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए यह भी बड़ा साबित हुआ और पूरी टीम केवल 208 रन पर सिमट गई।

श्रीलंकाई टीम को टी-20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद वनडे में भारतीय टीम की फार्म की गाड़ी अब तक पटरी पर नहीं लौट सकी है। पहले वनडे में केवल 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टाई खेलने वाली भारतीय टीम का स्पिन के विरुद्ध लचर प्रदर्शन दूसरे वनडे में भी जारी रहा। इस दौरान नौ बल्लेबाज केवल दो श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाजों वेंडर्से और असलंका के आगे चित हो गए। वैश्विक क्रिकेट में स्पिन के दिग्गज रहे मुथैया मुरलीधरन के देश का पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है, परंतु इस बार अपने घर पर स्पिन की मदद वाली पिच उनके गेंदबाजों को बहुत रास आ रही है। पहले मैच में भी स्पिनरों के कारण छोटे लक्ष्य का आधा-अधूरा बचाव करने वाली श्रीलंकाई टीम ने इस बार यह काम पूरा कर दिखाया है।

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (64) बल्लेबाजी में अकेले पूरी टीम का दायित्व उठा रहे हैं। लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जड़ने वाले कप्तान के अलावा सभी खिलाड़ी संघर्ष करते नजर आए हैं। पहले मैच के तरह ही इस बार भी पहला विकेट 98 रन पर गिरने के बावजूद केवल 110 रनों के भीतर शेष पूरी टीम आउट हो गई।

कोच गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि स्पिन को बढ़िया खेलने वाली टीम ने दोनों मैचों में इसके विरुद्ध बहुत संघर्ष किया है। रोहित के बाद एकमात्र अक्षर पटेल ने 44 रन और शुभमन गिल ने 35 रन बनाए।

स्कोर बोर्ड

श्रीलंका : 240/9 (50 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
निसांका का. राहुल बो. सिराज	00	01	0/0
फर्नांडो का. एंड बो. सुंदर	40	62	5/0
मेंडिस एलबीडब्ल्यू बो. सुंदर	30	42	3/0
समरविक्रमा का. कोहली बो. अक्षर	14	31	1/0
असलंका का. अक्षर बो. सुंदर	25	42	3/0
लियानगे का. एंड बो. कुलदीप	12	29	0/0
वेलालागे का. दुबे बो. कुलदीप	39	35	1/2
मेंडिस रन आउट	40	44	4/0
धनंजय रन आउट	15	13	2/0
वेंडर्से अविजित	01	01	0/0

अतिरिक्त: 24, कुल : 50 ओवर में नौ विकेट पर 240 रन, गेंदबाजी: सिराज 8-1-43-1, अर्शदीप 9-0-58-0, अक्षर 9-0-38-1, शिवम 2-0-10-0, सुंदर 10-1-30-3, कुलदीप 10-1-33-2, रोहित 2-0-11-0

भारत : 208 (42.2 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
रोहित का. निसांका बो. वेंडर्से	64	44	5/4
शुभमन का. मेंडिस बो. वेंडर्से	35	44	3/0
कोहली एलबीडब्ल्यू बो. वेंडर्से	14	19	2/0
दुबे एलबीडब्ल्यू बो. वेंडर्से	0	04	0/0
अक्षर का. बो. असलंका	44	44	4/2
श्रेयस एलबीडब्ल्यू बो. वेंडर्से	07	09	1/0
राहुल बो. वेंडर्से	0	02	0/0
सुंदर एलबीडब्ल्यू बो. असलंका	15	40	0/0
कुलदीप अविजित	07	27	0/0
सिराज एलबीडब्ल्यू बो. असलंका	04	18	0/0
अर्शदीप रनआउट	03	04	0/0

अतिरिक्त : 15, कुल: 42.2 ओवर में 208 पर आलआउट, गेंदबाजी: असिथा 7-0-31-0, वेलालागे 6-0-41-0, धनंजय 10-1-54-0, मेंडिस -3-0-19-0, वेंडर्से -10-0-33-6, असलंका 6.2-2-20-3

भारत के विरुद्ध स्पिनरों का शीर्ष प्रदर्शन (वनडे)

प्रदर्शन	खिलाड़ी	वर्ष
7/30	मुरलीधरन	2000
6/13	मेंडिस	2008
6/33	वेंडर्से	2024*
6/41	रिचर्ड्स	1989
6/54	धनंजय	2017

****

पावस गीत

राजेंद्र गौतम
मुंबई

बादल झुक आया है

अधसोई घाटी पर
आतुर-सा यायावर,
बादल झुक आया है।

गगन-गुफा में जाकर
अनहद में डूब गई,
अब थी, अब गायब है
शायद रस-बूंद हुई।
यों लगता है जैसे
धूप किसी कबिरा की
वेदांती माया है।

मुग्ध ग्रामिकाओं की
चल चितवन को हर्षा,
'गंभीरा' का जल पी
'वानीरों' को सरसा,
'अलका' के चिर उदास-
आंगन में फिर
मेघदूत आया है।

हवा चली खनकाती
लय-छंदों की पायल,
रेशमी फुहारों का
उड़-उड़ जाता आंचल
आषाढ़ी अंबर से
उतर आज धरती पर
'गीतपर्व' आया है।

rajendragautam99@yahoo.com

भाषा विमर्श

डा. बुद्धिनाथ मिश्र
देहरादून, उत्तराखंड

अथातो 'जाति' जिज्ञासा!

'जाति' शब्द अंग्रेजी के 'कास्ट' शब्द का पर्याय उसी तरह नहीं है, जैसे धर्म का पर्याय 'रिलीजन' और आत्मा का पर्याय 'सोल' नहीं है। हमारे यहां जातीयता संतरे की भांति भीतर से खंडित न होकर, राष्ट्रीय फल आम की तरह है, जिसके केंद्र में गुठली जैसा ठोस बीज है।

चित्र: जागरण आर्काइव

भारतीय जीवन-दर्शन के जिन आधारभूत शब्दों को सर्वाधिक हानि पहुंची है, उनमें धर्म, आश्रम, विग्रह, वर्ण और जाति सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनमें वर्ण और जाति सामाजिक वर्गीकरण से जुड़े शब्द हैं, पर दोनों के आधार अलग-अलग हैं।

हमारे यहां चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। वर्णों का आधार जन्म न होकर गुण और कर्म हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण-कर्म विभागशः अर्थात गुण और कर्म के आधार पर मैंने चार वर्णों की स्थापना की है। ईश्वर प्रत्येक कार्य किसी माध्यम से कराता है, इसलिए यहां 'मैंने' का अर्थ 'प्रकृति ने' मानना चाहिए।

गुण तीन होते हैं- सात्विक, राजसिक व तामसिक। प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण न्यूनाधिक होते हैं। एक ही परिवार में गुण की दृष्टि से सदस्यों का वर्ण पृथक हो सकता है। सबसे ज्वलंत उदाहरण पौलस्त्य वंश का है। रावण और कुंभकर्ण में तामसिक गुण अधिक थे तो विभीषण में सात्विक। लंका में राम के आने से पहले रावण का वर्चस्व था और आने के बाद विभीषण का। अंधकार या तामसिक गुण तो प्राकृत व सर्वव्यापी है, उसमें प्रकाश का विस्तार करना मनुष्य के देवत्व का सहज स्वभाव है। ऐसे व्यक्ति को ही ऊर्ध्वरिता कहा जाता है, जो अपने गुण और कर्म से वर्ण विभाजन की मेड़ों को तोड़ देता है।

'पुराण' कहते हैं कि दैत्य (राक्षस) और आदित्य (देव) एक ही कश्यप ऋषि की दो पत्नी दिति और अदिति से उत्पन्न हुए हैं। यह स्वाभाविक वर्ण व्यवस्था आज औद्योगिक समाज में भी है। ऊपर चेयरमैन है तो नीचे चपरासी। दोनों के गुण और कर्म भिन्न हैं।

मूलतः जन्म से संबंध रखने वाला 'जाति' शब्द अंग्रेजी के 'कास्ट' शब्द का पर्याय उसी तरह नहीं है, जैसे धर्म का पर्याय 'रिलीजन' और आत्मा का पर्याय 'सोल' नहीं है। अंग्रेजी पढ़कर आए लोग प्रायः जातीयता का अर्थ 'एथेनिक' से लेते हैं, जो गलत है। हमारे यहां जातीयता संतरे की भांति भीतर से खंडित न होकर राष्ट्रीय फल आम की तरह है, जिसके केंद्र में गुठली जैसा ठोस बीज है। 'जातीयता' शब्द उसी राष्ट्रीयता का पर्याय है, जिसमें वाग्देवी कहती हैं-अहं राष्ट्री संगमनी वसूनाम्(मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति और नागरिकों की मिलन-बिंदु हूं)।

'जाति' शब्द जन्म, वंश, गोत्र का द्योतक तो है ही, वर्ण-वंश-भाषा-देश-इतिहास-संस्कृति आदि की समानता रखने वाला मानव समुदाय अर्थात 'नेशन' भी है। यह हिंदुओं के विभिन्न वर्णों के अंतर्गत परस्पर रोटी-बेटी का संबंध रखने वाला और एक ही व्यवसाय करने वाला जन्मकृत जन समुदाय भी है। इसी अर्थ में समाज कहता भी है कि 'स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्' अर्थात उसी का जन्म लेना सार्थक है, जो अपने समुदाय के उत्कर्ष में योगदान करे। यह आकृति-स्वभाव-परंपरा आदि की समानता रखने वाला मानव समूह भी है, जैसे मंगोल जाति। इसीलिए जाति-धर्म का अर्थ जाति या वर्ण विशेष का आचार-विचार और व्यवसाय भी है। हमारे समाज में नाऊ, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, धोबी आदि शब्द इसी अर्थ में जाति हैं, क्योंकि प्रत्येक का व्यवसाय विरासत से चला आ रहा है।

संस्कृत में 'जाति-ब्राह्मण' उस ब्राह्मण को कहते हैं, जो केवल जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन गुण-धर्म या संस्कार से नहीं अर्थात तप-स्वाध्याय से रहित ब्राह्मण। शास्त्र कहता है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, 16 संस्कारों से गुजरने के बाद ही वह द्विज बनता है। द्विज अर्थात दो बार जन्म लेनेवाला। दूसरा जन्म उपनयन संस्कार होता है। वहीं शूद्र का अर्थ हम 'प्राकृत' या 'अनस्किल्ड' ले सकते हैं। आपने नवजात (नया जन्मा), सुजाता (अच्छे कुल में जन्मी), जातकर्म (चौथा संस्कार) और जातक (नवजात शिशु) शब्द भी सुने होंगे, लेकिन जातरूप (धतूरा) और जाया (पत्नी) शायद ही सुना हो। इसीलिए महाकवि कालिदास 'मेघदूत' में यक्ष की पत्नी के लिए 'कांता' (कश्चित् कांता-विरह-गुरुणा) और 'रघुवंश' में राजा दिलीप की पत्नी के लिए 'जाया' शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसे रघु को जन्म देना है- जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम्।

buddhinathji@gmail.com

वर्ग पहेली-2712

बाएं से दाएं
2 पानी भरने का घाट (4)। 4. लजाना, संकोच करना (3)। 5. प्रवाह, धारा (3)। 6. जल्दबाज, उतावला (5)। 9. भेंट, उपहार (4)। 11. लाश, जनाजा (2)। 12. आलम, दुनिया, संसार, विश्व (2)। 13. जोश में आना, आवेश में आना (4)। 15. गाली-गलौज करने वाला (5)। 17. भाग्य, किस्मत (3)। 20. अंटना, घुस जाना (3)। 21. ताजा, प्रफुल्ल (2,2)।

ऊपर से नीचे
1. बुरा, गुणहीन, बिगड़ा हुआ (3)। 2. बदलाव, हेर-फेर (5)। 3. गहरा (2)। 4. मद्य, मदिरा, मय (3)। 6. एक ही नाम का (4)। 7. घुमंतु, खानाबदोश को यह भी कहते हैं (4)। 8. धर्म (4)। 10. हर समय, सदा, हमेशा, सर्वदा (2,2)। 14. हाव-भाव, मोहक-चेष्टा (2,3)। 16. आर्थिक दंड (3)। 18. इस पार्टी का चुनाव चिह्न है हाथी (3)। 19. बिल्कुल ताजा और नया (2)।

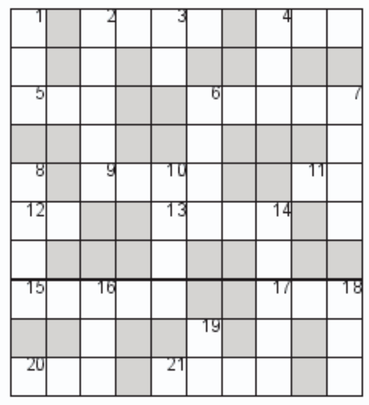

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

जागरण सुडोकू-2712

		5		2		4		8
2	1				3			5
		7	4		5		1	
8			3			5		7
	4	3			6		9	
9				7				4
4				3		1	8	
		9		1			4	
1			7		2			3

कल का हल

1	9	5	4	8	2	6	7	3
8	4	6	9	3	7	1	2	5
7	3	2	6	1	5	8	4	9
3	8	4	7	9	6	5	1	2
2	6	7	8	5	1	3	9	4
9	5	1	3	2	4	7	8	6
6	2	8	5	7	9	4	3	1
5	7	9	1	4	3	2	6	8
4	1	3	2	6	8	9	5	7

संगीतायन

शशिप्रभा तिवारी
दिल्ली

स्वरसिद्ध ठुमरी साम्राज्ञी

बनारस घराने की समृद्धि में योगदान करने वाली शास्त्रीय गायिका सिद्धेश्वरी देवी ने ठुमरी को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी आवाज में तैरती हुई पीड़ा ने उनके गायन को सिद्धि प्रदान की...

संगीत के समृद्ध बनारस घराने में विदुषी सिद्धेश्वरी देवी जैसी गायिका ने अपने शास्त्रीय गायन से सभी को चमत्कृत किया। ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी ने लगभग 50 वर्षों तक राजदरबारों, रेडियो और संगीत सम्मेलनों में गाया। हर मंच के अनुरूप उन्होंने स्वयं को ढाला। उनके समय के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज खां ने उन्हें 'ठुमरी रानी' का खिताब दिया था। उनकी पुत्री और प्रसिद्ध गायिका विदुषी सविता देवी ने बताया था कि एक बार मां मुंबई में संगीत सम्मेलन में गाने के लिए गई थीं। उनके बाद उस्ताद फैयाज खां साहब का गाना था। उस कार्यक्रम में मां ने राग पीलू में होरी 'काहे को डारे गुलाल' से गायन का समापन किया। तब फैयाज खां ने कहा कि तुम ही हो ठुमरी रानी। तुम्हारे बाद अब मैं नहीं गा सकता। उस शाम उन्होंने नहीं गाया। फिर, उसी समारोह में विदुषी केसरबाई केरकर से किसी ने ठुमरी गाने को कहा तो उन्होंने यह कहकर इन्कार कर दिया कि सिद्धेश्वरी जी की उपस्थिति में मैं ठुमरी गाने की हिम्मत नहीं कर सकती हूं।

भले ही सिद्धेश्वरी देवी खयाल अंग की ठुमरी गाने के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन ध्रुपद अंग में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। शास्त्रीय गायिका मीनाक्षी प्रसाद बताती हैं कि सिद्धेश्वरी जी ने राजा-महाराजाओं के दरबारों से गाना शुरू किया था। वह ठुमरी को खयाल की भांति विस्तार देते हुए गाती थीं, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने बोल-बनाव के साथ भावों को पेश करने की कला भी विकसित की। राग तिलंग पर आधारित उनकी ठुमरी 'सूरत मोरी काहे बिसराई राम' सुनकर मन भीतर तक भीग जाता है।

बचपन से ही सिद्धेश्वरी जी ने बहुत संघर्ष किया था। वह दर्द उनके व्यक्तित्व में समा गया था, जो उनकी आवाज से निकला। वर्ष 1965 में वह बनारस से दिल्ली आ गई थीं। सरोदवादक पं. विश्वजीत रायचौधरी बताते हैं कि जब भी मौका मिलता है, राग अड़ाना बहार में उनका गाया टप्पा 'ए नजर दौलत आई बहार' सुनता हूं। उनकी रागदारी, तानकारी में ठुमरी गायन अद्भुत है।

shashiprabha.tiwari@gmail.com

सिद्धेश्वरी देवी (8 अगस्त, 1908-18 मार्च, 1977)

खुली और बुलंद आवाज की इस गायिका ने घराने की गायन शैली की विशेषता अर्थात बंदिश के शब्दों के स्पष्ट उच्चारण पर जोर दिया। ठुमरी, कजरी, दादरा सभी के बोलों व भावों को स्वरों के माध्यम से सशक्त रूप से प्रकट किया। उनके स्वर में राग तिलक कामोद में दादरा 'झमाझम पानी भरे री', 'सूरत मोरी काहे बिसराई', मांझ-खमाज की ठुमरी 'जाओ बलम नहीं बोलो' व 'सांझ भई घर आवो' दादरा 'भीग जाऊं मैं पिया', राग गारा में दादरा 'यू गुइयां मोसे भरावे गगरिया' आदि सुनकर मन आज भी झूमने लगता है। उन्होंने स्वर-सिद्धियां प्राप्त की थीं, तभी तो वह ठुमरी रानी की उपाधि से समादृत हुई थीं।

पुस्तक परिचय

दिल्ली सल्तनत की कथा

पुस्तक: अग्निकाल
लेखक: युगल जोशी
प्रकाशक: पेंगुइन स्वदेश

इस उपन्यास की कहानी सल्तनत काल के सिपहसालार मलिक काफूर की है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने पारंपरिक शासक वर्ग और सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे विस्थापित किया और कैसे भारत पर विदेशी सभ्यता को थोपा गया, इसे कहानी में जाना जा सकता है। यह उपन्यास उस काल को मलिक काफूर के पात्र के माध्यम से पुनः जीवंत कर देता है। उस कालखंड के भारत की आहत मानवीय संवेदना का चित्रण यह उपन्यास करता है।

विवेक भटनागर

आज का भविष्यफल- 05 अगस्त, 2024 सोमवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: श्रावण मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। राहुकाल: प्रातः 07 बजकर 30 मिनट से 09 बजे तक। आज का दिशाशूल: पूर्व। पर्व एवं त्योहार: सोमवार व्रत
विशेष: बुध वक्री।

कल 06 अगस्त, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल: उत्तर
कल का पर्व एवं त्योहार: मंगलागौरी व्रत
विक्रम संवत 2081 शके 1946 दक्षिणायण, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया 19 घंटे 53 मिनट तक, तत्पश्चात तृतीया मघा नक्षत्र 17 घंटे 44 मिनट तक, तत्पश्चात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र वरियान योग 11 घंटे तक, तत्पश्चात परिघ योग, सिंह में चंद्रमा।

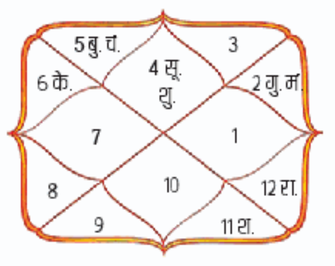

मेष: शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।
वृष: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। महिला से तनाव मिल सकता है।
मिथुन: व्यावसायिक सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
कर्क: पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।
सिंह: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।
कन्या: महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। सम्मान में वृद्धि होगी।
तुला: जीविका में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। दायित्व की पूर्ति होगी।
वृश्चिक: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अधिकारी का सहयोग मिलेगा।
धनु: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। सुखद समाचार मिलेगा।
मकर: योजना फलीभूत होगी। जीवनसाथी से तनाव मिल सकता है।
कुंभ: आर्थिक सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
मीन: शासनसत्ता का सहयोग मिलेगा। संतान के कारण चिंतित रहेंगे।

राष्ट्रीय फलक

अयोध्या में मंदिर के साथ रामनगरी के निर्माण का भी हुआ था भूमि पूजन

रघुवरशरण ● जागरण

- राम मंदिर के भूमि पूजन की चौथी वर्षगांठ पर विशेष
- अंतिम स्पर्श पा रहे भव्य मंदिर के साथ ढल रही श्रेष्ठतम सांस्कृतिक नगरी

अयोध्या: रामनगरी के क्षितिज पर पांच अगस्त, 2020 की तारीख मील के पत्थर की तरह है। इसी तिथि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। इस दिन यद्यपि घोषित तौर पर राममंदिर के लिए ही भूमि पूजन हुआ था, किंतु अघोषित तौर पर रामनगरी को श्रेष्ठतम सांस्कृतिक नगरी का स्वरूप देने के अभियान का भी आरंभ हो गया था। भूमि पूजन के बाद के चार वर्षों की यात्रा में जहां भव्य मंदिर अंतिम स्पर्श पा रहा है, वहीं रामनगरी श्रेष्ठतम सांस्कृतिक नगरी के रूप में उभर रही है। रामनगरी धार्मिक पर्यटन के शिखर की ओर उन्मुख है।

राम मंदिर परिकल्पना के अनुरूप भव्यता का पर्याय बनता जा रहा है। 360 फीट लंबे और 250 फीट चौड़े मंदिर का भूतल गत वर्ष निर्मित हुआ है और इसमें रामलला के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ आस्था का नित्य प्रतिमान गढ़ा जा रहा है। इसी वर्ष के अंत तक तीन तल, 392 स्तंभों, पांच उप शिखर और 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर से युक्त मंदिर निर्धारित मानचित्र के अनुरूप आकार ग्रहण कर चुका होगा। यह मात्र भव्य, सुदृढ़ और आकर्षक आकार में संयोजित शिलाओं का भव्य ढांचा ही नहीं है, बल्कि पराभूत अतीत का कलंक मिटा कर उस पर लिखी जा रही अस्मिता और कोटि-कोटि राम भक्तों की आस्था से जुड़ी असीम संभावना भी है। यह संभावना राम पथ से भी प्रशस्त होती है।

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हो रहा प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण कार्य। फाइल

इस पथ के माध्यम से न केवल रामनगरी का मुख्य आंतरिक मार्ग दो से तीन गुना तक चौड़ा और यातायात के आधुनिकतम मानकों से सज्जित हुआ है, बल्कि रामजन्मभूमि, पुण्य सलिला सरयू और कई अन्य प्रमुख स्थलों एवं मंदिरों के उन्नयन का परिचायक है। रामपथ का एक सिरा रामनगरी की जिस सीमा से शुरू होता है, वहां लता मंगेशकर चौक विकसित है। स्वर साम्राज्ञी की स्मृति जीवंत करने के साथ यहां से यह रामनगरी के शिखरगामी पर्यटन की व्यापकता का परिचायक प्रतीत होता है। इसी चौक पर लखनऊ-गोरखपुर हाइवे पर 400 मीटर लंबे धर्मपथ के दोनों ओर के सूर्य स्तंभ और मुहाने पर स्थापित भव्य सूर्य द्वार रामनगरी के पुराकालीन यशस्वी नरेशों का स्मरण कराता है। चित्रों और प्रतिमाओं के माध्यम से अभिव्यक्त श्रीराम की गाथा के साथ प्रवाहित 12 किलोमीटर की यात्रा का बोध तब और गहन होता है, जब बाईं ओर महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिखता है। यह राम मंदिर के साथ रामनगरी की स्वर्णिम संभावनाओं का सर्वाधिक प्रामाणिक साक्षी है।

कांवड़ यात्रा

पवित्र श्रावण मास में हैदराबाद स्थित चारमीनार के पास रविवार को कांवड़ यात्रा निकालते कांवड़िये। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। प्रेट्र

श्रद्धा का महासावन

प्रकृति के देव शिव शंकर की आराधना का मास

हमारी परंपरा में यूं तो सभी बारह मासों की अपनी अलग महत्ता है। सभी की अपनी उपादेयता है, फिर भी सावन की अपनी विशिष्ट महिमा है। इस मास में चतुर्दिक वृष्टि से धरती की प्यास बुझती है। शस्य श्यामला भूमि पर हरीतिमा व्याप्त हो जाती है। ग्रीष्म के भीष्म आतप से तप्त धरित्री नव हरित श्रृंगार किए अत्यंत मनोरम हो जाती है। धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नए धान्य के बीज अंकुरित होने लगते हैं। धरती शाक एवं फल-पुष्प से समृद्ध हो जाती है। चराचर जगत में नई ऊर्जा, नए उत्साह का उन्मेष होता है। वस्तुतः यह प्रकृति स्वरूप में मां पार्वती का श्रृंगार है। इसलिए सावन मास भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव औघड़दानी हैं। आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। एक लोटा जल, बेल पत्र और धतूर-मदार के पुष्प से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि साधक की समस्त मनो कामना पूरी कर देते हैं। सावन मास में सोमवार के व्रत का बड़ा महत्व है। यह मास अनेक उत्सवों का आकार है। इसी में भगवान शिव के अंग पर विराजित नागदेवता का पूजन नागपंचमी में किया जाता है। भगवान भूत भावन शिव के अंगभूषण स्वरूप नाग पूजन का विशेष महत्व है। इससे नाग भय दूर होता है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। काशी में भगवान विश्वनाथ स्वयं विराजते हैं।

स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी, पीठाधीश्वर, धर्मसंघ शिक्षा मंडल

अमरनाथ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक ने शंकराचार्य मंदिर में की पूजा-अर्चना

श्रीनगर में रविवार को अमरनाथ यात्रा के दौरान शंकराचार्य मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते मुख्य पुजारी महंत दीपेंद्र गिरि। एएनआइ

राज्य ब्यूरो, जागरण ● जम्मू

अमरनाथ यात्रा के लिए रविवार को श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक की पूजा-अर्चना की गई। परंपरा के अनुसार, श्रावण अमावस्या पर पूजा-अर्चना की जाती है। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर पहुंची, जहां दो घंटे तक चली पूजा-अर्चना में साधु-संतों ने शांति व खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सोमवार को शारिका भवन मंदिर हरि पर्वत में ले जाएगा और पूजा-अर्चना होगी। बाद में छड़ी मुबारक यात्रा के पारंपरिक मार्ग पहलगाम से पवित्र गुफा के लिए रवाना होगी। रक्षा बंधन वाले दिन छड़ी मुबारक के अंतिम दर्शन के साथ बाबा अमरनाथ की यात्रा संपन्न होगी।

अमावस्या महोत्सव

तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रविवार को आदि अमावस्या महोत्सव के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने तर्पण किया। प्रेट्र

कैलास यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं, गुंजी में बनेंगे ग्लास होम हट्स

नरेश कुमार ● जागरण

- केएमवीएन ने 2.80 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा प्रस्ताव
- आदि कैलास यात्रा के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं श्रद्धालु

नैनीताल: कैलास मानसरोवर और आदि कैलास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव गुंजी (पिथौरागढ़) में अब यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के बाद आदि कैलास यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने से सरकार ने क्षेत्र को सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। क्षेत्र में हेलीकाप्टर से और पैदल आने वाले यात्री अब हाईटेक ग्लास डोम हट्स में ठहरेंगे। कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) ने छह हट्स निर्माण को लेकर 2.80 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा है।

ऐतिहासिक कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए आधार शिविर धारचूला के बाद गुंजी प्रमुख पड़ाव है। यहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रियों को आगे रवाना किया जाता है। इधर, कोराना महामारी के बाद कैलास मानसरोवर यात्रा बंद है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस आदि कैलास यात्रा पर है। अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी के आदि कैलास यात्रा पर आने के बाद इस स्थान को प्रसिद्धी मिली है। जिससे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। केएमवीएन की ओर से संचालित यात्रा के पड़ाव गुंजी में यात्रियों के लिए हाईटेक सेवा उपलब्ध नहीं है। करीब एक दशक पूर्व बने इग्लू फाइबर हट्स और रेस्ट हाउस पुराने हो चुके है। केएमवीएन एमडी संदीप तिवारी ने बताया कि पर्यटन सचिव के निर्देश पर पुराने हट्स के स्थान पर नए हाईटेक ग्लास डोम हट्स बनाने का 2.80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन भेजा गया है।

नये हट्स के भीतर ही मिलेगी तमाम सुविधाएं: केएमवीएन एमडी संदीप तिवारी ने बताया कि पूर्व में गुंजी में फाइबर हट्स बनाए गए थे। नए ग्लास डोम हट्स को हाईटेक तरीके से डिजाइन किए गए हैं।

****

सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किए गए हस्ताक्षर

1963 में आज ही सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। परमाणु हथियारों के लगातार परीक्षण के कारण बढ़ते तनाव को देखते हुए यह संधि हुई थी। इसके तहत जमीन, पानी व अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगी।

अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट स्थापित की गई

1914 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका की सड़कों पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट स्थापित की गई थी। सड़क के किनारे के खंभों पर लगी इस ट्रैफिक लाइट पर केवल लाल और हरी बत्तियां थीं, जो सड़क के पास एक नियंत्रण बूथ के अंदर रखे मैन्युअल रूप से संचालित स्विच से जुड़ी थीं।

हिंदी के अग्रणी कवियों में गिने जाते हैं शिवमंगल सुमन

प्रसिद्ध कवि डा. शिवमंगल सिंह 'सुमन' का जन्म 1915 में आज ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। बीएचयू से हिंदी में शोधकार्य पूरा कर अध्यापन करने लगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, कालिदास अकादमी जैसी कई संस्थाओं से जुड़े। 1939 में पहला कविता संग्रह हिल्लोल प्रकाशित हुआ। मिट्टी की बारात संग्रह के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। जीवन के गान, प्रलय-सृजन, विंध्य हिमालय आदि उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। 1999 में उन्हें पद्मभूषण मिला।

20 वर्ष की मेहनत रंग लाई, ढूंढा नरमा के पत्ता मरोड़ रोग का तोड़

आशा मेहता ● जागरण

लुधियाना: अमेरिकन कपास (नरमा) की खेती अब किसानों के लिए अभिशाप नहीं रहेगी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के विज्ञानियों ने 20 वर्ष की अथक मेहनत से नरमा को लगने वाले काटन लीफ कर्ल रोग (सीएलसीयूडी) यानी पत्ता मरोड़ रोग का तोड़ निकाल लिया है। यह एक वायरल बीमारी है जोकि उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ-साथ पाकिस्तान में नरमा की फसल को बर्बाद करती रही है। विज्ञानियों का यह शोध कपास उत्पादक किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह संभव हुआ है फरीदकोट में पीएयू के क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन के प्रिंसिपल काटन ब्रीडर डा. पंकज राठौर, पीएयू लुधियाना के प्रिंसिपल काटन ब्रीडर डा. धरमिंदर पाठक, प्लांट ब्रीडर डा. हरीश कुमार, प्लांट पैथोलाजिस्ट डा. अशोक कुमार, सीनियर एंटोमोलाजिस्ट डा. सतनाम सिंह व डा. सुनीत पंधेर की संयुक्त रूप से कोशिशों के बाद। इन 20 वर्षों में विज्ञानियों ने कई सारे उतार व चढ़ाव झेले, लेकिन उन्होंने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया। इससे अब आगे चलकर सीएलसीयूडी रहित नरमा की किस्में तैयार करने का रास्ता खुल गया है।

पीएयू के विज्ञानियों की टीम ने नरमा की फसल को लगने वाले पत्ता मरोड़ रोग का तोड़ ढूंढा

नरमा की फसल में लगने वाले पत्ता मरोड़ रोग।

विज्ञानियों ने ऐसे पाई सफलता... : पीएयू के कुलपति डा. सतबीर सिंह गोसल ने विज्ञानियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए बताया कि पीएयू ऐसा करने वाला विश्व का पहला अनुसंधान संस्थान बन गया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास जंगली कपास की अलग-अलग प्रजातियों की किस्में हैं। उसी में से एक गासिपियम आर्मोरियनम एक ऐसी प्रजाति है, जो सीएलसीयूडी फैलाने वाले वायरस से लड़ने में सक्षम दिखी। हमने कपास की इस प्रजाति के पौधे को पेड़ की तरह बढ़ने दिया। इसमें वर्षों लग गए। हमने देखा कि जब कपास के पेड़ में यह बीमारी नहीं लगी, तो अगर इसके जीन को नरमा में क्रास करके ट्रांसफर कर दिया जाए, तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं। बस, फिर इस दिशा में शोध शुरू कर दी। इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया और हम सफल हुए।

100 से अधिक कंपनियों के साथ पीएयू करेगा एमओयू : पीएयू के वीसी डा. गोसल ने कहा कि यह हमारी बीस साल की इन्वेस्टमेंट है। ऐसे में अब हम कपास के बीज तैयार करने वाली कंपनियों के साथ एमओयू करेंगे। देश में करीब सौ से अधिक निजी कंपनियां काटन व बीटी काटन का बीज तैयार करती हैं। वह हमसे लाइनें लेकर बीमारी रहित बीटी काटन तैयार कर सकती हैं। गौर हो कि भारत, पाकिस्तान और चीन मिलकर दुनिया का लगभग आधा (49 प्रतिशत) कपास पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञानी वैरायटी बनाने के आसपास पहुंच चुके हैं। वैरायटी तैयार होने के बाद फिर फार्मर फील्ड पर ट्रायल होंगे।

क्या है पत्ता मरोड़ रोग? : डा. पंकज राठौर के मुताबिक अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं था। जब यह बीमारी फसल पर आती है, तो उसके पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप बीजकोषों के साथ पौधों का विकास रुक जाता है, जिससे उत्पादन पर फर्क पड़ता है। नई खोज से बीज ही ऐसे तैयार होंगे कि जिन पर यह बीमारी नहीं लग पाएगी।

डा. पंकज राठौर को रिटायरमेंट से पहले मिली सौगात : फरीदकोट स्थित पीएयू के क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन के पूर्व डायरेक्टर व प्रिंसिपल काटन ब्रीडर डा. पंकज राठौर की अहम भूमिका रही है। 59 वर्षीय डा. पंकज छह महीने बाद रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने पूरा जीवन इस शोध के लिए समर्पित कर दिया।

थाइलैंड में वार्षिक उत्सव का आयोजन

थाइलैंड के चोनबुरी प्रांत में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी रविवार को वार्षिक भैंस दौड़ उत्सव का आयोजन किया गया। विंग क्वाइ के नाम से भी प्रसिद्ध यह उत्सव चोनबुरी प्रांत का सबसे रोमांचक कार्यक्रम है। यह उत्सव थाइलैंड की कृषि जीवन शैली के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को एकत्रित होने, रोमांचक प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करने और स्वादिष्ट, स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने का मौका मिलता है। रायटर

इधर-उधर की

आर्ट गैलरी में घुसा पालतू अजगर, हैंडबैग आया पसंद

अपने मालिक की नजर बचा कर गैलरी में घुसा बोधी। इंटरनेट मीडिया

लंदन, एजेंसी: स्काटलैंड में एक पालतू अजगर ने एक आर्ट गैलरी में घुस कर चीजों को अस्त- व्यस्त कर दिया। हालांकि बाद में अजगर को उसके मालिक तक पहुंचाया गया। एबरडीनशायर के बैंचोरी में स्टूडियो 1 स्टोर और गैलरी के ऊपर रहने वाले मार्टिन वोल्स्की ने कहा कि उनके 10 फीट के अजगर बोधी ने नीचे जाने के लिए एक छोटे छेद का इस्तेमाल किया। स्टूडियो 1 की मालकिन विव केरिज ने कहा कि 5 वर्षीय बोधी ने काफी गड़बड़ कर दी। विव केरिज ने बताया कि फर्श पर ऊंची अलमारियों की कुछ चीजें बिखरी हुई थीं। बोधी को एक हैंडबैग पसंद आया।

स्तन व ओवरियन कैंसर के जीन म्यूटेशन से प्रभावित होती है महिलाओं में प्रजनन क्षमता

शोधा ▸ प्रजनन योग्य आयु वाले चूहों में अंडे की परिपक्वता दर में भी 45 प्रतिशत की कमी आई

इस बारे में ई-बायोमेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन से पता चला

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, आइएएनएस : शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाती हैं, जो कैंसर का कारण बनती हैं। प्रीक्लिनिकल माडल और मानव ऊतकों के नमूनों में किए गए शोध के अनुसार, बराक1 (बीआरसीए1) जीन म्यूटेशन वाली महिलाओं में प्रजनन क्षमता कम होने का खतरा बहुत अधिक हो सकता है, जो स्तन और ओवरियन (डिम्बग्रंथि) के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। बराक1 (बीआरसीए1) और बराक2 (बीआरसीए2) जीन स्तन और ओवरियन कैंसर से सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी जीन के म्यूटेशन से कैंसर विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। ओवेरियन कैंसर भारतीय महिलाओं में तीसरा और दुनिया भर में आठवां सबसे आम कैंसर है। ग्लोबोकैन 2018 फैक्ट शीट के अनुसार, सभी कैंसर के मामलों के 3.44 प्रतिशत है। ओवेरियन कैंसर तब होता है जब आपके अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब में असामान्य कोशिकाएं बढ़ती हैं और नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं. यह अंडाशय (ओवरी) से शुरू होता है। ओवेरियन कैंसर का पता लगाना कभी-कभी मुश्किल होता है क्योंकि इसके लक्षण अक्सर जल्दी नजर नहीं आते।

आस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि खासकर बढ़ती उम्र के साथ बराक1 जीन के बिना चूहों में अंडे का आकार और गुणवत्ता कम हो गई थी। बराक1 की कमी वाले प्रजनन योग्य आयु वाले चूहों में अंडे की परिपक्वता दर में भी 45 प्रतिशत की कमी आई। महिलाओं में रक्त में एंटी मुलरियन हार्मोन (एएमएच के स्तर को मापना उनके अंडों की संख्या का स्वर्ण मानक अप्रत्यक्ष मार्कर माना जाता है।

हालांकि, बीआरसीए म्यूटेशन वाली कुछ महिलाओं के ओवरियन के ऊतकों से एएमएच स्तर और अनुमानित अंडे की संख्या ने इन उपायों के बीच कोई संबंध नहीं दिखाया। यह ई-बायोमेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन से पता चला। निष्कर्षों ने यह समझने के लिए और अधिक अध्ययनों की आवश्यकता पर बल दिया कि क्या बीआरसीए म्यूटेशन वाली महिलाओं में एएमएच के अंडे की संख्या का एक अच्छा भविष्यवक्ता माना जाता है, क्योंकि इसका निहितार्थ बीआरसीए म्यूटेशन वाली महिलाओं के लिए है। विश्वविद्यालय की हट प्रयोगशाला की एमी विनशिप ने कहा कि यह रिजल्ट म्यूटेशन वाली महिलाओं को परिवार नियोजन और संभवतः प्रजनन संरक्षण के निर्णय लेने में परिणाम में मदद करते हैं जैसे अंडे को फ्रीज करना। विनशिप ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बराक1 ले जाने वाली महिलाओं को पहले से ही स्तन और ओवरियन कैंसर के विकास का बड़ा खतरा होता है। आगे के कैंसर का इलाज महिलाओं के प्रजनन स्तर को खराब कर सकते हैं।

बच्चों में घातक ब्रेन ट्यूमर के लिए अग्नाशय के कैंसर की दवा कारगर

अनुसंधान

अग्नाशय कैंसर के इलाज के लिए विकसित की गई एक दवा मेडुलोब्लास्टोमा बच्चों में होने वाले सबसे घातक ब्रेन ट्यूमर में सबसे कारगर साबित हुई।

जर्नल आफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि ट्रिप्टोलाइड दवा, जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा में इस्तेमाल की जाने वाली एक अंगूर की लता से निकाली जाती है। यह पानी में घुलनशील प्रोड्रग संस्करण मिनेलाइड है। यह विषाक्तता के लक्षण दिखाए बिना प्रीक्लिनिकल मेडुलोब्लास्टोमा माडल में जीवन दर को बढ़ाने में कारगर है। प्रोड्रग एक निष्क्रिय दवा है, जो शरीर में एंजाइमेटिक या रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सक्रिय दवा में बदल देता है। मेडुलोब्लास्टोमा की जीवित रहने की दर निर्भर करती है कि मरीज़ में चार उपप्रकारों में से कौन सा है, लेकिन सबसे खराब जीवित रहने की दर ऐतिहासिक रूप से लगभग 40 प्रतिशत है जो समूह 3 के लिए है। यह शोध समूह 3 पर केंद्रित था। मेडिकल यूनिवर्सिटी आफ साउथ कैरोलिना में सहायक प्रोफेसर जेजाबेल रोड्रिगेज ब्लैंको के शोध ने इस पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें ट्रिप्टोलाइड की एमवाइसी को निशाना बनाने की क्षमता की खोज की जो आंकोजीन या जीन में कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। एमवाइसी लगभग 70 प्रतिशत कैंसर में अव्यवस्थित या नियंत्रण से बाहर होता है। ट्यूमर में एमवाइसी की जितनी अधिक प्रतियां होती हैं, ट्रिप्टोलाइड उतना बेहतर काम करता है। एमवाइसी की प्रतियों वाले समूह ट्यूमर में प्रभावकारिता 100 गुना अधिक होती है।

(आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

तमन्ना बोलीं, 'वेदा' एक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा है

'वेदा' और 'स्त्री 2' दोनों में नजर आएंगी तमन्ना। इस्टाग्राम (@tamannaahspeaks)

यूं तो कलाकार हर जानर की कहानियों हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन कई बार न चाहते हुए भी उनकी एक खास किस्म की छवि बन जाती है। कई एक्शन फिल्में करने के कारण अभिनेता जान अब्राहम की भी एक्शन अभिनेता की छवि बन चुकी है। हाल ही में मुंबई में उनकी आगामी फिल्म वेदा की ट्रेलर जारी किया गया, जान से लगातार एक ही तरह की एक्शन फिल्में करने पर सवाल पूछा गया। जान ने जवाब तो दिया, लेकिन उन्हें यह बुरा भी लगा। अब उनके बचाव में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया उतरी हैं। तमन्ना वेदा में सहायक भूमिका में हैं। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर साझा करते हुए एक्स पर लिखा, 'वेदा को इसके कवर से मत जज करो। भरोसा रखो, जब मैं ऐसा कह रही हूं, तो यह फिल्म एक्शन से कहीं ज्यादा है। देश के सबसे पसंदीदा एक्शन हीरोज में से एक मेरे दोस्त जान अब्राहम अविश्वसनीय छाप एक ऐसे जानर में ला रहे हैं, जिसमें वे पूरी तरह माहिर हैं। इस बार, वे एक्शन के जरिए एक अलग तरह की कहानी कह रहे हैं, यह दिखाते हुए कि यह जानर आज के समय में कितनी सार्थक सिनेमाई अनुभव व्यक्त कर सकता है।' तमन्ना ने निर्देशन में फिर से वापसी कर रहे निखिल आडवाणी की भी प्रशंसा की। 15 अगस्त को स्त्री 2 में जहां उनका आइटम सांग हैं, वही वेदा में भी वह सहायक भूमिका में हैं।

पंजाब से स्काटलैंड तक जाएगी 'सन आफ सरदार 2' की कहानी

हिंदी सिनेमा के सिंघम अभिनेता अजय देवगन लगातार फ्रैंचाइजी फिल्में कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्मों की कतार में सिंघम अगेन, गोलमाल 5, दे दे प्यार दे 2, दृश्यम 3 जैसी फिल्में शामिल हैं। इसी कड़ी में वह साल 2012 में प्रदर्शित फिल्म सन आफ सरदार की सीक्वल सन आफ सरदार 2 भी कर रहे हैं। मूल फिल्म की कहानी में फिल्म का नायक जसविंदर सिंह रंधावा अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने लंदन से फगवाड़ा आता है। पूरी फिल्म की कहानी पंजाब में ही दिखाई गई थी। वहीं सन आफ सरदार 2 की कहानी विदेश भी जाएगी। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सन आफ सरदार 2 की कहानी पंजाब के साथ-साथ स्काटलैंड और लंदन भी जाएगी। लंदन और स्काटलैंड के हिस्सों को दोनों शहरों के वास्तविक लोकेशन पर शूट किया जाएगा। स्काटलैंड शेड्यूल के लिए फिल्म की टीम स्काटलैंड पहुंच चुकी है, टीम ने वहां शूटिंग भी शुरू कर दी है। निर्देशक विजय कुमार अरोड़ा ने बीस दिनों का स्काटलैंड शेड्यूल तय किया है। मूल फिल्म की तरह सन आफ सरदार 2 में भी अजय और संजय दत्त के बीच टकराव दिखेगा, हालांकि सीक्वल में अभिनेत्री मृणाल ठाकुर को जगह मिली है।

सन आफ सरदार 2 में फिर से मुख्य भूमिका में होंगे अजय। फाइल

मेघना गुलजार की फिल्म से अलग हुए आयुष्मान खुराना

फिल्म की आधिकारिक घोषणा होने से पहले उसके कलाकारों की कास्टिंग को लेकर खबरें आती रहती हैं। बीते दिनों आई खबरों में कहा गया था कि 'ड्रीम गर्ल' अभिनेता आयुष्मान खुराना मेघना गुलजार की अगली फिल्म (जिसका शीर्षक फिलहाल दायरा है) का हिस्सा होंगे। उसमें उनके साथ करीना कपूर स्क्रीन साझा करने वाली थीं। अब खबरें हैं कि आयुष्मान फिल्म से अलग हो गए हैं। बता दें कि यह फिल्म एक क्राइम थ्रिलर है और हैदराबाद में हुए दुष्कर्म मामले पर आधारित है। वैसे, अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं किया गया है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि इस साल के अंत तक इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आयुष्मान इस साल की दूसरी छमाही में व्यस्त शेड्यूल के कारण मेघना की फिल्म करने के लिए तारीख नहीं निकाल पाए हैं। फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत में आरंभ होनी है और यह आयुष्मान के अमेरिकी म्यूजिक टूर से टकराएगी। इसलिए वह फिल्म से अलग हो गए हैं। साथ ही, बार्डर 2 के अलावा उनके पास दो और फिल्में भी हैं। फिलहाल सभी प्रोजेक्ट्स के लिए तारीखों पर बातचीत चल रही है, लेकिन मेघना की फिल्म उनकी सूची में नहीं है। मेघना उनकी जगह अब दूसरे कलाकार के बारे में विचार कर रही हैं।

बार्डर 2 में नजर आएंगे आयुष्मान। फाइल

शूटिंग खत्म करने के लिए कार्तिक ने किया ओवरटाइम

इसके बाद अनुराग बासु की फिल्म शूट करेंगे कार्तिक। इंस्टाग्राम (@kartikaaryan)

फिल्म निर्माण में होने वाली हर पल की देरी निर्माताओं को कंधों पर अतिरिक्त खर्चे का बोझ बनती जाती है। अभिनेता कार्तिक आर्यन इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और इसका ध्यान भी रखते हैं कि उनके निर्माताओं को उनसे वक्त को लेकर कोई शिकायत न करें। करीब 40 दिनों तक चले अंतिम शेड्यूल की शूटिंग के बाद उन्होंने जुलाई में फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग को पूर्ण विराम दे दिया है। फिल्म के करीबी सूत्रों के अनुसार, फिल्म के निर्देशक अनीस बज्मी और निर्माता भूषण कुमार चाहते थे कि जुलाई के अंत तक फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाए। जिससे अगस्त के अंत तक फिल्म का पहला टीजर जारी किया जा सके और मार्केटिंग पर भी काम शुरू किया जा सके। कार्तिक ने भी ओवरटाइम करते हुए तय समय सीमा में ही शूटिंग खत्म कर ली। उनके करीबियों के अनुसार, इसके लिए कई बार उन्हें दिन के 15-20 घंटे शूटिंग सेट पर रहना पड़ा था। फिल्म के अंतिम शेड्यूल को मध्य प्रदेश के ओरछा के साथ-साथ मुंबई में फिल्माया गया। अंतिम दो सप्ताह की शूटिंग के लिए मुंबई में करीब 11 अलग-अलग सेट स्थापित किए किए थे। जिसे प्रोडक्शन डिजाइनर रजत पोद्दार ने डिजाइन किया था। इनमें राजा, रूह बाबा और मंजुलिका के कमरों के साथ-साथ हवेली का सेट भी था। फिल्म के मुख्य हिस्सों की शूटिंग खत्म हो चुकी है। यह फिल्म दीवाली पर रिलीज होगी।

मैं भीड़ का हिस्सा कभी नहीं रहा

सात सवाल

इन दिनों भाषाई बंदिशों को तोड़ते हुए कई कलाकार अलग-अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साउथ में चुंनिदा फिल्में करने के बाद अभिनेता मनोज बाजपेयी ने उससे दूरी बना ली। हाल ही में उनकी सौंवी फिल्म भैयाजी जी5 पर रिलीज हुई। फिलहाल वह वेब सीरीज फैमिलीमैन 3 की शूटिंग कर रहे हैं। मनोज ने साउथ सिनेमा से दूरी, दोस्ती, रील बनाने के चलन जैसे मुद्दों पर बात की :

● आपका नाम अभिनेता मनोज कुमार के नाम पर रखा गया था...

-उनकी पुरानी फिल्में थिएटर में लगती थीं, तो माता-पिता देखने के लिए साथ ले जाते थे। मैं उनका मुरीद तब हुआ, जब उनके निर्देशन में बनी फिल्म उपकार, रोटी कपड़ा मकान, शोर और क्रांति देखी। उसके कारण मैंने मनोज जी के कई पहलू देखे। वह कमाल के एक्टर, लेखक, गीतकार, निर्देशक रहे हैं। मैं जब उनसे मिला था, तो उन्हें बताया कि मेरा नाम आपके नाम पर रखा गया है। उन्होंने आशीर्वाद दिया था।

● गोविंद निहलानी की फिल्म द्रोहकाल में आपने एक मिनट का रोल किया था...

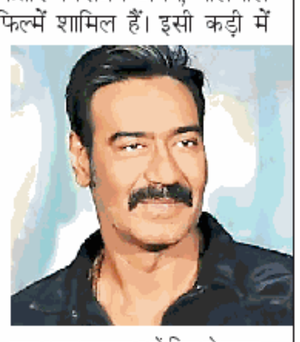

-जब मैं उनके पास पहुंचा, तब तक उनके पास सारे रोल बंट चुके थे। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, एक मिनट का रोल बचा है, जो मैं देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तुम बैंडिट क्वीन फिल्म करके आए हो। मैंने कहा मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे काम की सख्त जरूरत है। उससे दो-तीन हजार रुपये जो भी मिलते, उससे मेरा किराया चला जाता, पेट में कुछ खाना चला जाता।

● भैयाजी में आपको बहुत सारा एक्शन करने का मौका मिला। करियर के शुरुआती दौर में एक्शन का मौका न मिलने का मलाल रहा?

-किसी चीज का मलाल क्यों रखना। मैंने तो वही काम किया, जो मैं करना चाहता था। जहां तक बात है भैयाजी करने की, तो निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की ऐसी फिल्म करना चाहते थे, जिसे देखकर वह बड़े हुए हैं। नैनीताल के हल्दवानी में डब तेलुगु फिल्में उन्होंने देखी थीं। उस तरीके की फिल्म वह बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझसे सपोर्ट मांगा। मैंने अपनी जीजान लगा दी,उसे बनाने में। उसका सपना पूरा हुआ, मुझे इस बात की खुशी है।

● आजकल पैन इंडिया फिल्में बन रहीं हैं। आप इसे कैसे देखते हैं?

-कुछ नहीं, मीडिया में लिखने और प्रमोशन करने के लिए मेकर्स फिल्म को एक नाम दे देते हैं पैन इंडिया। अमिताभ बच्चन जब फिल्में किया करते थे, तो उन्हें देश-विदेश में लोग देखा करते थे। मिथुन चक्रवर्ती साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, राज कपूर साहब को पूरे हिंदुस्तान में लोग पसंद करते थे। वह भी पैन इंडिया थे। यह सब बिना मतलब की बातें हैं। तेलुगु, तमिल सिनेमा को महामारी के बाद लगना शुरू हुआ कि जिस तरीके की फिल्में वह बना रहे हैं, उस तरह के सिनेमा का इंतजार दर्शक हर जगह कर रहे हैं। जब मार्केट बढ़ता है, तो लोग नए-नए तरीके ढूंढते हैं।

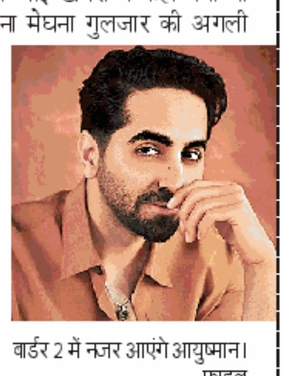

● आपने भी दक्षिण भारतीय फिल्में की थी, फिर दूरी बना ली?

-अल्लू अर्जुन के साथ दो फिल्में हैप्पी और वेदम की थी, दोनों को सराहा गया था। हैप्पी में मैंने कामेडी किरदार किया था, जो प्रसिद्ध हुआ था। वेदम में गंभीर रोल था। उससे लोग बहुत प्रभावित हुए थे। फिर पवन कल्याण के साथ फिल्म पुली किया था, वह उतनी चली नहीं थी।

● इंडस्ट्री में कितने दोस्त बना पाए हैं? कभी धोखा मिला?

-स्कूल, कालेज और थिएटर के दोस्त आज भी हैं। यह अलग बात है कि उनसे रोज बात नहीं हो पाती है। नीरज पांडे के साथ निर्देशक और एक्टर का रिश्ता नहीं रहा। दोस्ती से भी आगे जा चुका है। केके मेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती में धोखा मुझे नहीं मिला है।

(स्मिता श्रीवास्तव)

रील का जमाना है, लेकिन आप अपने इंटरनेट मीडिया पेज पर केवल फिल्म का प्रमोशन या एकाध फोटो पोस्ट कर देते हैं...

मैं भीड़ का हिस्सा कभी नहीं रहा। वह काम ही नहीं किया, जो सब कर रहे हैं। जो काम मुझे अच्छा लगता है, दिल को छूता है, वही करता हूं। बदलते समय के अनुसार चीजों को स्वीकार करना चाहिए। मैं स्वीकारता हूं कि यह चल रहा है, पर मैं इस पर अपना कोई जजमेंट इसलिए नहीं देता हूं, क्योंकि यह समय अलग है। मैं सिर्फ देख रहा हूं ताकि अपने भीतर के एक्टर को इस समय के साथ रख सकूं।

फैमिली मैन 3 की शूटिंग शुरू कर चुके हैं मनोज ● जागरण आर्काइव

टिकट खिड़की पर फीकी रही अगस्त की शुरुआत

उलझ फिल्म में जाह्नवी ने निभाई है मुख्य भूमिका ● मिडडे आर्काइव

टिकट खिड़की पर प्रदर्शन के लिहाज से अगस्त की शुरुआत भी काफी ठंडी हुई है। गत शुक्रवार को अजय देवगन अभिनीत औरों में कहां दम था और जाह्नवी कपूर अभिनीत उलझ प्रदर्शित हुई। दोनों ही फिल्मों के प्रति सिनेप्रेमियों में कुछ खास उत्साह नहीं दिखा। नीरज पांडे निर्देशित औरों में कहां दम था को शुक्रवार को सिर्फ 1.7 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली। अजय के साथ तब्बू, सई मांजरेकर और शांतनु माहेश्वरी अभिनीत औरों में कहां दम था को देशभर में करीब 2,500 स्क्रीन्स पर जगह मिली। दूसरे दिन शनिवार को मामूली बढ़त के साथ फिल्म की कमाई 1.9 करोड़ रुपये रही। इस तरह प्रदर्शित होने के पहले दो दिनों में फिल्म ने 3.6 करोड़ रुपये की कमाई की। उलझ को करीब 750 स्क्रीन पर जगह मिली। जाह्नवी के साथ गुलशन देवैया और रोशन मैथ्यूज अभिनीत इस फिल्म को शुक्रवार को सिर्फ एक करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली। दूसरे दिन शनिवार को करीब 70 प्रतिशत बढ़त के साथ फिल्म की कमाई 1.7 करोड़ रुपये रही। इस तरह प्रदर्शित होने के पहले दो दिनों में फिल्म ने कुल 2.7 करोड़ रुपये कमाए। अब टिकट खिड़की की नजरें 15 अगस्त को प्रदर्शित हो रही फिल्मों खेल खेल में, वेदा और स्त्री 2 के टकराव पर होंगी।

****